जीके टोर्नेडो ESIC और केनरा बैंक पीओ मेंस 2018

परीक्षा के लिए - बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता

Powered by :

gradeup

बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता टोरनाडो

ESIC SSO और Canara Bank PO 2018 परीक्षा के लिए

प्रिय पाठक,

यह टोर्नेडो महत्वपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय समाचारों और घटनाओं की एक पूरी डॉकेट है जो पिछले 7 महीनों में हुई थी (**1 मई 2018- 12 दिसम्बर 2018**)। बैंकिंग और बीमा परीक्षा जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टोर्नेडो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है।

आरबीआई से संबंधित समाचार

दिसम्बर

1. शक्तिकांत दास को आर.बी.आई. के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया

- शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर के रूप में तीन वर्षों के लिए पदभार संभाला।
- वह उर्जित पटेल का स्थान लेंगे जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया।

शक्तिकांत दास के बारे में

- शक्तिकांत दास ओडिशा के पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी हैं। वह 1980 के बैच आई.ए.एस. अधिकारी तमिलनाडु केडर से हैं।
- जब विमुद्रीकरण की घोषणा की गई तब वह आर्थिक मामलों के सचिव थे। वह अगस्त 2015 से मई 2017 तक इस पद पर सेवारत थे।
- शक्तिकांत दास विमुद्रीकरण के स्पष्टवादी समर्थक रहे हैं।
- वह लगभग पांच वर्षों में केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने वाले पहले नौकरशाह (आई.ए.एस.) होंगे।
- वह पहले भारत की पंद्रहवीं वित्त आयोग और जी20 में भारत के शेरपा सदस्य रह चुके हैं।

2. उर्जित पटेल ने आर.बी.आई. के गवर्नर से इस्तीफा दिया

- उर्जित पटेल ने अपने तीन साल के कार्यकाल के पूरा होने से नौ महीने पहले 10 दिसंबर 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया।
- उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया।
- आजादी के बाद यह दूसरी बार है कि आर.बी.आई. के कार्यकारी गवर्नर ने इस्तीफा दिया।
- ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति सर बेनेगल राम राउ थे, जिन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ मतभेदों के कारण अपने दूसरे विस्तारित कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया था।

नोट:

- उन्हें 4 सितंबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के 24वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया।

3. आर.बी.आई. ने इंडियन बैंक पर 1 करोड़ रूपये जुर्माना लगाया

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर परिपत्र के उल्लंघन के लिए इंडियन बैंक पर 1 करोड़ रूपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
- सेंट्रल बैंक ने एक कथन में कहा है कि आर.बी.आई. द्वारा जारी उपरोक्त दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए यह जुर्माना लगाया गया है।

4. आर.बी.आई. के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन सालों में हर दिन 3 बैंक लूटे जाते हैं

- आर.बी.आई. के आंकड़ों के मुताबिक, हर दिन लगभग तीन बैंक पिछले तीन सालों और तीन महीनों (2015-16 से जून 2018 तक) में लूटे गए थे।
- इस अवधि के दौरान विभिन्न बैंकों से 168.72 करोड़ रूपये लूटे गए हैं।
- इस अवधि के दौरान बैंकों द्वारा लूट, डकैती, चोरी और धमकी के 3,167 मामलों में से 10 प्रतिशत बिहार से

रिपोर्ट किए गए थे, इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक से 9 प्रतिशत मामले थे।

- पंजाब के साथ 7 प्रतिशत मामले और राजस्थान में 6 फीसदी की रिपोर्टिंग के साथ, इन छह राज्यों में कुल मामलों में 50 प्रतिशत का योगदान है।
- हालांकि, जब चोरी की गई राशि की बात आती है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में बैंकों से 87.21 करोड़ (51 प्रतिशत) चोरी हो गई थी।
- इसी अवधि के दौरान, ए.टी.एम. और डेबिट कार्ड से संबंधित 2,468 धोखाधड़ी, जिसमें 111.71 करोड़ रूपये शामिल थे, की सूचना मिली थी।

5. आर.बी.आई. ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा

- 6 दिसंबर 2018 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2018-19 के लिए अपनी चौथी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में, रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा।
- रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जी.डी.पी. विकास अनुमान 7.4 प्रतिशत पर बनाए रखा।
- 2019-20 की पहली छमाही के लिए जी.डी.पी. का अनुमान 7.5 प्रतिशत रहा है।
- आर.बी.आई. ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दूसरे छमाही में मुद्रास्फीति का अनुमान 2.7-3.2 प्रतिशत है।
- एम.पी.सी. की अगली बैठक 5-7 फरवरी, 2019 से निर्धारित है।

मौजूदी दर इस प्रकार है:

1. रेपा रेट	6.50% (परिवर्तित)
2. रिवर्स रेपो रेट	6.25% (परिवर्तित)
3. सी.आर.आर (नकद निधि अनुपात)	4.00% (अपरिवर्तित)
4.सी.एल.आर. (वैधानिक तरलता अनुपात)	19.50% (अपरिवर्तित)
5. एम.एस.एफ. (सीमांत स्थायी सुविधा)	6.75% (परिवर्तित)
6. बैंक दर	6.75% (परिवर्तित)

याद रखने के लिए बिंदु:

➢ **रेपो दर:**

- यह एक दर है, जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ पैसा उधार देता है।
- यह एक दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक से पैसा उधर लेते हैं।

➢ **रिवर्स रेपो दर:**

- यह एक दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को पैसे उधार देते हैं।
- यह एक दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेती है।

➢ **सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर:**

- यह दर है जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ आरबीआई से रात भर धन उधार ले सकते हैं।
- यह अनुसूचित बैंकों के लिए बहुत ही अल्पकालिक उधार योजना है।

➢ **बैंक दर:**

- बैंक दर एक दर है जिस पर किसी देश के सेंट्रल बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋणों को बढ़ाता है।
- बैंक दर को प्रबंधित करना एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं।
- लोअर बैंक दर में उधारकर्ताओं के लिए धन की लागत को कम करके अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में मदद मिल सकती है, और उच्च बैंक दरें अर्थव्यवस्था में राज में मदद करती हैं जब मुद्रास्फीति वांछित से अधिक होती है
- रेपो दर एक अल्पकालिक उपाय है और बैंक दर एक दीर्घकालिक उपाय है।

- **नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर):**
  - यह बैंक के कुल फंड के अनुपात का अनुपात है जिसे बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है।
  - सिस्टम से अत्यधिक पैसा निकालने के लिए आरबीआई सीआरआर का इस्तेमाल करता है।
- **सांविधिक चलन अनुपात (एसएलआर):**
  - यह राशि का एक अनुपात है जो बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के नकदी, सोना और बेहिचक प्रतिभूतियों, खजाना बिल, दिनांकित प्रतिभूतियों आदि जैसे रूपों की एक निर्धारित अनुपात बनाए रखना है।

नवम्बर

1. **भारतीय रिजर्व बैंक ने ई.सी.बी. के लिए मौजूदा प्रतिरक्षा नियमों को 100% से 70% तक आसान बनाया**
   - भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) के लिए अनिवार्य प्रतिरक्षा नियमों को मौजूदा 100% से 70% तक कम करके मानदंडों को आसान बनाया।
   - अधिसूचना के अनुसार, निश्चित मानदंड ई.सी.बी. के लिए परिपक्वता अवधि के साथ 3 से 5 साल के बीच लागू होंगे।

नोट:

- अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी से गैर-बैंकिंग कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तब आर.बी.आई. प्रतिरक्षा नियमों को आसान बना देता है।
- आर.बी.आई. ने ई.सी.बी. मार्ग के माध्यम से पांच साल से तीन साल तक उधार लेने के लिए न्यूनतम कार्यकाल पहले ही घटा दिया है।
- आर.बी.आई. ने 10 साल से अनिवार्य प्रतिरक्षा से पांच साल तक छूट के लिए आवश्यक कार्यकाल भी कम कर दिया है।
- आर.बी.आई. के अनुसार, ट्रैक I मध्यम अवधि की विदेशी मुद्रा-वर्णन ई.सी.बी. को संदर्भित करता है जिसमें न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 3-5 साल होती है।

प्रतिपक्षा के बारे में

- प्रतिरक्षा प्रतिकूल मूल्य या मुद्रा स्थानांतरण के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक एक निवेश प्रक्रिया है।
- एक उधारकर्ता को इस तरह से बचाव करना होता है कि अनुमानित नकद प्रवाह विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के बावजूद उधारकर्ताओं की अपेक्षा से मेल खा सके।

2. **अप्रैल, 2020 से बैंकों के लिए कुल स्थिर निधि अनुपात नियम: आरबीआई**
   - आर.बी.आई. के अनुसार, एन.एस.एफ.आर. नियम जो बैंकों को अपनी संपत्ति और अव्यवस्थित (ऑफ-बैलेंस) शीट गतिविधियों की संरचना के संबंध में एक स्थिर निधि प्रोफ़ाइल बनाए रखने के लिए जरूरी है, यह नियम अप्रैल 2020 से परिचालित होंगे।
   - एन.एस.एफ.आर. को आवश्यक स्थिर निधि की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधि की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।
   - एन.एस.एफ.आर. अकेले और समेकित स्तर पर भारतीय बैंकों के लिए लागू होगा।
   - दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि भारत में शाखाओं के रूप में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों के लिए संरचना स्वचलित आधार पर लागू होगी (केवल भारतीय परिचालनों के लिए)।
   - दिशानिर्देशों के मुताबिक, रिजर्व बैंक को अपने निधिकरण जोखिम प्रोफाइल और 'सुदृढ़ सिद्धांतों' के अनुपालन को दर्शाने के लिए और अधिक कठोर मानकों को अपनाने के लिए एक व्यक्तिगत बैंक की आवश्यकता हो सकती है।
3. **बैंक धन के अविनियोजन के लिए एन.बी.एफ.सी. सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना रहा: आर.बी.आई.**
   - गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एन.बी.एफ.सी.) अपनी तरलता की समस्या के बावजूद, बैंक धन के अविनियोजन के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना रहा।
   - भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, एन.बी.एफ.सी. को क्रेडिट 2017 के इसी

महीने में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अक्टूबर में 55 प्रतिशत बढ़ गया।

- अक्टूबर-अंत में एन.बी.एफ.सी. के बकाया राशि का योग 5.62 ट्रिलियन था, जो अक्टूबर 2017 में 3.6 ट्रिलियन था। सितंबर 2018 के अंत में यह 5.46 ट्रिलियन था।

4. आर.बी.आई. ने इंफ्रा कंपनियों के लिए ई.सी.बी. मानदंडों को आसान बनाया

- रिज़र्व बैंक ने "सरकार के परामर्श के साथ" बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विदेशी ऋण को नियंत्रित करने वाले मानदंडों को उदार बनाया है।
- पात्र उधारकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधारभूत संरचना अवधि में ई.सी.बी. (बाहरी वाणिज्यिक उधार) के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकता को पिछले पांच वर्षों से तीन साल कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक ने घोषणा की कि अनिवार्य बचाव-व्यवस्था के लिए औसत परिपक्वता आवश्यकता को पिछले दस वर्षों से पांच साल कर दिया गया है।

5. आरबीआई ने बैंकों को डीआरआई के साथ विदेशी मुद्रा डेटा साझा करने के आदेश दिए

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के साथ डेटा साझा करने के लिए विदेशी मुद्रा (अधिकृत डीलर -1 बैंक) में सौदा करने के लिए अधिकृत किया है।
- सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए डीआरआई सर्वोच्च खुफिया और जांच एजेंसी है।

6. आर.बी.आई ने ड्यूश बैंक और जम्मू-कश्मीर बैंक पर जुर्माना लगाया

- **भारतीय रिजर्व बैंक** ने दो ऋणदाताओं - **ड्यूश बैंक** और **जम्मू-कश्मीर बैंक**, प्रत्येक पर परिसंपत्ति वर्गीकरण और अपने ग्राहक को जानों (know your customer) मानदंडों सहित विभिन्न मानदंडों की अवज्ञा के लिए 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इन दोनों बैंकों पर बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफलता को ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगाया गया है।

अक्टूबर

6. आर.बी.आई. ने नए खाते खोलने के लिए फिनो भुगतान बैंक पर लगा प्रतिबंध हटाया

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने फिनो भुगतान बैंक के लिए नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया।
- परिचालन दिशानिर्देशों के अनुपालन के कारण मई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, विशेष रूप से स्वीकृत राशि से अधिक राशि वाले कुछ खातों से।
- भुगतान बैंकों के लिए आर.बी.आई. के परिचालन दिशानिर्देशों ने कहा कि उसके बैंक खाते में ग्राहक के लिए कुल सीमा 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. आर.बी.आई. ने वित्त वर्ष 19 के दूसरी छमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति दर 3.9-4.5 पी.सी. कम की

- रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति दर को मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में असामान्य रूप से अनुकूल प्रवृत्ति के कारण 3.9-4.5 प्रतिशत कर दिया।
- "मुद्रास्फीति दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) 2018-19, 3.2-4.5 प्रतिशत एच2 (अक्टूबर-मार्च) में 4 प्रतिशत और क्यू (Q) 1: 201 9-20 (अप्रैल-जून) में 4.8 प्रतिशत के साथ, उछाल के लिए कुछ हद तक जोखिम के लिए अनुमानित है।

8. आर.बी.आई. नकदी प्रबंधन के लिए प्रणाली में 12,000 करोड़ रुपये लगा कर नवीनता लाएगा

- रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि त्यौहार के मौसम में धन की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी बॉन्ड की खरीद के जरिए यह प्रणाली में 12,000 करोड़ रुपये की नकदी लगाएगा।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि सरकार वर्ष 2020 से वर्ष 2030 के बीच परिपक्वता के साथ बांड खरीदेगी।
- सरकारी बॉन्ड खरीदने की नीलामी प्रणाली में नकदी प्रबंधन करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओ.एम.ओ.) का एक हिस्सा है जो नकदी तनाव का सामना कर रहा है।
- ओ.एम.ओ. के हिस्से के रूप में, आर.बी.आई. वर्ष 2020 में 8.27 प्रतिशत, वर्ष 2022 (8.15 प्रतिशत), वर्ष 2024 (7.35 प्रतिशत), वर्ष 2026 (8.15 प्रतिशत) और वर्ष 2030 (7.61 प्रतिशत) की ब्याज दर के साथ परिपक्व सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेंगे।)।

नोट:

- ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओ.एम.ओ.) वह उपकरण हैं जिसका उपयोग सिस्टम से नकदी लगाने या निकालने के लिए किया जा सकता है।
- यह टिकाऊ आधार पर बाजार में रुपया नकदी की स्थिति समायोजित करने के लिए किया जाता है।
- अगर अतिरिक्त नकदी है, तो आर.बी.आई. प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा लेता है और रुपये की नकदी को खींचता है।
- इसी तरह, जब नकदी की तनावपूर्ण स्थिति होती है, तो यह बाजार से प्रतिभूतियों को खरीदती है, जिससे बाजार में पैसा जारी होता है।

9. आर.बी.आई. सर्वेक्षण: अधिकांश भारतीय परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति को लेकर संदेहपूर्ण हैं

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) के नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश की आम आर्थिक स्थिति के बारे में भारतीय लोगों की धारणा घट गई है और पिछले दौर की तुलना में अभी भी निराशावादी क्षेत्र में बनी हुई है।
- लेकिन वे एक साल बाद सुधार देखने की उम्मीद कर रहे हैं।
- मौजूदा स्थिति सूचकांक सितंबर 2018 के दौर में सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार परिदृश्य पर उपभोक्ताओं की धारणा को और खराब करता है।
- सर्वेक्षण 13 प्रमुख शहरों - दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, पटना और तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था।
- इसने धारणाओं और परिवारों की अपेक्षाओं पर लगभग 5,264 प्रतिक्रियाएं एकत्र कीं।

प्रमुख बिंदु

- उपभोक्ता विश्वास सूचकांक में गिरावट आई है और जून 2018 में किए गए सर्वेक्षण के पिछले दौर में 98.3 से 94.8 अंक की गिरावट आई है।
- जून 2018 के दौर में 119.8 अंकों की तुलना में एक साल आगे की उम्मीदें 121.1 अंक तक पहुंच गईं।
- नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार, लगभग 44.3% लोगों ने महसूस किया है कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, लगभग 33.7% ने कहा है कि इसमें सुधार हुआ है।
- दिलचस्प बात यह है कि, 53.2% लोग मानते हैं कि सर्वेक्षण के अगले एक साल में स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
- मूल्य स्थिति के बारे में, लोगों के एक बड़े प्रतिशत - 88.3% - के अनुसार मूल्य स्तर बढ़ गया है और 80.1% प्रतिभागियों ने कहा है कि यह साल-दर-अवधि की अवधि में उच्च रहेगा।
- लेकिन, अधिकांश प्रतिभागी कीमत की स्थिति के बारे में निराशावादी बने रहे। इसके अलावा, उत्तरदाताओं का बहुमत अगले एक वर्ष में आय का स्तर बढ़ने की उम्मीद करता है।

सितंबर

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने सी.आई.एम.एस. को लागू करने के लिए इंफोसिस, टी.सी.एस., 3 अन्य आई.टी. कम्पनियों का चयन किया

- रिजर्व बैंक ने समेकित डेटा संग्रह और सत्यापन के लिए केंद्रीकृत सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली (सी.आई.एम.एस.) के कार्यान्वयन के लिए इंफोसिस

एवं टी.सी.एस. समेत पांच आई.टी. कम्पनियों को सूचीबद्ध किया है।

- केंद्रीय बैंक ने शीर्ष बैंक के डेटा वेयरहाउस (डी.डब्ल्यू.) का निरीक्षण करके सी.आई.एम.एस. के कार्यान्वयन के लिए समाधान प्रदाता की पहचान के लिए जुलाई में ब्याज की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) के लिए आमंत्रित किया था।

2. **आर.बी.आई. ने बंधन बैंक की नई शाखाएं खोलने पर रोक लगाई, सी.ई.ओ. के मुआवजे को स्थिर किया**
   - भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बंधन बैंक की नई शाखाएं खोलने पर रोक लगा दी है,और शेयरहोल्डिंग नियमों पर स्थिरता में विफलता के कारण बैंक के सी.ई.ओ. वेतन पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है।
3. **आर.बी.आई. ने करूर वैश्य बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया**
   - भारतीय रिजर्व बैंक ने करूर वैश्य बैंक पर अपने निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 5 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है।
4. **आर.बी.आई. ने नकदी को सहज करने के लिए बैंकों के लिए नकद आरक्षित नियमों को आसान बनाया**
   - भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को देश के मुद्रा बाजारों को प्रभावित करने वाली नकदी की कठिन परिस्थिति को कम करने के लिए सांविधिक नकदी भंडार में आगे बढ़ने की अनुमति दी।
   - भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कथन में कहा है कि बैंक अपने नकदी आवरण अनुपात (एल.सी.आर.) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैधानिक नकदी भंडार के तहत 13 प्रतिशत की तुलना में 15 प्रतिशत तक धारण क्षमता बना सकते हैं।
   - भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इसके परिणामस्वरूप एल.सी.आर. के लिए फंड का लाभ उठाने की सुविधा में वृद्धि हुई है, जो 1 अक्टूबर से 11 फीसदी प्रभावी है।

   नोट:
   - एस.एल.आर. जमा धन का प्रतिशत है जिसमें भारत में वाणिज्यिक बैंकों को ग्राहकों को क्रेडिट प्रदान करने से पहले नकद, स्वर्ण भंडार, सरकारी अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
   - वर्तमान एस.एल.आर. 19.5 प्रतिशत है ।
5. **जून के अंत में भारत का बाहरी ऋण 2.8 प्रतिशत गिरकर 514.4 अरब डॉलर हो गया: आर.बी.आई.**
   - भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, वाणिज्यिक ऋण, अल्पकालिक ऋण और अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) जमा में कमी के कारण पिछले तिमाही के दौरान जून के अंत में भारत का बाहरी ऋण 2.8 प्रतिशत घटकर 514.4 अरब डॉलर हो गया।
   - जून 2018 के अंत में, विदेशी ऋण 514.4 बिलियन अमरीकी डालर पर रखा गया था, मार्च 2018 के अंत में 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्ज की गई।
6. **आरबीआई ने धोखाधड़ी का पता लगाने में देरी के कारण यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया**
   - भारतीय रिजर्व बैंक ने समय पर धोखाधड़ी का पता न लगाने और रिपोर्ट करने में विफल होने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
   - आरबीआई में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के निहित शक्तियों के प्रयोग में यह जुर्माना लगाया गया है , "यूनियन बैंकोफ इंडिया ने शुक्रवार को एक नियामक फाइलिंग में कहा।
   - आरबीआई ने 15 जनवरी, 2018 को बैंक को एक कारण नोटिस जारी किया था कि अधिनियम के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना क्यों नही लगाया जाए।
7. **आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए है कि बैंक स्तर पर शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक लोकपालों को नियुक्त करें**
   - भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिये है जिनके 10 से अधिक बैंकिंग आउटलेट है कि एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त करें जिससेग्राहको की शिकायतों को बैंक स्तर पर ही हल किया जा सके।

- 'आंतरिक लोकपाल योजना, 2018' के अनुसार, आईओ ग्राहक शिकायतों की जांच करेगा जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से बैंक द्वारा खारिज किए गए हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियामक निरीक्षण के अलावा, आईओ योजना 2018 के कार्यान्वयन की निगरानी बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र द्वारा की जाएगी।
- "इससे पहले, आईओ योजना अर्द्ध औपचारिक व्यवस्था थी। अब, यह अनिवार्य कर दिया गया है। एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा, उनके निर्णय बैंक पर बाध्यकारी होंगे
- मई 2015 में, आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी थी, निजी ग्राहक सेवा अधिकारी, या आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के लिए निजी और विदेशी बैंकों का चयनकरें।
- इस योजना के अनुसार, आईओ के पास तीन से पांच वर्ष का कार्यकाल तय होगा, जो विस्तार योग्य नहीं है। उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- आईओ नियुक्त होने के बाद, उसे आरबीआई की अनुमति के बिना हटाया नहीं जा सकता है। उनका पारिश्रमिक बैंक के बोर्ड की ग्राहक सेवा उप-समिति द्वारा तय किया जाएगा।

8. आरबीआई ने वित्त वर्ष 18 में 8.46 टन सोने की खरीद की; ये 9 साल में पहली बार इतनी खरीद है

- एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 8.46 टन सोना खरीदा है, जो लगभग नौ वर्षों में शीर्ष बैंक द्वारा पीले धातु की पहलीखरीद है।
- आरबीआई की 2017-18 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 30 जून, 2017 को 557.77 टन की तुलना में 30 जून, 2018 को आरबीआई के पास 566.23 टन सोना था।
- रिपोर्ट में कहा गया है, "इस वर्ष में 8.46 टन सोने की वृद्धि हुई है।"

पिछली बार शीर्ष बैंक ने सोना नवंबर 2009 में खरीदा था , जब उसने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 200 टन पीले धातु खरीदे थे।

अगस्त

1. एस गुरुमूर्ति, सतीश मराठे आरबीआई बोर्ड में शामिल

- केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड पर अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में सतीश काशीनाथ मराठे और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को नियुक्त किया।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति के मुताबिक, उनकी नियुक्ति चार साल के लिए की गई है।

2. आरबीआई, वित्त वर्ष 18 के लिए सरकार को 50,000 करोड़ रुपये का लाभांश देगा

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकार को अपने अतिरिक्त धन का 50,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेगा, जो 2015-16 के बाद से सबसे अधिक है, यह संघर्ष कर रहे कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक आंशिक राहत है।
- यह धन स्थानांतरण, सरकार को बैंकों में पूंजी लगाने के लिए अधिक सहायता देगा।
- वित्त वर्ष 2016 और 2017 के आर्थिक सर्वेक्षणों ने आरबीआई से सरकार को अतिरिक्त पूंजी के बड़े हस्तांतरण के लिए भी दबाव डाला था।

3. चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.4% पर बढ़ने के लिए: आरबीआई

- रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक गतिविधि और अच्छे मॉनसून में भारत की आर्थिक विकास दर 7.4 फीसदी की दर से बढ़ेगी।

जुलाई

1. **भारतीय रिजर्व बैंक (R.B.I.) लैवेंडर (हल्का बैंगनी) रंग में 100 रुपए के नए नोट जारी किये**

- भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल के हस्ताक्षर

वाले महात्मा गांधी (नयी) श्रृंखला में 100 रुपए मूल्यवर्ग के नए बैंकनोट जारी किया है।

100 रुपए के नए बैंक नोट के बारे में जानने योग्य बातें निम्न हैं:

- बैंकनोट का आकार **66 मि.मी.**× **142 मि.मी.** होगा, जो वर्तमान 100 रुपए के नोट से छोटा है।
  नोटः वर्तमान 100 रुपए के नोट का आकार 157 मि.मी.×73 मि.मी. है।
- आधार रंग - मुख्य नोट का रंग लैवेंडर है।
- रूपांकन : नए नोट में उल्टी तरफ **गुजरात स्थित विरासत स्थल "रानी की वाव"** का रूपांकन है।

2. **पी-2-पी प्लेटफॉर्म का नियमन आर.बी.आई. द्वारा किया जाएगा**
   - पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (पी-2-पी) प्लेटफॉर्म को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसा व्यवहार किया जाएगा और **भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)** इनका नियमन करेगी।
   - केंद्रीय बैंक जल्द ही इन प्लेटफॉर्म के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगी।

पी 2 पी उधार क्या है?

- पी-2-पी लेंडिंग एक भीड़-वित्त पोषण मॉडल है (मुख्यतः ऑनलाइन) जहां पैसा उधार देने वाले व्यक्तियों को उधार ले सकने वाले व्यक्तियों की तलाश होती है।
- इसकी अवधारणा मुख्यतः इस विचार पर केन्द्रित है कि इसमें बचतकर्ता अपने धन को बचाकर रखने के स्थान पर उसे उधार देकर अधिक ब्याज दर प्राप्त करते हैं वहीं उधारकर्ता को यह धन तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दर पर प्राप्त होता है।
- उधारकर्ता व्यक्ति अथवा लघु व्यवसायी होते हैं। लेकिन पारंपरिक बचत खातों के विपरीत, उधारकर्ता के डिफॉल्टर (धोखेबाज) साबित होने पर ऋणदाता अपना धन गंवा सकता है।

3. **मोनेक्सो फिनटेक को पी.2.पी. बिज़ के लिए आर.बी.आई. से प्रमाणपत्र मिल गया है**
   - भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनेक्सो फिनटेक (प्राइवेट) लिमिटेड को भारत में संचालन के लिए गैर-बैंकिंग वित्त निगम - पी-2-पी प्रमाणपत्र दे दिया है।
   - भारत में पीयर-2-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म में वृद्धि हो रही है, जिसके पीछे मुख्य वजह बढ़ता डिजिटल लेनदेन, फिनटेक इनोवेशन और सुलभ क्रेडिट की बढ़ती मांग है।
   - आर.बी.आई. के प्रमाणपत्र से मोनेक्सो फिनटेक को वित्त बाजार में दखल प्राप्त होगा और उसके अपने निवेशक समुदाय के बीच भरोसा मजबूत होगा।

4. **फेडरल बैंक को बहरीन, कुवैत और सिंगापुर में प्रवेश के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति मिली**
   - फेडरल बैंक को बरहीन, कुवैत और सिंगापुर में अपने कार्यालय खोलने के लिए रिज़र्व बैंक की नियामक अनुमति मिल गयी है।
   - कोची स्थित मुख्यालय वाली यह बैंक प्रवासी प्रेषण में अग्रणी है और इसके अबू धाबी और दुबई में पहले से कार्यालय हैं।

5. **भारतीय रिजर्व बैंक ने अलवर शहरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया:**
   - आरबीआई ने राजस्थान के अलवर में अलवर शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि वह

अपने जमाकर्ताओं को पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम नहीं है।

6. **रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को दिया भारत में कामकाज शुरू करने का लाइसेंस**
   - रिजर्व बैंक ने बैंक आफ चाइना को भारत में कामकाज शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है।
   - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से इसका वादा किया था।
   - पिछले महीने चीन के क्विंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन (**SEO**) की शिखर बैठक में यह वादा किया गया था।
   - बैंक ऑफ चाइना चीन का सबसे पुराना बैंक हैं।
   - यह देश में काम करने वाला दूसरा चीनी बैंक होगा.
   - **1** जनवरी, **2018** को औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड **45** अन्य विदेशी बैंकों के साथ भारत में काम कर रहा है.

जून

1. **एम.के. जैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गये**
   - आईडीबीआई के सीईओ महेश कुमार जैन को तीन साल की अवधि के लिए चौथे डिप्टी गवर्नर के रुप में नियुक्त किया गया है।
   - एस.एस. मुंद्रा जुलाई 2017 में सेवानिवृत्त होने के बाद से चौथे डिप्टी गवर्नर का पद खाली हो गया था ।
   - आरबीआई अधिनियम के मुताबिक, केंद्रीय बैंक में चार डिप्टी गवर्नर होना चाहिए - रैंक के भीतर से दो और एक वाणिज्यिक बैंकर और दूसरा अर्थशास्त्री मौद्रिक नीति विभाग का नेतृत्व करेगा।
   - महेश कुमार जैन को 2017 में आईडीबीआई बैंक के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया था और इससे पहले वह नवंबर 2015 और मार्च 2017 के बीच चेन्नई स्थित इंडियन बैंक में सीईओ थे।
2. **सुधा बालकृष्णन को आरबीआई का पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया**
   - सुधा बालकृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया गया है।
   - भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल होने से पहले, वह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी की उपाध्यक्ष थी।
   - वह आरबीआई के 12 वें कार्यकारी निदेशक होंगे और तीन साल की अवधि होगी।
3. वित्तीय साक्षरता सप्ताह विषय 'ग्राहक संरक्षण' के साथ संपन्न हुआ:
   - भारतीय रिजर्व बैंक ने 'ग्राहक संरक्षण' विषय से वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया।
   - इसका उद्देश्य विभिन्न वित्तीय उत्पादों, सेवाओं, डिजिटल अनुप्रयोगों और बैंकों के ग्राहकों के बीच अच्छे वित्तीय प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
4. **आर.बी.आई खराब ऋण को रोकने के लिए पीसीआर की स्थापना करेगा**
   - भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि वह एक सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) स्थापित करेगा जो एक सूचना भंडार होगा जो व्यक्तियों और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की सभी ऋण जानकारी को एकत्रित करेगा।
   - एक क्रेडिट रिपोजिटरी बैंकों को बुरे और अच्छे उधारकर्ता के बीच अंतर करने में मदद करेगी और तदनुसार अच्छे उधारकर्ताओं को आकर्षक ब्याज दरें और खराब उधारकर्ताओं को उच्च ब्याज दरें प्रदान करेगी।
   - यह कदम पिछले साल स्थापित समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका नेतृत्व एम. देवस्थली ने किया है। समिति ने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट पेश की थी।
5. **आरबीआई ने गोल्ड मुद्रीकरण योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें संशोधन किया**
   - रिजर्व बैंक ने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम (जीएमएस) को आकर्षक बनाने के लिये इसमें कुछ बदलाव किया है।
   - योजना में सुधार का मकसद लोगों को स्वर्ण बचत खाता खोलने को सुगम बनाना है।

- रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि अल्पकालीन जमा को बैंक के बही-खाते पर देनदारी के अनुरूप माना जाना चाहिए।
- रिजर्व बैंक ने कहा है कि, 'यह जमा मनोनीत बैंकों में एक से तीन साल के लिये किया जाएगा। अन्य अवधि के लिये भी जमा की अनुमति होगी।
- यह एक साल तीन महीने , दो साल चार महीने पांच दिन आदि हो सकता है।' आरबीआई के अनुसार अलग - अलग अवधि के लिये ब्याज दर का आकलन पूरे हुए वर्ष तथा शेष दिन के लिये देय ब्याज पर तय किया जाएगा।
- सरकार ने 2015 में यह योजना शुरू की थी। इसका मकसद घरों तथा संस्थानों में रखे सोने को बाहर लाना और उसका बेहतर उपयोग करना है।

6. आरबीआई ने बैंक क्रेडिट की डिलीवरी के लिए ऋण प्रणाली पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक क्रेडिट की डिलीवरी के लिए ऋण प्रणाली पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए जो निधि आधारित कार्यशील पूंजी वित्त में ऋण घटक के न्यूनतम स्तर और बड़े उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त की गई नकदी क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट सीमाओं के गैर-आहरित भाग के लिए अनिवार्य क्रेडिट अंतरण कारक (सीसीएफ) निर्धारित करती हैं जिसका लक्ष्य बड़े उधारकर्ताओं के बीच क्रेडिट अनुशासन को बढ़ाना है।

'ऋण घटक' का न्यूनतम स्तर और प्रभावी तिथि

- "बैंकिंग प्रणाली से 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल फंड आधारित कार्यशील पूंजी सीमा वाले उधारकर्ताओं के संबंध में, 1 प्रतिशत, 2018 से 40 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर 'ऋण घटक' प्रभावी होगा।
- तदनुसार, ऐसे उधारकर्ताओं के लिए, बकाया 'ऋण घटक' स्वीकृत फंड आधारित कार्यशील पूंजी सीमा के कम से कम 40 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए, जिसमें विज्ञापन क्रेडिट सुविधाएं शामिल हैं।

नकद क्रेडिट सीमा के अनचाहे हिस्से के लिए जोखिम भार

- 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, उपरोक्त बड़े उधारकर्ताओं को स्वीकृत नकद क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट सीमाओं का अनचाहे हिस्सा, चाहे बिना शर्त रूप से रद्द करने योग्य या नहीं, 20 प्रतिशत का क्रेडिट रूपांतरण कारक आकर्षित करेगा।
- 1 अप्रैल, 2019 से 40 प्रतिशत ऋण घटक 60 प्रतिशत तक संशोधित किया जाएगा।

7. आर.बी.आई. ने ऋण में निवेश करने के लिए एफ.पी.आई. के मानदंडों को सुलभ बनाया;

- रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत बड़े निगमों में निवेश मानदंडों को आसान बना दिया है.
- एफपीआई को सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, राज्य विकास ऋण और कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे विभिन्न ऋण बाजार उपकरणों में निवेश करने की अनुमति है, लेकिन कुछ सीमाओं और प्रतिबंधों के साथ।
- आरबीआई ने सरकारी सुरक्षा में एफपीआई की कैप में 20 फीसदी से पहले उस सुरक्षा के बकाया शेयर का 30 प्रतिशत बढ़ाया।
- एफपीआई को सरकारी बांड में तीन साल की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता के साथ निवेश करने की इजाजत थी।

8. आर.बी.आई. ने प्राथमिकता क्षेत्र के तहत महंगे आवासीय ऋण की सीमा को संशोधित किया

- रिजर्व बैंक के अनुसार, 45 लाख रुपये से कम की कीमत वाले आवासों के लिए 35 लाख रुपये तक के आवास ऋण को कम लागत वाले सेगमेंट को भरने के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) माना जाएगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों के लिए कम लागत वाले आवास को प्रोत्साहन देने के लिए, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत पात्रता के लिए आवास ऋण सीमा को महानगरीय केंद्रों में 35 लाख रुपये और अन्य केंद्रों में 25 लाख रूपए में संशोधित किया जाएगा।
- एक शर्त है कि प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने के लिए महानगरीय केंद्र (दस लाख और उससे

अधिक की आबादी के साथ) और अन्य केंद्रों में आवास इकाई की कुल लागत क्रमशः 45 लाख रुपये और 30 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- वर्तमान में, महानगरीय केंद्रों में 28 लाख रुपये और अन्य केंद्रों में 20 लाख रुपये के लिए व्यक्तियों को ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि आवासीय इकाई की लागत क्रमशः 35 लाख रुपये और 25 लाख रुपये से अधिक न हो।

9. आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रबंधन बोर्ड का प्रस्ताव रखा है:

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में 100 करोड़ रुपये से अधिक का जमा आकार रखने वाले प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।
- इसका उद्देश्य शासन को मजबूत करना और इन बैंकों में पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
- 2010 में, वाईएच मालेगाम की अध्यक्षता में गठित नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने पर विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक यूसीबी में बीओएम का गठन किया जाना चाहिए।
- आरबीआई द्वारा जनवरी 2015 में गठित आर गांधी की अध्यक्षता में यूसीबी पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा इसे दोहराया गया था।

10. आरबीआई ने बैंकों से अधिक सुरक्षा के लिए एटीएम को अपग्रेड करने का आदेश दिया:

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से सभी एटीएम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल करने और जून 2019 तक उन्हें अपग्रेड करने के लिए कहा है।
- पूरे देश में फरवरी के अंत तक 2.06 लाख से ज्यादा एटीएम थे।
- आरबीआई द्वारा अधिसूचित समयरेखा के अनुसार, सभी एटीएम को जून 2019 तक अपग्रेड किया जाना चाहिए।

मई

1. आरबीआई ने आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए मानदंडों को संशोधित किया

- भारतीय रिजर्व बैंक ने आईएफएससी में बैंकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) की स्थापना के मानदंडों में संशोधन किया।
- नए मानदंडों के मुताबिक - मूल बैंक को आईबीयू में किसी भी विदेशी मुद्रा में न्यूनतम 20 मिलियन डॉलर या समकक्ष की पूंजी प्रदान करने और बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
- अप्रैल 2015 में, आरबीआई ने आईएफएससी में बैंकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की।

2. आरबीआई ने बैंकों के लिए 100% शुद्ध स्थिर निधि अनुपात का प्रस्ताव दिया

- 17 मई 2018 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) पर सुझाव देने के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों की लंबी अवधि में अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए वित्त पोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।
- आरबीआई बैंकों के लिए 100 प्रतिशत शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) का सुझाव देता है

जो बासेल III तरलता मानकों में दीर्घकालिक तरलता माप शामिल है।

- बैंकों को हर तिमाही के लिए 15 दिनों के भीतर एनएसएफआर डेटा जमा करना होगा।

एनएसएफआर के बारे में

- एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) की मात्रा के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह बैंकों को अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए निरंतर आधार पर वित्त पोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ लंबी अवधि के समय क्षितिज पर लचीलापन को बढ़ावा देता है।
- उपरोक्त अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए।

उद्देश्य

- एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी संपत्ति और ऑफ-बैलेंस शीट गतिविधियों की संरचना के संबंध में एक स्थिर निधि प्रोफ़ाइल बनाए रखें।

नोट:

- बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) पर बेसल कमेटी ने 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान वैश्विक पूंजी और तरलता नियमों को मजबूत करने के लिए कुछ सुधारों का प्रस्ताव दिया।
- इस संबंध में दो न्यूनतम मानकों को प्राप्त करने के लिए बासेल समिति द्वारा तरलता को वित्त पोषित करने के लिए तरलता कवरेज अनुपात (एनसीआरआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) निर्धारित किया गया है।
- भारत में, एलसीआर 1 जनवरी 2019 से पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा।

3. आरबीआई ने साउथ इंडियन बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

- 18 मई 2018 को, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संपत्ति वर्गीकरण, जानकारियों-ग्राहक (केवाईसी) और ट्रेजरी कार्य करने पर अपने नियमों का पालन न करने के लिए साउथ इंडियन बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

4. आरबीआई ने 3 NBFCs के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, **1934 की धारा 45-आईए (6)** के तहत इसे प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित कंपनियों के पंजीकरण का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया – i. जगन्नाथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ii. एससीएफ फाइनेंस लिमिटेड, iii. मानसर फाइनेंस लिमिटेड.

5. आरबीआई ने देना बैंक पर पीसीए लगाया

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उच्च गैर-निष्पादित ऋण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता देना बैंक के खिलाफ 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' शुरू की है।
- आरबीआई के पीसीए मानदंडों के मुताबिक, बैंक जोखिम सीमा के दूसरे स्तर पर है क्योंकि उसने लगातार तीन साल नकारात्मक आरओए और शुद्ध एनपीए 9% से अधिक की सूचना दी है।
- चौथा और अंतिम जोखिम सीमा चार साल की नकारात्मक आरओए और 12% से अधिक नेट एनपीए है।

- **Returns on Assets** (ROA)– ROA उन मापदंडों में से एक है जिस पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बैंकों का निर्णय लिया जाता है।

देना बैंक का सकल एनपीए 22.4% तक पहुँच गया

- सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में बैंक की सकल गैर-निष्पादित संपत्तियां मार्च के अंत तक 22.4% थीं, जबकि एक साल पहले 16.17% थी।
- पूर्ण रूप से, खराब ऋण ₹ 12,618.73 करोड़ से, 16,361.44 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- बैंक का कुल एनपीए 10.66% या 735.12 करोड़ से 11.95% या ₹ 7,838.78 करोड़ तक हो गया था।
- 2017-18 के लिए बैंक की नकारात्मक रिटर्न (ROA) -1.5 9 है - जो एक साल पहले 0.67 थी।

तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई

- तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश किया गया एक गुणात्मक उपकरण है जिसके तहत बैंक की वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कमजोर बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है।
- भारत में पहली बार पीसीए, आरबीआई के गवर्नर के रूप में बिमल जालान की अवधि के दौरान 2002 में पेश किया गया था और आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने अप्रैल 2017 को इसके नियम को और कड़ा कर दिया था।
- यह आरआरबी को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), लघु वित्तीय बैंक पर लागू है। यह भुगतान बैंक, एनबीएफसी और मुद्रा बैंकों की अपनी सीमा में भी नहीं लेता है।

विभिन्न संगठनों द्वारा अनुमानित भारत की जी.डी.पी. विकास दर - 2018

1. **आरबीआई** - केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 7.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।
2. **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) -** आई.एम.एफ. की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में इसने भारत की जी.डी.पी. विकास दर **वर्ष 2018-19 में 7.3 % और वर्ष 2019-20 में 7.4 %** होने का अनुमान लगाया।
3. **विश्व बैंक -** विश्व बैंक द्वारा जारी 2018-ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट (जी.ई.पी.) ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को **वर्ष 2018 में 7.3% से और वर्ष 2019 और 2020 में 7.5%** तक ले जाने का अनुमान लगाया।
4. **एडीबी** बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष (2018-19) में भारत की विकास दर **7.3 फीसदी** रहने का अनुमान लगाया है और वित्त वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था की विकास दर **7.6 फीसदी** के स्तर पर रहेगी.
5. **इंड-रा ने वित्त वर्ष 19 के विकास दृष्टिकोण को 7.4% से 7.2% तक संशोधित किया**
   - भारत रेटिंग और रिसर्च ने 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनुमानित 7.4% से 7.2% की भविष्यवाणी के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है।
6. **एच 2 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% हो सकती है: नोमुरा**

- नोमुरा अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और 2018 के दूसरे छमाही में पहली छमाही में 7.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद करता है।

7. 2018, 201 9 में भारत का जीडीपी विकास 7.5% तक बढ़ने की उम्मीद है: **मॉर्गन स्टेनली**
8. **Fitch ने FY18-19 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान बढ़ाकर 7.8 फीसदी किया**
    - फिच ने अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में वित्तवर्ष 2018-19 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.8 प्रतिशत कर दिया है।
    - फिच ने 2019-20 के लिए वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.3 प्रतिशत तय किया है.
9. **संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट -** संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं (डब्ल्यूईएसपी) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.6% तक बढ़ने की उम्मीद है। 2017-18 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.5 से बढ़ने की उम्मीद है।
10. **चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% बढ़ी: केंद्रीय सांख्यिकी डेटा**
    - केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-मार्च में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सात तिमाहियों में 7.7 फीसदी की तेजी से बढ़ रहा है, जो चीन की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे है।
11. **भारत 2022 तक 9% की वृद्धि दर हासिल करेगा: नीति आयोग**
    - **नीति आयोग** के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 तक निरंतर आधार पर 9 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करेगी।
    - 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान

नवम्बर

1. **विश्व बैंक का ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस 2019: भारत 77वें स्थान पर पहुंचा**
    - विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस 2019 सूचकांक में 190 देशों के बीच भारत ने 23वें स्थान से 77वें स्थान पर बढ़त हासिल की।
    - 31 अक्टूबर, 2018 को विश्व बैंक ने वर्ष 2018 में ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस के आधार पर 'डूंईग बिजनेस 2019: ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म' नामक रिपोर्ट जारी कर देशों का आकलन और उन्हें स्थान दिया गया।
    - पिछले साल, भारत ने शीर्ष 100 तक पहुंचने के लिए 30 स्थानों की प्रगति की।
    - अपनी वार्षिक 'डूइंग बिजनेस' 2019 की रिपोर्ट में, विश्व बैंक ने कहा कि भारत ने देश में कारोबार शुरू करने और व्यवसाय करने के 10 में से छह पैरामीटर में सुधार किया है।
    - संकेतों में "निर्माण स्वीकृति" और "सीमाओं के पार व्यापार" से जुड़े सबसे बड़े सुधार हुए हैं।
    - ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस से शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर और डेनमार्क शामिल हैं।
2. **आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2018 : भारत को 53वां स्थान**

- स्विट्जरलैंड लगातार पांचवें वर्ष के लिए आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2018 की सूची में शीर्ष स्थान पर है.
- ब्रिक्स देशों में, दक्षिण अफ्रीका को मध्य स्थान(50 वां) के साथ भारत (53 वां) और ब्राजील (58 वां) से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है लेकिन वह चीन (39 वां) और रूस (46 वां) से पीछे है.

सूची में शीर्ष 3 देश हैं:

- स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे

अक्टूबर

1. **फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक नियोक्ता की सूची में एल एंड टी को 22वां स्थान**
   - इंजीनियरिंग और निर्माण प्रमुख लार्सन एंड टुब्रो फोर्ब्स की वैश्विक 2000 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में शीर्ष 25 कंपनियों में शामिल होने वाली एकमात्र घरेलू फर्म है.
   - एल एंड टी 22 वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष 100 की सूची में महिंद्रा एंड महिंद्रा 55, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 59 और एचडीएफसी 91वें स्थान पर है.
   - सूची में शीर्ष 3 कंपनियां हैं: अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्प्ल.
2. **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2018: भारत 58 वें स्थान पर है**
   - रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2018 पर भारत ने 5 स्थान की बढत के साथ 58वें सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है.
   - इस रिपोर्ट में अमेरिका शीर्ष पर है उसके बाद सिंगापुर और जर्मनी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
   - भारत ने G20 देशों के बीच सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया है.
   - विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2018 जारी की है.
3. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018: भारत 103 वां स्थान पर
   - ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 119 देशों में भारत 103वें स्थान पर है।
   - रिपोर्ट के अनुसार, भारत 45 देशों में से एक है जहां "भूख के गंभीर स्तर" हैं।
   - 2017 में, भारत 100 वें स्थान पर था।
   - 2018 ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) इंगित करता है कि दुनिया भर में भूख और कुपोषण का स्तर 2000 में 29.2 से नीचे 20.9 के मान पर गंभीर श्रेणी में आता है.
   - ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट वैश्विक गैर सरकारी संगठनों, कंसर्न वर्ल्डवाइड (आयरलैंड) और वेल्थुंगरहिल्फ़ (जर्मनी) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी।
   - शीर्ष 3 देशों - बेलारूस, क्यूबा, एस्टोनिया
4. विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक: भारत 115 वां स्थान पर
   - विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक पर 157 देशों के बीच भारत 115 वें स्थान पर है।
   - इस वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट (डब्लूडीआर) का विषय "काम की बदलती प्रकृति" है।

- सूचकांक बाली, इंडोनेशिया में विश्व बैंक-आईएमएफ वार्षिक बैठक में जारी किया गया था।
- सिंगापुर शीर्ष पर है उसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग और फिनलैंड देश हैं।

5. ऑक्सफैम वर्ल्ड असमानता सूचकांक 2018: भारत 147 वें स्थान पर

- विश्व असमानता सूचकांक पर 157 देशों के बीच भारत को 147 वां स्थान पर रखा गया है।
- एशियाई देशों के बीच जापान 11 वें स्थान के साथ सबसे शीर्ष रहा।
- शीर्ष 3 देशों में - डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड शामिल हैं।

सितम्बर

1. मानव पूंजी' स्कोर में शीर्ष स्थान पर, भारत 158वें स्थान पर

- मानव पूंजी के अपने स्तर के लिए पहले वैज्ञानिक अध्ययन रैंकिंग देशों के अनुसार भारत शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में अपने निवेश के लिए दुनिया में 158 वें स्थान पर है.
- भारत सूडान से पीछे (157वें स्थान पर) और नामीबिया (159 वें स्थान पर) भारत से पहले है
- पत्रिका द लंसेट में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 195 देशों में से भारत को 158वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह 1990 में 162वें स्थान से स्थिति में सुधार हुआ है
- यू.एस. 27वें स्थान पर है, जबकि चीन 44 वें स्थान पर है और पाकिस्तान 164 वें स्थान पर है.
- फिनलैंड सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क.

2. पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर: CSRI रिपोर्ट

- परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जिसमें 111 कंपनियों का 839 अरब डॉलर का कुल बाजार पूंजीकरण हैं.
- क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSRI) द्वारा प्रकाशित 2018 के 'क्रेडिट सुइस 1000 फॅमिली' अध्ययन के अनुसार, भारत, चीन के 159 फर्मों और अमेरिका के 121 फर्म से बहुत कम अंतर से पीछे है.
- रिपोर्ट के अनुसार, गैर-जापानी एशियाई क्षेत्र के भीतर पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या के मामले की सूची में चीन, भारत और हांगकांग का प्रभुत्व है.

अगस्त

1. संयुक्त राष्ट्र ई-सरकारी सूचकांक: भारत 96वां स्थान पर, डेनमार्क शीर्ष पर

- संयुक्त राष्ट्र के ई-सरकारी विकास सूचकांक (ईजीडीआई) 2018 के शीर्ष 100 में भारत पहले से 22 स्थान ऊपर 96 वें स्थान पर पहुंच गया है।
- ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर दो वर्षों में जारी किया जाता है।

सूची में शीर्ष 3 देश हैं:

- डेनमार्क,
- ऑस्ट्रेलिया,

- कोरिया गणराज्य।

2. ईज ऑफ़ लिविंग इंडेक्स 2018 : पुणे शीर्ष पर

- ईज ऑफ़ लिविंग इंडेक्स 2018 की सूची केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी की थी, जिसमें कुछ प्रमुख शहर शीर्ष 10 में जगह बनाने में नाकाम रहे।
- सूचकांक के तहत क्रमशः कुल 111 शहरों में से पुणे को पहले स्थान पर रखा गया है जबकि नवी मुंबई 'जीवितता' के मामले में दूसरी पसंदीदा स्थान के रूप में सामने आया है।

सूची में शीर्ष 5 शहर हैं:

- पुणे,
- नवी मुंबई,
- ग्रेटर मुंबई,
- तिरुपति,
- चंडीगढ़।

सूची में नीचे के 3 शहर हैं:

- रामपुर (111 वां),
- कोहिमा (110 वां)
- पटना (109 वां)।

3. वैश्विक लाइवबेलिटी इंडेक्स 2018: दिल्ली 112 वें स्थान पर है

- इस इंडेक्स में दिल्ली को 112 वां स्थान पर रखा गया और मुंबई 117 वें स्थान पर।
- ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को विश्व के सबसे जीवंत शहर के रूप में स्थान दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबोर्न को विस्थापित कर रहा है।
- ग्लोबल लाइवबेलिटी इंडेक्स 2018, इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) ने जारी किया है।

सूची में शीर्ष तीन शहर हैं:

1. वियना,
2. मेलबोर्न,
3. ओसाका।

जुलाई

1. पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018: केरल सबसे अच्छा शासित राज्य, बिहार सबसे खराब

- पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 के अनुसार, केरल देश में सबसे अच्छा शासित राज्य है, जिसे बेंगलुरु थिंक टैंक, पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात अच्छे शासन प्रदान करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में से हैं।
- बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा सूचकांक पर सबसे कम स्थान पर हैं, जो उच्च सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का संकेत देते हैं।

2. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018:

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) ने इनोवेटिव देशों की सूची में भारत को 57वें नंबर पर रखा है।
- भारत की रैंकिंग में 3 स्थान का सुधार हुआ है, पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था।
- यह इंडेक्स कॉर्नेल यूनिवसिटी और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन ने मिलकर तैयार किया है।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 3 देश: स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और स्वीडन हैं।

जून

1. **वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018:**
    - वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) रैंकिंग में भारत सबसे निचे 177 वें स्थान पर है।
    - 2016 में, 180 देशों में से भारत 141 स्थान पर था।
    - सूची में शीर्ष 3 देश हैं: स्विट्जरलैंड, फ्रांस और डेनमार्क हैं।
2. **वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2018:**
    - भारत हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक (जीआरटीआई) में 100 देशों (देशों) के बीच 35 वें स्थान पर है।
    - सूचकांक रियल्टी सलाहकार जेएलएल द्वारा जारी किया गया था।
    - शीर्ष 3 देश हैं: यूनाइटेड किंगडम (प्रथम), ऑस्ट्रेलिया (2), संयुक्त राज्य (3)।
3. **बचपन सूचकांक 2018 का अंत ":**
    - बच्चों को बचाने के लिए "बचपन सूचकांक 2018 का अंत" के अनुसार, भारत गरीब देशों, कुपोषण, शिक्षा से बहिष्कार, बाल श्रम और बाल विवाह के परिणामस्वरूप बचपन की धमकी के संबंध में 175 देशों में 113 स्थान पर है।
    - सिंगापुर और स्लोवेनिया को पहली जगह साझा करने के लिए शीर्ष स्थान पर रखा गया है और नाइजीरिया को सूचकांक की सूची के अंत में175 स्थान पर रखा गया है।
4. **वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर**
    - 2018 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 163 देशों में 136वें स्थान पर पहुंच गया है।
    - सूचकांक ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) द्वारा तैयार किया गया था।
    - आइसलैंड इंडेक्स में सबसे ऊपर है, इसके बाद न्यूज़ीलैंड (दूसरे स्थान पर), ऑस्ट्रिया (तीसरे स्थान पर), पुर्तगाल (चौथे स्थान पर), डेनमार्क (पांचवे स्थान पर) हैं।
    - सीरिया दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जो पिछले पांच सालों से एक ही स्थान पर बना हुआ है।

मई

1. **आईएमडी की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत 44 वां स्थान पर रहा**
    - अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (आईएमडी) द्वारा संकलित वार्षिक रैंकिंग में प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में भारत को 44 वां स्थान पर रखा गया है।
    - अमेरिका सूची में सबसे ऊपर है और आर्थिक प्रदर्शन और बुनियादी ढांचे में अपनी ताकत से विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बन गया है।
    - हांगकांग दूसरे स्थान पर है और सिंगापुर सूची में तीसरे स्थान पर है।
2. **व्यापार आशावाद सूचकांक 2018**
    - एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत इस वर्ष की पहली तिमाही के लिए कारोबारी आशावाद सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 6 वें स्थान पर पहुंच गया है।
    - 89 के स्कोर के साथ, भारत सूचकांक में छठे स्थान पर है।
    - रिपोर्ट में शीर्ष पांच राष्ट्र ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इंडोनेशिया, नीदरलैंड और अमेरिका हैं।

3. **एफ.डी.आई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018**
    - भारत 2018 एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 11 वें स्थान पर है।
    - पिछले साल, 2017 में, भारत एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 8वें स्थान पर था।
    - सूचकांक के इतिहास में चीन सबसे कम रैंकिंग में था। चीन 5 वें स्थान पर है और पिछले साल वह तीसरे स्थान पर था।
    - इस साल के सूचकांक पर केवल 7 एशियाई देश शामिल हैं।
    - ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म ए. टी. कीर्नी रिपोर्ट प्रकाशित करती है।
    - **सूचकांक में शीर्ष 3 देश -** संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, और जर्मनी.

विभिन्न रिपोर्ट या सर्वेक्षण में भारत का स्थान

दिसम्बर

1. **2017 में भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या में 50% तक वृद्धि: संयुक्त राष्ट्र**
    - संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अनुसार, भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या 2017 में तेजी से वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए 50% तक बढ़ी है.
    - भारत द्वारा दिए गए पेटेंट 2016 में 8,248 से बढ़कर 2017 में 12,387 हो गए है, WIPO की विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2018 की रिपोर्ट जेनेवा में जारी की गई.
    - रिपोर्ट का अनुमान है कि विश्व स्तर पर, 2017 में 1.4 मिलियन पेटेंट दिए गए थे.
2. **भारत 80 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ प्रेषण में शीर्ष स्थान पर कायम रहेगा: विश्व बैंक**
    - विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2018 में प्रेषण के विश्व के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा, जिसमें इसके प्रवासी 80 अरब अमेरिकी डॉलर घर भेज रहे है.
    - वैश्विक ऋणदाता के अनुसार भारत के बाद चीन (67 अरब अमेरिकी डॉलर), मेक्सिको और फिलीपींस (34 अरब अमेरिकी डॉलर) और मिस्र (26 अरब अमेरिकी डॉलर) हैं.
    - बैंक का अनुमान है कि 2018 में विकासशील देशों का आधिकारिक रूप से दर्ज प्रेषण 10.8% की वृद्धि के साथ 528 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा.
3. **फोर्ब्स अमेरिका में टेक की शीर्ष 50 महिलाओं की सूची में 4 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल**
    - फोर्ब्स अमेरिका टेक 2018 में शीर्ष 50 महिलाएं की सूची चार भारतीय मूल की प्रौद्योगिकी अधिकारियों ने स्थान प्राप्त किया है.
    - सूची में नेहा नारखेड़े, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म कांफ्लूएंट की सह-संस्थापक; कामक्षी शिवरामकृष्णन, सीईओ, और पहचान प्रबंधन कंपनी ड्रॉब्रिज के संस्थापक; सिस्को की पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) पद्मश्री वारियर, और उबर की वरिष्ठ निदेशक कोमल मंगलानी शामिल हैं.
4. **सलमान खान फोर्ब्स की सबसे आमीर भारतीय सेलिब्रिटी की सूची 2018 में शीर्ष पर**

- 2018 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची के अनुसार बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी है, वह लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर है.
- शाहरुख खान शीर्ष 10 सूची से बाहर हो गये है.
- 2018 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट रैंकिंग हस्तियों के मनोरंजन से संबंधित कमाई के अनुमानों पर आधारित हैं.
- भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने एक स्थान की बढत के बाद 228.0 9 करोड़ रुपये की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हासिल किया है, यह पिछले वर्ष की तुलना में 116.53 प्रतिशत है.
- अभिनेता अक्षय कुमार ने सूची के लिए विचाराधीन अवधि में 185 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त किया है.

5. संयुक्त अरब अमीरात पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली: आर्टन कैपिटल की रिपोर्ट

- संयुक्त अरब अमीरात के पास अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है.
- वैश्विक पासपोर्ट सूची में शीर्ष स्थान संयुक्त अरब अमीरात के 47 वें राष्ट्रीय दिवस और 1971 से इसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ प्राप्त हुआ.
- आर्टन कैपिटल द्वारा संकलित सूचकांक, राष्ट्रीय धारकों को उन देशों की संख्या के आधार पर रखता है जो एक धारक वीजा के बिना या आगमन पर दर्ज कर सकता है. सूची में भारत 140वें स्थान पर था.
- इंडिविजुअल पासपोर्ट पावर रैंक पर शीर्ष 3 देश हैं:

  1. संयुक्त अरब अमीरात 2. सिंगापुर 3. जर्मनी

नवम्बर

1. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019: रोजगार दर, प्रतिभा गुणवत्ता में आंध्र शीर्ष पर

- इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार आंध्र प्रदेश शीर्ष पर राजस्थान और हरियाणा उसके बाद उच्चतम रोजगार के साथ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है.
- बी.टेक / बी.ई. के नियोक्ता स्तर में सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, जो 63.11% की नई ऊंचाई को छू रही है, जो पिछले वर्ष 42.08 थी.
- हालांकि, एमबीए और पॉलिटेक्निक के नियोक्ता स्तर 47.18% और 45.90% के बीच हैं. सर्वेक्षण संयुक्त रूप से व्हीबॉक्स, पीपुल्सट्रोंग, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित किया गया था.

2. भारत की बेरोजगारी दर 2 वर्ष में अधिकतम 6.9% : रिपोर्ट

- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में देश में बेरोजगारी दर 6.9% हो गई है, जो दो वर्ष में सबसे अधिक है.
- अक्टूबर 2018 के दौरान नियोजित लोगों की अनुमानित संख्या 397 मिलियन थी. अक्टूबर 2017 में यह दर 2.4% कम थी.
- 2017 में इसी अवधि के दौरान 407 मिलियन व्यक्तियों को नियोजित किये जाने का अनुमान लगाया गया था. अक्टूबर 2018 में वयस्क जनसंख्या का केवल 39.5% नियोजित था.

3. भारत कार्बन दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बनने के लिए अमेरिका से आगे निकल जाएगा: IEA रिपोर्ट

- इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 'वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक' में कहा है कि भारत 2030 से पहले ऊर्जा क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बनने के लिए अमेरिका से आगे निकल जाएगा.
- 2040 तक भारत के ऊर्जा क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लगभग 80% तक बढ़ने की उम्मीद है क्यूंकि ऊर्जा के उपयोग के रूप में लगभग तीगुना, एयर कंडीशनिंग द्वारा भाग द्वारा संचालित है.
- चीन सबसे बड़ा उत्सर्जक बना रहा.

4. भारत में मलेरिया के मामलों में 24% की गिरावट: WHO रिपोर्ट

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत एकमात्र देश है जिसने 2017 में दुनिया भर में 11 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से मलेरिया के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की है.
- भारत ने 2016 से 24% की कटौती दर्ज की है, अधिकतर मामलों में मुख्य रूप से उड़ीसा के अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण राज्य में बीमारी की पर्याप्त गिरावट के चलते, यह देश में मलेरिया के सभी मामलों में से लगभग 40 प्रतिशत का केंद्र है.
- रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में भारत ने वैश्विक मलेरिया के मामलों में 4% का योगदान दिया था.

5. चौथी वार्षिक ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई

- 'यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस रिपोर्ट' जारी कर दी गई है. इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यूके व्यवसायों ने भारत में परिचालन करने के लिए भ्रष्टाचार के बाधा के रूप में धारणा 2015 से कम हो गयी है.
- रिपोर्ट में 122 बिलियन अमरीकी डालर के संयुक्त कारोबार के साथ कारोबारों का गहन सर्वेक्षण पाया गया, 2018 में ब्रिटेन के 25% व्यवसायों में भ्रष्टाचार को मुख्य बढ़ा के रूप में देखा गया है जो 2015 में 51% था.
- यूके व्यवसायों का 46% उत्तरदायियों के लिए अगले 12 महीनों में भारत में अपने निवेश का विस्तार करने की योजना थी.
- 2000 से, ब्रिटेन भारत में सबसे बड़ा जी 20 निवेशक रहा है, जो 17.5 अरब पाउंड का निवेश कर रहा है और 371,000 नई नौकरियां प्रदान कर रहा है, यह इस अवधि में सभी एफडीआई से संबंधित 10% नौकरियों का प्रतिनिधित्व करता है।

अक्टूबर

1. भारत दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया: मेरकोम

- मर्कॉम कम्युनिकेशंस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कैलेंडर वर्ष 2018 के पहले छमाही के दौरान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सौर बाजार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए 4.9 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा स्थापित की।
- रिपोर्ट के मुताबिक, चीन सूची में सबसे ऊपर है।

2. 2017 में भारत के ज्यादा प्रवासी: एडीबी रिपोर्ट

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की रिपोर्ट एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 2018

के मुताबिक, 2017 में अधिकांश अंतरराष्ट्रीय प्रवासी भारत से थे।

- भारत के बाद चीन और बांग्लादेश के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या सबसे ऊपर थी।
- 2017 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का एक तिहाई हिस्सा एशिया से था।
- 2017 में भारत (17 मिलियन) के सबसे बाहरी प्रवासियों के बाद चीन (10 मिलियन) और बांग्लादेश (7.5 मिलियन) था।

3. भारत ने क्यूएस एशिया रैंकिंग 2019 में अपनी रैंकिंग को दोगुना किया

- क्वाकक्वेल्ली साइमंड्स द्वारा क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत ने रैंकिंग में अपनी उपस्थिति को दोगुना कर लिया है**.
- मुख्य भूमि चीन (112) और जापान (8 9) के बाद भारत में विश्वविद्यालयों और संस्थानों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या (75) है.
- **सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय** का मूल्यांकन एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है. आईआईटी-बॉम्बे उच्चतम रैंकिंग संस्थान बना हुआ है. यह एक स्थान परिवर्तित होकर 33 वें स्थान पर आ गया है.

शीर्ष 100 में अन्य भारतीय संस्थान हैं:

- IIT-दिल्ली 40 वें स्थान पर ,
- IIT-मद्रास 48 वें स्थान पर,
- भारतीय विज्ञान संस्थान - बैंगलोर, 50 वें स्थान पर,

4. दुनिया की सबसे बड़ी सहकारिता कंपनी बनी इफको

- 'वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनीटर' 2018 की रिपोर्ट में 'इफको' को विश्व की सहकारिता कंपनियों में पहला स्थान दिया गया है।
- वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनीटर रिपोर्ट का प्रकाशन इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस (ICA) तथा यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोआपरेटिव एंडसोशल एंटरप्राइजेज़ (यूरिक्स) द्वारा किया गया है।
- इफको के पास लगभग 36,000 सदस्य सहकारी समिति हैं और इसका कारोबार लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2017-18) का है।

5. भारत 9 वां सबसे मूल्यवान राष्ट्र ब्रांड बना

- ब्रैंड फाइनेंस, एक प्रमुख ब्रांड मूल्यांकन और रणनीति परामर्श द्वारा जारी 'राष्ट्र ब्रांड्स 2018' नामक एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने शीर्ष 50 मूल्यवान राष्ट्रीय ब्रांडों में से नौवां रैंक हासिल किया है.
- पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भारत 8 वें स्थान पर था, ब्रांड वैल्यू में 5% की बढ़ोतरी के बावजूद 9 वें स्थान पर पहुंच गया.
- यूएस 25,899 अरब डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ सूची में सबसे ऊपर है जो पिछले वर्ष से 23% बढ़ी है.
- चीन 12,779 अरब डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे स्थान पर है. चीन के ब्रांड वैल्यू में पिछले वर्ष से 25% की वृद्धि देखी गई।

6. **जापानी पासपोर्ट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, भारत 81वां स्थान पर**
    - हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 के मुताबिक जापान के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे शक्तिशाली नाम दिया गया है।
    - भारतीय पासपोर्ट को 81वें स्थान पर रखा गया है।
    - हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पावर रैंकिंग 2018 में शीर्ष 3 देश : जापान, सिंगापुर, जर्मनी।
7. सरकार ई-भुगतान अपनाने में भारत 28वें स्थान पर है: सर्वेक्षण
    - सर्वेक्षण के अनुसार, भारत ई-भुगतान अपनाने के लिए 2018 की कुल रैंकिंग में 28 वें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन इसे डिजिटल आधारभूत संरचना पहुंच और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर और अधिक कार्य करने की जरूरत है।
    - नॉर्वे 73-देश के समूह की रैंकिंग में प्रमुख स्थान पर है, इसके बाद फ्रांस और डेनमार्क का स्थान है।
8. अधिकतम औसत AUM के साथ राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर: AMFI
    - एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया (AMFI) के आंकड़ों के अनुसार,अधिकतम प्रवेश और प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (AUM) के साथ राज्य के लिए चार्ट में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया.
    - महाराष्ट्र के लिए, यह 10.35 लाख करोड़ रुपये पुरे भारत के लगभग 41.1%, तक पहुंच गया. इसके बाद दिल्ली के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए 1.76 लाख करोड़ रुपये हैं.

सितम्बर / अगस्त

1. जोधपुर ए1 श्रेणी में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है: सफाई रिपोर्ट
    - रेलवे, कोयला, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, पियुष गोयल ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा आयोजित स्टेशन स्वच्छता पर एक रिपोर्ट जारी की है।

ए1 श्रेणी स्टेशन (75 में से):

- पहला: जोधपुर / उत्तर-पश्चिमी रेलवे
- दूसरा: जयपुर / उत्तर-पश्चिमी रेलवे
- तीसरा: तिरुपति / दक्षिण-मध्य रेलवे।

ए श्रेणी स्टेशन (कुल 332 में से):

- पहला: मारवार / उत्तर पश्चिमी रेलवे
- दूसरा: फुलेरा / उत्तर-पश्चिमी रेलवे
- तीसरा: वारंगल / दक्षिण-मध्य रेलवे।

क्षेत्रीय रेलवे रैंकिंग हैं:

- उत्तर पश्चिमी रेलवे
- दक्षिण मध्य रेलवे
- पूर्वी तट रेलवे।

2. **एसबीआई भारत का सबसे देशभक्ति ब्रांड है: सर्वेक्षण**
    - यूके स्थित ऑनलाइन मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स फर्म यूगोव द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश का सबसे बड़ा ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) सबसे देशभक्ति ब्रांड माना गया है।
    - एसबीआई के बाद टाटा मोटर्स, पतंजलि, रिलायंस जियो और बीएसएनएल का अनुसरण किया जाता है।

- वित्तीय क्षेत्र में, एसबीआई 47% उत्तरदाताओं के साथ चार्ट का नेतृत्व करता है, जो इसे देशभक्ति ब्रांड के रूप में सबसे ज्यदा माना जाता है, इसके बाद 16% के साथ एलआईसी का स्थान है।

3. **केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल (बेंगलुरु) दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ हवाई अड्डा:**
   - यात्रियों की संख्या में वास्तविक वृद्धि के संदर्भ में केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) 2018 की पहली छमाही में दुनिया के दूसरे सबसे तेजी से बढ़ते हवाई अड्डे के रूप में उभरा है।
   - छह महीने की अवधि के दौरान इसमें 1,58,50,352 फ्लायर दर्ज किए गए हैं।
   - केवल टोक्यो के हनेदा इंटरनेशनल ने केआईए के विकास को बेहतर बना दिया है।
   - रिपोर्ट रूट्स ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो वैश्विक स्तर पर विमानन की गुणवत्ता और मानकों पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनी है।
   - नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को छठे स्थान पर रखा गया है जबकि हैदराबाद यात्रियों की वास्तविक वृद्धि के मामले में 17 वें स्थान पर है।

4. **दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ने जारी की**
   - भारतीय तेल निगम (आईओसी) भारत की रैंकिंग में ऊपर है जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है।
   - अमेरिका स्थित खुदरा कंपनी, वॉलमार्ट सूची में सबसे ऊपर है।
   - सूची में शीर्ष 3 कंपनियां हैं:
     - 1. वॉलमार्ट (यूएसए),
     - 2. राज्य ग्रिड (चीन),
     - 3. साइनोपेक समूह (चीन)।

5. **कर्नाटक अक्षय ऊर्जा में सबसे ऊपर है: आईईईएफए रिपोर्ट**
   - यूएस आधारित इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय बाजार है।
   - यह तमिलनाडु से आगे है जो काफी समय से भारत का सबसे अच्छा नवीकरणीय बाजार रहा है।

6. **जीएसटी के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में हरियाणा शीर्ष राज्य**
   - हरियाणा जीएसटी के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में अन्य राज्यों में सबसे ऊपर है और देश में ई-वे बिलों का चौथा सबसे ज्यादा उत्पादक भी है।

7. **भारत परिवार की स्वामित्व वाली व्यापार सूची पर तीसरा स्थान है: सीएसआरआई रिपोर्ट**
   - विश्व में परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है, जिसमें 111 कंपनियां हैं कुल बाजार पूंजीकरण 839 अरब डॉलर हैं।

     ध्यान दें:

     भारत 121 कंपनियों के साथ चीन तथा 159 फर्मों के अमेरिका के काफी नज़दीक है।

   रिपोर्ट क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआरआई) द्वारा प्रकाशित की गई है।

जुलाई/जून

1. **ईज ऑफ डुइंग बिजनस में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर:**
   - एक सर्वेक्षण के मुताबिक, आंध्र प्रदेश को व्यवसाय करने के लिए सबसे आसान भारतीय राज्य के रूप में स्थान दिया गया है।
   - इस सूची में आंध्र प्रदेश के बाद उसके पड़ोसी राज्य तेलंगाना को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
   - वहीं हरियाणा तीसरे तो झारखंड और गुजरात क्रमश: चौथे और पांचवे पायदान पर है।
   - ये रैंकिंग भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रोमोशन(DIPP) ने जारी की है।
2. **भारत विश्व की 6 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: विश्व बैंक**
   - 2017 के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिससे फ्रांस सातवें स्थान पर पहुंच गया है।
   - फ्रांस 2.582 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले 2017 के अंत में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) $ 2.597 ट्रिलियन था।
   - दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान।
3. **नाइजीरिया ने** सबसे ज्यादा गरीबों वाले देश के रूप में भारत को पीछ छोड़ दिया: **ब्रुकिंग्स रिपोर्ट**
   - अमेरिका स्थित थिंक टैंक, ब्रुकिंग्स द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक गरीबी में लगातार गिरावट के साथ भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों का देश नहीं है।
   - अध्ययन के मुताबिक, नाइजीरिया ने पहले से ही 2018 की शुरुआत में सबसे ज्यादा गरीबों वाले देश के रूप में भारत को पीछ छोड़ दिया है, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जल्द ही नंबर 2 स्थान ले सकता है।
4. **भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है: सर्वेक्षण**
   - वैश्विक विशेषज्ञों के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत यौन उत्पीड़न के उच्च जोखिम और गुलाम श्रम में मजबूर होने के कारण महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है।
   - अफगानिस्तान और सीरिया देश थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन में महिलाओं के मुद्दों पर 550 विशेषज्ञों के सर्वेक्षण के बाद दूसरा और तीसरा स्थान पर हैं, इसके बाद सोमालिया और सऊदी अरब देश हैं।
5. **हेल्थकेयर एक्सेस में भारत का 145 वां स्थान: लांसेट रिपोर्ट**
   - लैंसेट अध्ययन के मुताबिक भारत 195 देशों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और पहुंच के मामले में 145 वें स्थान पर है।
   - 2016 में, भारत की हेल्थकेयर एक्सेस और गुणवत्ता 41.2 पर रही (1 99 0 में 24.7 से ऊपर)।
   - भारत चीन (48), श्रीलंका (71), बांग्लादेश (133) और भूटान (134) के पीछे है।
   - 2016 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और गुणवत्ता के उच्चतम स्तर वाले शीर्ष 3 देश: आइसलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड्स।
6. **भारत दुनिया का 6 वां सबसे धनी देश है: अफ्रसिया बैंक**
   - अफ्रेशिया बैंक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के मुताबिक, भारत दुनिया का छठा सबसे धनी देश है जहां कुल संपत्ति 8,230 अरब डॉलर है।
   - अमेरिका, 62,584 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर देश है।
   - शीर्ष 6 सबसे धनी देश: अमेरिका ($ 62,584 बिलियन), चीन ($ 24,803 बिलियन), जापान ($ 1 9,522 बिलियन), ब्रिटेन (9, 9 1 अरब डॉलर), जर्मनी (9,660 अरब डॉलर), भारत ($ 8,230 बिलियन)।

7. **भारत बना एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चौथी सबसे बड़ी शक्ति**
    - एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों में भारत **चौथी** सबसे प्रमुख शक्ति है।
    - यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के थिंकटैंक द लोवी इंस्टीट्यूट दवारा जारी की गई है।
    - सूचकांक में शीर्ष तीन देश हैं - यूएस, चीन और जापान।
8. **भारत दुनिया में शीर्ष पांच रक्षा व्यय करने वालों में से एक**
    - स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2017 में दुनिया के पांच सबसे बड़े सैन्य व्यय करने वालों में से एक है।
    - भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के चलते अपनी सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ावा दिया है।
    - अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और रूस के बाद भारत 5वें स्थान पर था, और ये सभी देश द्वारा विश्व का कुल सैन्य खर्च 60% है।
    - चीन एशिया में किसी अन्य शक्ति की तुलना में अपनी सेना पर कहीं ज्यादा खर्च करता है।
9. **भारत 2017 में प्रेषण के उच्चतम प्राप्तकर्ता: विश्व बैंक**
    - विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2017 में 69 बिलियन डॉलर के साथ प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान बनाए रखा है।
    - 2016 में यह 429 अरब अमेरिकी डॉलर से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
    - इसके बाद चीन (64 अरब डॉलर), फिलीपींस (33 अरब डॉलर), मेक्सिको (31 अरब डॉलर), नाइजीरिया (22 अरब डॉलर), और मिस्र ($ 20 बिलियन) का स्थान हैं।
10. **भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है: आईएमएफ**
    - भारत अब 2017 में 2.6 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
    - भारत ने इस स्थिति पर फर्म खड़े होने के लिए फ्रांस को विस्थापित कर दिया।
    - अप्रैल 2018 के लिए अपने विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा डेटा जारी किया गया था।
    - आगे की पांच अर्थव्यवस्थाएं **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम** हैं।
11. **भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता**
    - भारत दुनिया में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है।
    - स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसयूएफआई) के मुताबिक, भारत ने जापान से आगे बढ़कर फरवरी 2018 में दुनिया का क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने का लक्ष्य रखा है।
    - चीन दुनिया में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है।
    - पहले 2017 में, भारत ने अमेरिका को पीछे कर कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था।
12. **भारत छठा सबसे अमीर देश है:** न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट
    - न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 10 सबसे प्रतिष्ठित देशों की सूची में 8,230 अरब डॉलर के कुल धन के साथ छठा सबसे धनी देश है।
    - प्रमुख 3 सबसे धनी देश - **अमेरिका, चीन और जापान**
13. **भारत कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश:** डब्ल्यू.एस.ए. रिपोर्ट
    - वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यू.एस.ए.) द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2017

में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बनने के लिए अमेरिका को पीछे छोड़ा है।

- कच्चे इस्पात के प्रमुख 2 सबसे बड़े उत्पादक: **चीन** सबसे बड़ा उत्पादक और **जापान** दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक है।

14. निवेश हेतु भारत पांचवा सबसे आकर्षक बाजार:

पी.डब्ल्यू.सी. सर्वेक्षण

- ग्लोबल कंसल्टेंसी पी.डब्ल्यू.सी. के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत निवेश के लिए पांचवां सबसे आकर्षक बाजार और वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर आशा के रूप में उभरा है।
- "अमेरिका वैश्विक निवेश के लिए सबसे ऊपर है, इसके क्रम में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन और जर्मनी का स्थान है।
- चौथे स्थान पर अमेरिका है। "भारत ने वर्ष 2018 में पांचवां सबसे आकर्षक बाजार बनकर जापान को पीछे छोड़ा,"।

बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता

दिसम्बर

1. वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के वास्तविक जीडीपी में 7.2% की वृद्धि का अनुमान : मूडीज आउटलुक

- भारत में मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस की वार्षिक बैंकिंग सिस्टम आउटलुक ने चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के लिए देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में क्रमश: 7.2% और 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है.
- अपने बैंकिंग सिस्टम दृष्टिकोण में, वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि विकास निवेश वृद्धि और मजबूत खपत से प्रेरित होगा. यह भी कहा गया है कि परिचालन वातावरण मजबूत होगा, मजबूत आर्थिक विकास द्वारा समर्थित है.

2. अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने पी.एम.ई.ए.सी. से इस्तीफा दे दिया

- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (पी.एम.ई.ए.सी.) से इस्तीफा दे दिया है। सरकार द्वारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।
- उन्हें पी.एम.ई.ए.सी. के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था जो भारत सरकार को विशेष रूप से प्रधान मंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए गठित एक गैर-संवैधानिक, गैर-स्थायी और स्वतंत्र निकाय है।
- परिषद का नेतृत्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बिबेक देब्राय ने किया है।
- छह सदस्यीय परिषद में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री शामिल हैं: बिबेक देब्राय (अध्यक्ष), श्री रतन पी. वाताल (सदस्य सचिव), राथिन रॉय (अंशकालिक सदस्य), आशीमा गोयल (अंशकालिक सदस्य), और शामिका रवि (अंशकालिक सदस्य)।

3. ए.डी.बी. ने भारतीय विकास पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2019 के लिए 7.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा

- एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास का अनुमान 7.3 प्रतिशत और 2019-20 के लिए 7.6 प्रतिशत रखा है।

4. आई.ओ.बी. ने बेसल III अनुपालन बॉन्ड के माध्यम से 300 करोड़ रुपये एकत्र किए

- राज्य-स्वामित्व वाले इंडियन ओवरसीज बैंक (आई.ओ.बी.) ने कहा कि उसने बेसल III अनुपालन बॉन्ड जारी करके 300 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

नोट:

- बेसल III बैंकिंग क्षेत्र के भीतर विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सुधारों के एक सेट के साथ एक अंतरराष्ट्रीय नियामक ढांचा है।
- वैश्विक बेसल III पूंजी नियमों का अनुपालन करने के लिए, बैंकों को अपनी पूंजी नियोजन प्रक्रिया में सुधार और मजबूती की आवश्यकता है।

5. स्विफ्ट इंडिया ने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अरुंधती भट्टाचार्य को नियुक्त किया

- स्विफ्ट इंडिया ने पूर्व एस.बी.आई. प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
- स्विफ्ट इंडिया प्रमुख भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और स्विफ्ट (विश्वव्यापी इंटरबैंक वित्तीय दूरसंचार संस्था) का संयुक्त उद्यम है।
- भट्टाचार्य पूर्व बैंकर एम.वी.नायर का स्थान लेंगे, जो कंपनी के साथ पांच साल पूरा करने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं।
- किरण शेट्टी स्विफ्ट इंडिया के सी.ई.ओ. हैं।

6. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने कामकाजी महिलाओं के लिए बचत बैंक खाता खोला

- 12 दिसंबर 2018 को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए बचत बैंक खाता शुरू किया।
- बचत खाते को 'एडवांटेज वूमेन औरा सेविंग एकाउंट' कहा जाएगा जो कि कामकाजी महिलाओं के लिए है, जिनमें स्वयं-नियोजित महिलाएं शामिल हैं जो शिक्षक, पेशेवर या घर से व्यवसाय करती हैं।

महत्वपूर्ण बातें

- खाते के 5 प्रकार हैं - रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नम और टाइटेनियम - और खाताधारक को विभिन्न विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करता है।
- बैंक ने बचत खाता प्रस्ताव के अपने समूह में पहली बार 'मैग्नम' को एक संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया है।
- खाताधारकों को हवाई और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी क्रमश: 40 लाख रूपये और 10 लाख रुपये है।

7. सेबी ने आई.टी.पी. का नाम 'इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफार्म' के रूप में बदल दिया

- शेयर बाजार पर स्टार्ट-अप को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, बाजार नियामक सेबी प्रस्तावों के एक नए सेट के साथ सामने आया है जो अधिक निवेशक श्रेणियों की अनुमति देता है, शेयरहोल्डिंग मानदंडों को कम करता है और व्यापारिक राशि को कम करता है।
- इस संबंध में, सेबी ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म (आई.टी.पी.) के ढांचे में बदलावों को प्रस्तुत किया है, जिसने अगस्त 2015 में इसे लागू किए जाने के बावजूद इसमें ज्यादा तनाव नहीं दिखा है।
- प्रस्तावित परिवर्तनों में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म (आई.टी.पी.) का नाम बदलना शामिल है जो नियामक इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफार्म (आई.जी.पी.) जैसी लिस्टिंग के लिए बनाया था।

8. सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 10% से 14% तक अपने योगदान में बढ़ोतरी की है

- कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में सरकार के योगदान को मौजूदा 10 प्रतिशत से 14% मूल वेतन में बढ़ाने का फैसला किया है।
- हालांकि, न्यूनतम कर्मचारी योगदान 10% पर रहेगा।
- मंत्रिमंडल ने 10% की सीमा तक कर्मचारियों के योगदान के लिए आयकर अधिनियम के 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी।
- वर्तमान में, सरकार और कर्मचारी प्रत्येक एन.पी.एस. में 10% मूल वेतन का योगदान करते हैं।
- सरकार ने एन.पी.एस. को पूरी तरह से कर मुक्त करने का फैसला किया है, जो इसे भविष्य निधि योजना के बराबर बना देता है।

- उसने सेवानिवृत्ति पर वापस लेने वाले एन.पी.एस. कॉर्पस के हिस्से पर लागू होने वाले आयकर को मुक्त करने का निर्णय लिया है।
- वर्तमान में, योजना से बाहर निकलने के दौरान, 60% कॉर्पस निकाला जा सकता है और निकाले जाने की राशि का 20% कर योग्य है। इस हिस्से को अब कर मुक्त कर दिया गया है।
- एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एन.पी.एस. नियमों में नवीनतम बदलाव वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2,840 करोड़ रुपये के राजकोष होगा।

एनपीएस के बारे में

- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) एक सरकारी प्रायोजित पेंशन योजना है।
- यह सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में शुरू की गई थी।
- हालांकि, 2009 में, यह सभी वर्गों के लिए खोली गयी थी।
- यह योजना ग्राहकों को अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान करने की अनुमति देती है।
- सेवानिवृत्ति पर, ग्राहक एकमुश्त में कॉर्पस का एक हिस्सा वापस ले सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुरक्षित करने के लिए एक वार्षिक वेतन के लिए शेष कॉर्पस का उपयोग कर सकते हैं।

नियामक

- एन.पी.एस. को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा शासित और प्रशासित किया जाता है।

आयु सीमा –

- वर्तमान में, 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच कोई भी भारतीय स्वेच्छा से एन.पी.एस. में शामिल हो सकता है।

पी.आर.ए.एन.

- प्रत्येक एन.पी.एस. ग्राहक को 12-अंकों का अद्वितीय नंबर वाला कार्ड जारी किया जाता है जिसे स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या या पी.आर.ए.एन. कहा जाता है।

एन.पी.एस. दो स्तरों में संरचित है

- टीयरI और टीयरII
- टीयर I वह प्राथमिक खाता है जिसे ग्राहक को टियर II खाते को खोलने में सक्षम होने के लिए खोलना होता है।
- टीयर I में जब तक ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता तब तक कोई रकम निकाली नहीं की जा सकती है।
- टीयर II में ग्राहक किसी भी समय रकम निकाल सकता है जब भी वह चाहे।

9. ई.सी.बी. ने 'टिप्स' टारगेट इंसटेंट पेमेंट सेटलमेंट शुरू किया

- यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने यू.एस. और एशियाई तकनीकी दिग्गजों द्वारा भीड़ वाले क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की उम्मीद करते हुए पहली पैन-यूरोज़ोन तत्काल भुगतान सेवा शुरू की।
- तथाकथित टी.आई.पी.एस. – टारगेट इंसटेंट पेमेंट सेटलमेंट 19-राष्ट्र यूरो क्षेत्र में उपभोक्ताओं और व्यवसायों को ऑनलाइन और वास्तविक विश्व लेनदेन से जुड़ी सामान्य समस्याओं के बिना, केवल सेकंड में धन भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देगा।
- यह सेवा गुगल, ऐप्पल, अमेज़ॅन या चीन के अलीबाबा और टेनेंट द्वारा प्रदान की गई "डिजिटल वॉलेट" के लिए एक सीधी चुनौती है, जो संपर्क रहित, सुपर-फास्ट ऑनलाइन भुगतान प्रदान करती है और लोकप्रियता में विस्फोटक का काम कर चुकी है।
- ई.सी.बी. ने कहा कि टी.आई.पी.एस. शुरू में यूरो क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, बैंक या व्यापार के लिए खुलेगा लेकिन भविष्य में दूसरे देशों और मुद्राओं में विस्तार किया जा सकता है।

10. सी.ए.जी. राजीव मेहर्षि को लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया

- नियंत्रक और महालेखा जनरल राजीव मेहर्षि को संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ ऑडिटर, सी.ए.जी. का उपाध्यक्ष बना गया है।
- संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ ऑडिटर में संयुक्त राष्ट्र और उसके एजेंसियों के बाहरी लेखा परीक्षकों का समावेश होता है।
- वर्तमान में, पैनल में 11 देश - भारत, जर्मनी, चिली, कनाडा, फ्रांस, इटली, फिलीपींस, घाना, इंडोनेशिया, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
- वर्तमान में, पैनल की अध्यक्षता ब्रिटेन के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।
- पैनल ने न्यूयॉर्क में अपनी वार्षिक बैठक 3 से 4 दिसंबर 2018 तक आयोजित की।
- पैनल ने ब्रिटेन के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक और कार्यकाल (2019) के लिए पैनल के अध्यक्ष के रूप में भी चुना।
- नवंबर-दिसंबर 2019 में पैनल की अगली बैठक बॉन, जर्मनी में आयोजित की जाएगी।

नवम्बर

1. **शापूरजी पल्लोनजी देश की पहली बड़े पैमाने वाली अस्थाई सौर परियोजना**
   - • भारत की पहली बड़े पैमाने वाली अस्थाई सौर परियोजना उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा के साथ रिहंद बांध पर 150 मेगावाट वाली परियोजनाओं की सौर ऊर्जा निगम भारतीय नीलामी में पहला ब्लॉक जीतने वाली शापूरजी पल्लोनजी है।
   - अधिकारियों ने बताया कि शापूरजी पलोनजी ने प्रति माह 3.29 रुपये के टैरिफ उद्धृत 50 मेगावॉट के लिए रिवर्स नीलामी जीती।
   - सौर ऊर्जा निगम (एस.ई.सी.आई.) के एक अधिकारी ने कहा, "यह इस तरह के पैमाने पर देश की पहली अस्थाई सौर परियोजना है।"

नोट:

- रिहांद बांध, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैले तालाब के साथ रिहांद नदी पर स्थित विस्तार क्षेत्र और कृत्रिम झील के साथ देश का सबसे बड़ा जलाशय है।
- शापूरजी पल्लोनजी समूह निर्माण, रियल एस्टेट, कपड़ा, इंजीनियर सामान, घरेलू उपकरण, शिपिंग, प्रकाशन, बिजली, और जैव प्रौद्योगिकी में रूचि के साथ भारत में एक व्यापार समूह है।

2. **सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियों को उधार देने के लिए एन.बी.एफ.सी. की स्थापना की योजना बनाई**
   - खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल के अनुसार; सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) की स्थापना की योजना बनाई है।
   - इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने के अपने प्रयास के हिस्से के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्त पोषित करना है।
   - मंत्री ने कहा; वह इस एन.बी.एफ.सी. की स्थापना पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श लेंगी। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
   - मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सालाना 1 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 7,000 करोड़ रुपये) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) आकर्षित कर रहा है।

3. **बिहार राज्य के राजमार्गों को सुधारने के लिए भारत एवं ए.डी.बी. ने 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए**

- भारतीय सरकार और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने बिहार राज्य के राजमार्गों में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

4. **आई.आई.एफ.सी.एल. द्वारा इन्फ्रा निधिकरण को बढ़ावा देने के लिए ए.डी.बी. ने 300 मिलियन डॉलर का ऋण देगा**
   - भारत और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने राज्य संचालित भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) का समर्थन करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जो बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करता है।
5. **सरकार एवं ए.डी.बी. ने तमिल नाडु में पानी, स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए 169 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए**
   - केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के कम से कम 10 शहरों में जलवायु-तन्यक जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 169 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
6. **ए.डी.बी. एवं भारत ने हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत ट्रांसमिशन का समर्थन करने के लिए 105 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए**
   - एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) और भारत सरकार ने राज्य एवं राष्ट्रीय ग्रिड में जल विद्युत आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में ट्रांसमिशन सिस्टम उन्नयन को वित्त पोषित करने के लिए 105 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
7. **प्रधान मंत्री ने ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की**
   - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग में एक कार्यक्रम में ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की।
   - इसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कारोबार करने के लिए सबसे आसान स्थानों में से एक बनाना है।
   - प्रधान मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत को कम से कम संभव समय में 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सुधार करना आवश्यक है।

उद्देश्य -

   - इस चुनौती का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन और अन्य अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर अभिनव विचारों को आमंत्रित करना है।
   - ग्रैंड चैलेंज के लिए मंच स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है।

नोट:

   - 31 अक्टूबर 2018 को जारी विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डी.बी.आर., 2019) में भारत ने 2017 में 100वें स्थान से 23 पदों की छलांग लगाकर विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए 190 देशों के बीच 77 वां स्थान हासिल किया।
   - सरकार द्वारा निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत ने पिछले दो वर्षों में 53 पदों और पिछले चार वर्षों में 65 पदों से अपनी रैंक में सुधार किया है।

8. **दूसरी तिमाही जी.डी.पी. वृद्धि 7.5-7.6 प्रतिशत तक धीमी होने की संभावना: रिपोर्ट**
   - एस.बी.आई. शोध रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले तीन महीने की अवधि में 7.5-7.6 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, मुख्य रूप से ग्रामीण मांग में मंदी के चलते।
   - 2018-19 की अप्रैल-जून तिमाही में निरंतर कीमतों (2011-12) में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8.2 प्रतिशत थी।

- इसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण मांग को धीमा करने के कारण, दूसरी तिमाही सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) वृद्धि 7.3-7.4 प्रतिशत हो सकती है।

9. भारत की जी.डी.पी. सीमांत रूप से धीमा होने की संभावना, लेकिन 2019 और 2020 में 7.5% पर मजबूत रहेगी: ओ.ई.सी.डी.

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के अनुसार, 2019 और 2020 में 7.50% के करीब भारत की आर्थिक वृद्धि कुछ हद तक धीमी रहेगी लेकिन मजबूत रहेगी।
- 2017-18 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) 6.7% बढ़ गया।
- बाजार की कीमतों पर ओ.ई.सी.डी. परियोजनाएं जी.डी.पी. 2018 में 7.5% से बढ़कर वर्ष 2019 में 7.3% और 2020 में 7.4% हो जाएगी।

10. कैनरा बैंक ने 113वां संस्थापक दिवस मनाया

- कैनरा बैंक ने 19 नवंबर 2018 को 113वां संस्थापक दिवस मनाया।
- 1906 में अमेम्बल सुब्बाराव पाई द्वारा मैंगलोर में कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी। यह देश के सबसे पुराने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है।
- स्थापना दिवस के दौरान, केनरा बैंक ने एक उन्नत कॉल सेंटर सुविधा "कॉल कैनरा" का उद्घाटन किया।
- कुछ सी.एस.आर. पहल के साथ बैंक ने बैंकिंग बिजनेस आउटलेट (बिजनेस पत्राचार मॉडल) लॉन्च किया। बैंक ने कर्मचारियों के सदस्यों को क्रच सुविधा भी स्थापित की।
- केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।
- टी. एन. मनोहरन कैनरा बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

11. सिद्धार्थ रथ स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस के नए एम.डी. और सी.ई.ओ. हैं

- सिद्धार्थ रथ ने स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस के प्रबंध निदेशक और सी.ई.ओ. के रूप में कार्यभार संभाला है।
- एस.बी.एम. बैंक (भारत) में शामिल होने से पहले, रथ एक्सिस बैंक के साथ कॉर्पोरेट, लेनदेन बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के समूह कार्यकारी और अध्यक्ष के रूप में थे।

12. एन.पी.सी.सी. अब एक मिनीरत्न कम्पनी है

- **राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड** को केंद्र सरकार द्वारा मिनिरत्न श्रेणी -1 की स्थिति से सम्मानित किया गया है।
- एन.पी.सी.सी. को मिनीरत्न स्थिति का सशक्तिकरण कंपनी को अधिकारों के प्रतिनिधिमंडल को बढ़ाकर तेजी से निर्णय लेने में मदद करेगा।
- एन.पी.सी.सी., जल संसाधन आर.डी. और जी.आर. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'बी' सी.पी.एस.ई., आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणन भी प्रदान किया गया है।

एन.पी.सी.सी. के बारे में

- 1957 में स्थापित एन.पी.सी.सी., एक प्रमुख निर्माण कंपनी है जो देश के आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कार्य करती है।

कंपनी 2009 -10 के बाद से लगातार लाभ कमा रही है, पिछले छह सालों से सकारात्मक नेटवर्थ है और 11,833 करोड़ रुपये की बढ़ी आदेश पुस्तक स्थिति के साथ महत्वाकांक्षी व्यापार योजना है।

13. अखिलेश रंजन नए प्रत्यक्ष कर कानून कार्यबल के संयोजक नियुक्त किए गए

- • सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अखिलेश रंजन को कार्यबल का संयोजक नियुक्त किया – इसे केंद्र द्वारा एक नया प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करने के लिए स्थापित किया गया।
- कार्यबल के अन्य सदस्य अपरिवर्तित रहते हैं।
- वह सितंबर 2018 में सेवानिवृत्त अरबिंद मोदी का स्थान लिया है।

14. बाबा कल्याणी समिति ने सेज़ नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

- भारत की मौजूदा सेज नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित बाबा कल्याणी नेतृत्व समिति ने 19 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य, उद्योग एवं नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

उद्देश्य - समिति के उद्देश्य थे

- सेज नीति का मूल्यांकन करने और इसे डब्ल्यू.टी.ओ. संगत बनाने के लिए,
- सेज़ में खाली भूमि के उपयोग को अधिकतम करने के उपायों का सुझाव देना,
- अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर सेज़ नीति में बदलाव का सुझाव देना
- तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे, राष्ट्रीय औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र और खाद्य और वस्त्र पार्क जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ सेज नीति का विलय करना ।

समिति के सुझाव

- समिति का सुझाव है कि अगर भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर बनने जा रहा है तो प्रतिस्पर्धात्मकता और सेवाओं के निर्माण के मौजूदा माहौल को बुनियादी प्रतिमान बदलाव करना पड़ सकता है।
- आई.टी. और आई.टी.ई.एस. जैसे सेवा क्षेत्र द्वारा देखी गई सफलता को स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं, कानूनी, मरम्मत और डिजाइन सेवाओं जैसे अन्य सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना है।
- भारत सरकार ने अपने प्रमुख 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र से 100 मिलियन नौकरियां बनाने और सकल घरेलू उत्पाद का 25% हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इसके अलावा, सरकार 2025 तक विनिर्माण मूल्य को 1.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने की योजना बना रही है।
- हालांकि, विकास दर में भारत को आगे बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए मौजूदा नीति ढांचे के मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- साथ ही, नीति को प्रासंगिक डब्ल्यू.टी.ओ. नियमों के साथ संकलित करने की आवश्यकता है।

15. भारत और चीन ने डबल टैक्सेशन टावरेंस संधि में संशोधन किया

- वित्त मंत्रालय के अनुसार, भारत और चीन ने द्विपक्षीय कर संधि में संशोधन किया है जो सूचना के आदान-प्रदान की अनुमति देकर कर चोरी को रोकने में मदद करेगा।
- भारत सरकार और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 26 नवंबर, 2018 को दोहरे कराधान से बचने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (डी.टी.ए.ए.) में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम की है ।

नोट:

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के तहत, भारत चोरी के निवारण के लिए जानकारी के आदान-प्रदान के लिए आय के दोहरे करों से बचने के लिए एक विदेशी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ एक समझौते में प्रवेश कर सकता है।

16. इंडसइंड बैंक ने भारत का पहला इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड 'नेक्सट' (Nexxt) प्रस्तुत किया

- इंडसइंड बैंक ने इंडसइंड बैंक नेक्सट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है – यह बटनों के साथ भारत में पहला इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड है।
- कार्ड ग्राहकों को एक प्वाइंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) टर्मिनल पर तीन भुगतान विकल्पों की सुविधा प्रदान

करता है - क्रेडिट, 4 अवधि विकल्पों (6, 12, 18 और 24 महीने) के साथ ई.एम.आई. में लेनदेन को परिवर्तित करना या संचित रिवार्ड पॉइंट्स का उपयोग कार्ड पर एक बटन दबाकर कर सकते हैं।

- यह कार्ड डायनेमिक्स इंक के साथ साझेदारी में बनाया गया है, जिसका मुख्यालय पिट्सबर्ग यू.एस.ए. में है, और डिजाइन एवं वस्तु कुशल, बैटरी संचालित भुगतान कार्ड बनाती है।

17. सितंबर में 8 आधारभूत संरचना क्षेत्रों की वृद्धि 4.3% तक धीमी हुई

- इस साल सितंबर में आठ आधारभूत संरचना क्षेत्रों की वृद्धि में 4.3 प्रतिशत की कमी आई, जो पिछले चार महीनों में सबसे कम है, क्योंकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट आई है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, उर्वरक में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, सीमेंट में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और बिजली उत्पादन में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- हालांकि, कोयले की वृद्धि में 6.4 प्रतिशत की गिरावट, रिफाइनरी उत्पादों में 2.5 प्रतिशत की गिरावट और इस्पात क्षेत्र में 3.2 प्रतिशत तक की गिरावट आई।
- समीक्षाधीन महीने में कच्चे तेल का उत्पादन 4.2 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस में 1.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
- पहले, सबसे कम वृद्धि दर मई 2018 में थी जब मूलभूत क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत का विस्तार हुआ ।

नोट:

- कोयले, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, सीमेंट और बिजली के आठ बुनियादी ढांचे क्षेत्रों में पिछले साल सितंबर में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- इन आठ क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के वजन का 40 प्रतिशत से अधिक शामिल है।

18. अक्टूबर में निर्यात 17.86 प्रतिशत बढ़ा

- इस साल अक्टूबर में भारत का निर्यात 17.86 प्रतिशत बढ़कर 26.98 अरब डॉलर हो गया है।
- वाणिज्य मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा, पिछले साल अक्टूबर में भारत का निर्यात 22.8 9 बिलियन डॉलर था।
- स्वस्थ विकास दर्ज करने वाले क्षेत्रों में पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, रसायन, फार्मा और रत्न और आभूषण क्षेत्र शामिल हैं।
- चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान, निर्यात 13.27 प्रतिशत बढ़कर 191 अरब डॉलर हो गया।
- मंत्रालय ने कहा, अक्टूबर के दौरान आयात भी 17.62 प्रतिशत बढ़कर 44 अरब डॉलर हो गया। अक्टूबर में तेल आयात 52.64 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

19. सरकार नेताजी सुभाषचंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी करेगी

- सरकार **नेताजी सुभाषचंद्र बोस** द्वारा पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी करेगी।
- वित्त मंत्रालय ने 75 रुपये का सिक्का जारी करने के संबंध में अपने निर्देशों के साथ एक अधिसूचना जारी की है।
- 30 दिसंबर, 1943 को, बोस, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना (आई.एन.ए) की स्थापना की थी, ने पोर्ट ब्लेयर सेल्युलर जेल में पहली बार तिरंगा फहराया था।
- स्मरणीय 75 रुपये का सिक्का 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबे, और 5 प्रतिशत निकल एवं जस्ता से बना होगा, और इसका वजन 35 ग्राम होगा।
- इस सिक्के की पृष्ठभूमि पर पोर्ट ब्लेयर सेल्युलर जेल में ध्वज को सलाम करते हुए 'नेताजी सुभाषचंद्र बोस' का चित्र होगा।

20. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11 नवंबर, 2018 को 100 वर्ष का हुआ

- **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** ने 11 नवंबर, 2018 को मुंबई में अपना **100वां स्थापना दिवस** मनाया।
- 11 नवंबर, 1919 को स्थापित, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन मुंबई में महात्मा गांधी ने किया था।
- भारतीय डाक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंक द्वारा जारी एक कॉफी टेबल बुक 'ए सेंचुरी ऑफ ट्रस्ट' का विमोचन किया।
- इस अवसर पर बैंक ने दो प्रकार के डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एक नया मोबाइल बैंकिंग ऐप और एम.एस.एम.ई क्षेत्र के लिए ऋण हेतु एक वेब और टैब-सक्षम मॉड्यूल भी लॉन्च किए।

21. आई.डी.एफ.सी फर्स्ट बैंक नए वर्ष से परिचालन आरंभ कर सकता है

- **आई.डी.एफ.सी बैंक** के साथ कैपिटल फर्स्ट के एकीकरण के बाद गठित नई इकाई **आई.डी.एफ.सी फर्स्ट बैंक** नए वर्ष से परिचालन प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
- सूत्रों ने कहा, "उम्मीद की जा रही है कि विलय के बाद गठित नया बैंक जनवरी से परिचालन शुरू करेगा।"
- आई.डी.एफ.सी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के शेयरधारकों और लेनदारों ने क्रमश: अक्टूबर और नवंबर में लेनदेन को मंजूरी दे दी थी।
- आई.डी.एफ.सी बैंक ने 25 अक्टूबर को कहा था कि बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक को अपना नाम बदलकर 'आई.डी.एफ.सी फर्स्ट बैंक लिमिटेड' करने के आवेदन को मंजूरी दे दी है।
- विलय के बाद, आई.डी.एफ.सी बैंक के प्रबंध निदेशक और सी.ई.ओ राजीव लाल, नई इकाई के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
- कैपिटल फर्स्ट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वी. वैद्यंथन, जो एक अनुभवी बैंकर भी हैं, नई इकाई के एम.डी. और सी.ई.ओ बनेंगे।

22. प्रधान मंत्री मोदी ने सिंगापुर में APIX टेक्नोलॉजी शुरू की

- प्रधान मंत्री **नरेंद्र मोदी** ने एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म **APIX** (Application Programming Interface Exchange) लॉन्च किया है, जो दुनिया भर में लगभग उन दो बिलियन लोगों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है जिनके पास अभी भी बैंक खाता नहीं है।
- प्रधान मंत्री मोदी ने सिंगापुर के उप-प्रधान मंत्री **टी. शनमुगरतम** के साथ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शुरू किया।
- प्रधान मंत्री मोदी सिंगापुर में प्रतिष्ठित फिनटेक महोत्सव को संबोधित करने वाले पहले नेता बने।
- APIX एक बैंकिंग प्रौद्योगिकी मंच है जो दुनिया भर में उन दो बिलियन लोगों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है जिनके पास अभी भी बैंक खाता नहीं है।
- हैदराबाद, कोलंबो और लंदन स्थित सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया, APIX एक परिष्कृत तकनीक है जो बोस्टन-मुख्यालय वर्तुसा द्वारा विकसित की गई है, यह विशेषकर छोटे बैंकों, टियर 3 और 4 हेतु दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए है।
- APIX बैंकों को 10 आसियान सदस्यों के साथ-साथ भारत जैसे प्रमुख बाजार और फिजी जैसे छोटे राष्ट्र सहित 23 देशों में उन व्यक्तियों तक पहुंच प्राप्त करने में सहयोग करेगा जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं।

23. अशोक चावला ने यस बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

- **यस बैंक** के अध्यक्ष **अशोक चावला** ने यह कहकर पद से इस्तीफा दे दिया कि वर्तमान परिवर्तन काल किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो अधिक समय और ध्यान दे सके।

24. ए.डी.बी ने देश में कुशल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ई.ई.एस.एल को 13 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया

- **एशियाई विकास बैंक** (ए.डी.बी) ने कहा है कि वह भारत में कुशल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ई.ई.एस.एल को 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा।

25. तमिलनाडु को राज्य आवास कोष लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली

- **तमिलनाडु** को बाजार नियामक **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड** (सेबी) से किफायती आवास खंड में निवेश आकर्षित करने हेतु अपने **राज्य आवास कोष** को लॉन्च करने की मंजूरी मिली।
- राज्य के उप-मुख्यमंत्री **ओ. पन्नीरसेल्वम** ने कहा कि - तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु अवसंरचना कोष की स्थापना की है जो प्रथम श्रेणी का वैकल्पिक निवेश कोष है।
- उप-मुख्यमंत्री ने कहा, "कोष निवेशकों को सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त लाभ प्रदान करने का एक सामाजिक प्रभाव कोष है।"

26. भारत वर्ष 2027 तक नई प्रौद्योगिकी में 14 लाख आई.टी. नौकरियां उत्पन्न करेगा: सिस्को अध्ययन

- **सिस्को** और **इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन** (आई.डी.सी) द्वारा एक संयुक्त अध्ययन में ज्ञात हुआ है कि भारत द्वारा वर्ष 2027 तक 1.4 मिलियन से अधिक नई आई.टी. नौकरियां उत्पन्न करने की संभावना है।
- यह मुख्य रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी) और बिग डेटा द्वारा संचालित नौकरियों में 46% वृद्धि को दर्शाता है, जो संगठनों द्वारा तलाशे जाने वाले डिजिटल रूपांतरण कौशल हैं।
- निष्कर्षों के अनुसार, सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर, मशीन लर्निंग (एमएल) डिजाइनर और आई.ओ.टी डिजाइनर जैसी नौकरियां आने वाले वर्षों में देश में सर्वाधिक मांग वाली नौकरियों में से होंगी।

27. फिच ने भारत के लिए 'BBB' रेटिंग बरकरार रखी है

- 15 नवंबर को **फिच रेटिंग** ने 'BBB' (सबसे न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग) पर भारत के स्थिर दृष्टिकोण को कायम रखते हुए सार्वभौमिक रेटिंग को बरकरार रखा है।
- एजेंसी ने कहा कि अर्थव्यवस्था वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान विमुद्रीकरण और जी.एस.टी के किसी भी दूरगामी प्रभाव को दूर कर देगी।
- "फिच ने वित्त वर्ष 19 में 7.3% की वृद्धि और वित्त वर्ष 20 में 7.5% की वृद्धि की भविष्यवाणी की।
- फिच ने 1 अगस्त, 2006 को एक स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की सार्वभौमिक रेटिंग को BB+ से BBB पर अपग्रेड किया था।
- फिच ने वर्ष 2004 में अपग्रेड के बाद से देश को पहली सार्वभौमिक रेटिंग दी।

28. सुनील मेहता समिति ने अधिक एन.पी.ए के लिए 'सशक्त भारत ए.एम.सी' का गठन किया

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान पर कार्य कर रहे एक बैंकर समिति के अध्यक्ष **सुनील मेहता** ने कहा कि अधिक खराब ऋणों के समाधान के लिए एक **परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी** (ए.एम.सी) का गठन किया गया है और इसे **सशक्त भारत परिसंपत्ति प्रबंधन** कहा जाएगा।
- उन्होंने यह भी कहा कि समिति अब संभावित निवेशकों को एक वैकल्पिक निवेश कोष (ए.आई.एफ) के लिए पहचानने की दिशा में कार्य कर रही है जो ए.एम.सी को निधि प्रदान करेगा।

नोट:

- सरकार ने जुलाई में बैंकिंग क्षेत्र में बोझ से निपटने के लिए प्रॉजेक्ट सशक्त के तहत पांच-स्तरीय रणनीति का प्रस्ताव दिया था, और पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी) के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था।
- प्रॉजेक्ट के तहत, समिति को 500 करोड़ रुपये से अधिक की गैर निष्पादित संपत्ति (एन.पी.ए) के समाधान के लिए ए.एम.सी और ए.आई.एफ को कार्यान्वित करना पड़ा।

- मेहता समिति में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई) सहित सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- ऐसे लगभग 200 बुरे ऋण (बैड लोन) वाले खाते हैं जो वर्तमान में 3.1 लाख करोड़ रुपये के कुल ऋण जोखिम के साथ प्रत्येक बैंकों के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक के देनदार हैं।

29. पी.एन.बी. ने भारत में ऑनलाइन लेनदेन में प्रमुख पी.एस.यू. बैंक का स्थान प्राप्त किया: फिनमिन रिपोर्ट

- पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) को भारत में कुल डिजिटल लेनदेन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पी.एस.यू. बैंक के रूप में स्थान दिया गया है।
- "डी.एफ.एस. (वित्तीय सेवाओं विभाग) के हालिया निष्कर्षों के आधार पर, पी.एन.बी. को भारत में डिजिटल लेनदेन में नंबर 1 पी.एस.यू. बैंक स्थान दिया गया है।
- पी.एन.बी. कथन के मुताबिक, 31 जुलाई, 2018 को डिजिटल लेनदेन में बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था।
- बैंक को '71' के स्कोर के साथ सरकार द्वारा 'बेहतर' के रूप में रेट किया गया है जो प्रदर्शन की सर्वोच्च श्रेणी है। "

30. सरकार वाहन चोरी की जांच के लिए माइक्रोडॉट्स तकनीक का उपयोग करेगी

- वाहन चोरी को खत्म करने के लिए, सरकार जल्द ही ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक नया मानक लॉन्च करेगी, जिसमें एक तकनीक का उपयोग शामिल है।
- इस तकनीक में, हजारों छोटे बिंदुओं के लेजर नक़्क़ाशी को पूरे वाहन पर वाहन पहचान संख्या के साथ स्प्रे किया जाएगा।
- इसमें उनके इंजन भी शामिल होंगे।
- इस तकनीक को माइक्रोडॉट्स कहा जाता है और इन बिंदुओं को हटाना लगभग असंभव है।

31. रिकवरी ने भारत में माइक्रोडॉट एंटी-चोरी तकनीक लॉन्च की

- रिकवरी ने भारत में अपनी माइक्रो टैग पहचान और वाहनों के लिए समाधान का पता लगाने की शुरूआत की।
- दक्षिण अफ्रीका स्थित कंपनी अपनी माइक्रोडॉट प्रौद्योगिकी का निर्माण और निर्यात करती है, जिसे वाहन अंकन और एक शक्तिशाली चोरी निवारक का प्रभावी रूप माना जाता है।
- माइक्रोडॉट एंटी-चोरी तकनीक वाहन पहचान संख्या (वी.आई.एन.) से जुड़ी व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) के साथ हजारों छोटे लेजर कणों का उपयोग करती है।
- माइक्रोडॉट्स को पूरे वाहन में स्प्रे किया जाता है।
- ये 1मिमी x 1मिमी बहुलक बिंदु हैं जिन्हें ढूंढना मुश्किल है।

32. पेट्रोलियम मंत्री ने एक वैकल्पिक, हरित परिवहन ईंधन के रूप में संपीड़ित जैव गैस को बढ़ावा देने के लिए एस.ए.टी.ए.टी. पहल शुरू की

- धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एक अभिनव पहल की शुरुआत की है।
- एस.ए.टी.ए.टी. शीर्षक, इस पहल का उद्देश्य विकासशील प्रयास के रूप में सस्ते परिवहन (एस.ए.टी.ए.टी.) के लिए एक सतत विकल्प प्रदान करना है जो वाहन-उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ किसानों और उद्यमि दोनों को लाभान्वित करेगा।

33. बी.ओ.बी., सी.डी.एस.एल. ने समझौते पर हस्ताक्षर किए

- बैंक ऑफ बड़ौदा ने सी.डी.एस.एल. कमोडिटी रिपोजिटरी (सी.सी.आर.एल.) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस प्रकार पंजीकृत/मान्यता प्राप्त गोदामों के लिए भंडार पारिस्थितिक तंत्र के तहत जमानती वित्त के लिए रिपोजिटरी प्रतिभागी बनने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है।

34. संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से एस.डी.जी. (सतत विकास लक्ष्य) के कार्यान्वयन पर अपनी वोलंटरी नेशनल रिव्यू (वी.एन.आर.) प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

- चूंकि 47 देश संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम पर सतत विकास (एच.एल.पी.एफ. 2018) के जुलाई 2018 सत्र में अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वी.एन.आर.) प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, 21 देशों ने एच.एल.पी.एफ. 2019 के दौरान वी.एन.आर. प्रस्तुत करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी है।
- सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत नियमित आधार पर सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) की प्रगति की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध है।

35. भारत के निर्वाचन आयोग को सुगम चुनावों के लिए राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया

- भारत के निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) ने नई दिल्ली में दो दिवसीय "सुगम चुनावों के लिए राष्ट्रीय परामर्श" का आयोजन किया है।
- कार्यक्रम "विकलांग व्यक्तियों" (पी.डब्ल्यू.डी.) पर विशेष ध्यान देने के साथ ई.सी.आई. ने अपने मिशन 'किसी भी मतदाता को पीछे मत छोड़ो' का पर ध्यान केंद्रित किया है।
- "पी.डब्ल्यू.डी. के समावेशन" का विषय ई.सी.आई. की रणनीतिक योजना 2016-2025 में विशेष ध्यान दिया गया है।
- इसके अलावा, "सुगम चुनाव" को इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोहों के लिए केंद्रीय विषय के रूप में अपनाया गया है।

36. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 5 राज्यों से 70% निर्यात की गणना की गई

- सर्वेक्षण भारत के इतिहास में पहली बार बताता है कि पांच राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना भारत के निर्यात में 70% हिस्सेदारी देते हैं।
- महाराष्ट्र (22.3%), गुजरात (17.2%), कर्नाटक (12.7%), तमिलनाडु (11.5) और तेलंगाना (6.4) शीर्ष पांच राज्य जो निर्यात में आगे हैं। इसके बाद हरियाणा (4.9%) है, जो कुल निर्यात में संचयी से 75 प्रतिशत तक पहुंच गया।
- आंकड़ों से यह भी पता चला कि भारत के 30 राज्यों में से 16 (29 राज्य + दिल्ली) में 97 प्रतिशत निर्यात है। उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश साथ मिलकर निर्यात का केवल 3 प्रतिशत बनाते हैं।

37. 2017 में, दिल्ली का आई.जी.आई. दुनिया के प्रमुख 20 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक

- 2017 में - यात्री यातायात के मामले में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आई.जी.आई.) हवाई अड्डा दुनिया के प्रमुख 20 व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है।
- एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ए.सी.आई.), विश्व हवाई अड्डे यातायात पूर्वानुमान भविष्यवाणी के अनुसार भारत वर्ष 2020 तक अमेरिका और चीन के बाद यात्री के मामले में तीसरा सबसे बड़े विमानन बाजार का प्रतिनिधित्व करेगा।

38. भारत में नीति अयोग और संयुक्त राष्ट्र ने 2018-2022 के लिए सतत विकास ढांचे पर हस्ताक्षर करें

- भारत में नीति अयोग और संयुक्त राष्ट्र ने 2018-2022 के लिए सतत विकास ढांचे पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा प्रतिबद्धता और प्रयासों का प्रतिबिंब है।

- यू.एन.एस.डी.एफ. 2018-2022 के कार्यान्वयन के लिए कुल नियोजित बजट व्यय लगभग 11000 करोड़ रुपये है।

39. सरकार कृषि कमोडिटी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी: एफ.एम. अरुण जेटली

- सरकार कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी जिनके पास 100 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की क्षमता है।
- देश का कृषि निर्यात वर्तमान में लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर हैं। "30 अरब अमरीकी डालर के मौजूदा निर्यात के मुकाबले भारत की कृषि निर्यात क्षमता 100 अरब अमेरिकी डॉलर जितनी अधिक है।
- भारत कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है।
- देश के कुल निर्यात का 10 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पादों की गणना करता है।
- भारत मुख्य रूप से चाय, कॉफी, चावल, अनाज, तंबाकू, मसाले, काजू, तेल भोजन, फल एवं सब्जियां और समुद्री उत्पादों का निर्यात करता है।

40. बेनामी लेनदेन सूचनार्थी पुरस्कार योजना, 2018

- आयकर विभाग द्वारा "बेनामी लेनदेन इंफॉर्मेंट्स रिवार्ड स्कीम, 2018" नामक एक नई इनाम योजना जारी की गई है।
- इस इनाम योजना का लक्ष्य लोगों को बेनामी लेनदेन और संपत्तियों के साथ-साथ ऐसे छिपे निवेशकों और लाभकारी मालिकों द्वारा इस तरह की सम्पत्ति पर अर्जित आय देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **1 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार** - कर विभाग ने दो इनाम योजनाओं की घोषणा की जिसके अंतर्गत किसी भी बेनामी लेनदेन या संपत्ति के बारे में 'विशिष्ट जानकारी' साझा करने वाले सूचनार्थियों को 1 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा।
- **5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार** - विदेश में रखे गए अनजान काले धन की जानकारी देने वाले सूचनार्थियों के लिए 5 करोड़ रुपये का इनाम दिया जा सकता है।
- **50 लाख रुपये तक का पुरस्कार** - विभाग की घोषणा के अनुसार, 'आयकर सूचनार्थी रिवार्ड पुरस्कार' में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत एक व्यक्ति को कर की पर्याप्त चोरी के बारे में विशिष्ट जानकारी देने के लिए 50 लाख रुपये तक का इनाम प्राप्त हो सकता है। यह भारत में आय या संपत्ति, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत क्रियाशील हैं।

41. राजनीतिक निधि में पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से **'चुनावी बॉन्ड' योजना** की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017 के बजट के दौरान केंद्रीय वित्त चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की थी।

उद्देश्य - राजनीतिक दलों और चुनावों के वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना

प्रमुख बिंदु –

- **ब्याज रहित दस्तावेज -** चुनाव बांड एक वचनबद्ध दस्तावेज होगा जैसे कि वचन पत्र और ब्याज-मुक्त बैंकिंग दस्तावेज।
- **मूल्यवर्ग -** 1,000, 10,000, 10 लाख, और 1 करोड़ रूपये के गुणांक में किसी भी मूल्य के चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं।
- **केंद्र -** भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी विशिष्ट शाखा से खरीदें जा सकते हैं।
- **के.वाई.सी. मानदंड अनिवार्य -** खरीदार को सभी विद्यमान के.वाई.सी. मानदंडों की पूर्ति के लिए और बैंक खाते से भुगतान करके केवल चुनावी बांड खरीदने की अनुमति दी जाएगी।
- **वैधता -** बांड केवल **15 दिनों** के लिए वैध होगा। **पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों** में **एक फीसदी से ज्यादा** वोट पाने वाले

पंजीकृत राजनीतिक दल ही बॉन्ड के जरिए चंदा प्राप्त कर सकेंगें।

- **एक वर्ष में केवल 4 महीने उपलब्ध -** बांड **जनवरी, अप्रैल, जुलाई** और **अक्टूबर** के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आम चुनाव के एक वर्ष के लिए निर्दिष्ट अतिरिक्त 30 दिनों का होगा।
- एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही बांड भर्ती किया जाएगा।
- भुगतानकर्ता का नाम इसमें शामिल नहीं होगा

42. प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना (पी.एम.वी.वी.वाई.) - यह भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से घोषित एक पेंशन योजना है।

उद्देश्य - वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अनिश्चित बाजार की स्थितियों के कारण ब्याज आय में भावी गिरावट के कारण 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों की रक्षा करना अनिवार्य है।

आयु सीमा –

न्यूनतम प्रवेश आयु: 60 वर्ष (पूर्ण)
अधिकतम प्रवेश आयु: कोई सीमा नहीं

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में 10 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 8% का आश्वासित लाभ प्रदान किया गया है।
- इस योजना के तहत न्यूनतम खरीद मूल्य **1,50,000 / - रूपये** के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 / - रूपये प्रति माह है।
- अधिकतम प्रति माह **5000 / - रुपये की अधिकतम पेंशन के लिए अधिकतम खरीद मूल्य 7,50,000** / - रूपये है।
- इस योजना को माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) से छूट दी गई है।
- यह योजना 3 मई 2018 तक आवेदन के लिए खुली है।

अक्टूबर

1. एस.बी.आई और हिताची पेमेंट ने संयुक्त उद्यम का गठन किया

- भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई) और हिताची पेमेंट सर्विस इंडिया (भुगतान समाधान प्रदाता) ने कार्ड स्वीकृति और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की स्थापना हेतु संयुक्त उद्यम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में एस.बी.आई की सर्वाधिक हिस्सेदारी होगी।
- हिताची पेमेंट सर्विस इंडिया हिताची ग्रुप, जापान के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

2. सेशेल्स ने विश्व के पहले सॉवरेन ब्लू बॉन्ड लॉन्च किए

- सेशेल्स गणराज्य ने दुनिया के पहले सॉवरेन ब्लू बॉन्ड लॉन्च किए हैं।
- सॉवरेन ब्लू बॉन्ड दीर्घकालिक समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया वित्तीय साधन है।
- बॉन्ड समुद्री संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग को वित्तपोषित करने के लिए पूंजी बाजारों के

उपयोग हेतु देशों की क्षमता को प्रमाणित करता है।

- बॉन्ड ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्र किए हैं।

3. आई.बी.एम ने अपनी सबसे बड़ी खरीद के तहत 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर में रेड हैट का अधिग्रहण किया

- अमेरिका की कंपनी आई.बी.एम ने सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद और ऋण सौदे के तहत अधिग्रहण किया है, जो कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है।
- ओपन सोर्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर निर्माता 'रेड हैट' की स्थापना 25 वर्ष पहले हुई थी, कंपनी का मूल्य व्यापार के अंत में लगभग 5 बिलियन डॉलर था।

4. कॉर्पोरेशन बैंक ने एम.एस.एम.ई पुरस्कार जीता

- कॉर्पोरेशन बैंक ने एसोचैम (Assocham) द्वारा स्थापित 'सर्वश्रेष्ठ एम.एस.एम.ई बैंक - विजेता 2018' पुरस्कार हासिल किया।
- '6वें एसोचैम एस.एम.ई उत्कृष्टता पुरस्कार - 2018' नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे।
- बैंक के डी.जी.एम शिवनंद हेब्बर को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने पुरस्कार प्रदान किया।
- यह पुरस्कार एस.एम.ई (छोटे और मध्यम उद्यम) क्षेत्र में बैंक के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया गया।

5. सतीश कुमार गुप्ता को पेटीएम पेमेंट बैंक का सी.ई.ओ नियुक्त किया गया

- अनुभवी बैंकर सतीश कुमार गुप्ता को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का प्रबंध निदेशक (एम.डी) और सी.ई.ओ नियुक्त किया गया है।
- जुलाई में रेणु सत्ती द्वारा सी.ई.ओ पद से इस्तीफा देने के बाद श्री गुप्ता की नियुक्ति हुई है।
- इससे पहले, श्री गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम में मुख्य उत्पाद अधिकारी और भारतीय स्टेट बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में कार्य किया था।

नोट:

- पेटीएम पेमेंट बैंक एक पृथक कंपनी है जिसमें संस्थापक विजय शेखर शर्मा की 51% हिस्सेदारी, वन97 कम्युनिकेशन की 39% हिस्सेदारी और शेष 10% हिस्सेदारी वन97 की सहायक कंपनी और शर्मा जी की है।
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नवंबर, 2017 में बैंक का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया था।
- यह वर्ष 2018 के अंत तक भारत भर में 100,000 से अधिक बैंकिंग आउटलेट लॉन्च करने के लिए तैयार है।

6. पी.एन.बी मेटलाइफ ने ए.आई संचालित ग्राहक सेवा ऐप 'खुशी' लॉन्च किया

- पी.एन.बी मेटलाइफ ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-संचालित ग्राहक सेवा ऐप 'खुशी' लॉन्च किया है।
- ऐप को एक ऐसा केंद्र बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो किसी भी समय, कहीं भी बीमा संबंधित जानकारी जैसे पॉलिसी की विशेषता, देय प्रीमियम विवरण प्रदान करने के अलावा फंड मूल्य और पोर्टफोलियो विवरण प्रदान करता है।
- खुशी ऐप में ग्राहक के प्रयोजन को समझने और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया प्रदान करने की क्षमता है।
- इससे पहले वर्ष 2016 में, पी.एन.बी मेटलाइफ ने 'conVRse', एक वर्चुअल रियलिटी (वी.आर) सर्विस

प्लेटफॉर्म के साथ-साथ 'eBranch', एक पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो सूचना के वास्तविक समय में हस्तांतरण को सक्षम बनाता था।

7. आई.एफ.सी ने अमेरिका और यूरोप में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मसाला बॉन्ड योजना शुरू की

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी) ने अमेरिका और यूरोप में अपनी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मसाला बॉन्ड योजना शुरू की है।
- इन बॉन्ड का उद्देश्य भारत में आई.एफ.सी की तेजी से बढ़ती निवेश गतिविधियों को वित्त पोषित करना है।
- मसाला बॉन्ड भारत के बाहर लेकिन भारतीय रुपये में जारी किए जाने वाले बॉन्ड हैं।
- आई.एफ.सी विदेशों में रुपया फंड जुटाने के लिए इनका उपयोग करती है और लाभ को निवेश के लिए भारत में पहुंचाती है।

नोट:

- मसाले शब्द का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी) द्वारा भारतीय संस्कृति और व्यंजन के लिए किया गया था।
- पहले मसाला बॉन्ड विश्व बैंक द्वारा समर्थित आई.एफ.सी ने नवंबर, 2014 में जारी किए थे जब इसने भारत में निधि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ बॉन्ड एकत्र किए थे।

8. पेटीएम ने जापान में 'पेपे' (PayPay) मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया

- पेटीएम ने सॉफ्ट बैंक और याहू जापान कॉर्पोरेशन के सहयोग से जापान में एक क्यू.आर आधारित स्मार्टफोन भुगतान निपटान सेवा शुरू की है।
- यह एक स्मार्टफोन आधारित निपटान सेवा है जो यूजरों को अपने 'पेपे' ('PayPay') वॉलेट में बैंक खाते से पैसा जमा करने और इसके माध्यम से भुगतान करने की अनुमति देती है।
- यह क्यूआरटेक (QRtech) की तर्ज पर बनाया गया है, जिसे इसने ग्राहकों को ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देने के लिए भारत में प्रभावी रूप से उपयोग किया है।

9. डब्ल्यू.ई.एफ. ने भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र शुरू किया

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) ने भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपने नए केंद्र की घोषणा की है।
- केंद्र महाराष्ट्र में स्थित होगा।
- यह नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
- यह सैन फ्रांसिस्को (यू.एस.), टोक्यो (जापान) और बीजिंग (चीन) के साथ डब्ल्यू.ई.एफ. के वैश्विक नेटवर्क के हिस्से के रूप में चेन-वन में चौथा केंद्र होगा।

10. सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में योग्य विदेशी संस्थाओं (EFEs) की भाग लेने की इजाजत दी

- वस्तु यौगिक बाजार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, नियामक सेबी ने विदेशी संस्थाओं को अपने एक्सपोजर को हेजिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भाग लेने की इजाजत दी है।
- वर्तमान में, विदेशी वस्तुओं को भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार में सीधे भाग लेने की अनुमति नहीं है, भले ही वे भारत से विभिन्न वस्तुओं को आयात या निर्यात करते हैं।
- बाजार नियामक ने कहा, ऐसी विदेशी संस्थाओं को योग्य विदेशी संस्थाओं (EFE) के रूप में जाना जाएगा। "
- मानदंडों के तहत, ऐसे ईएफई का भारतीय भौतिक कमोडिटी बाजारों में वास्तविक जोखिम होगा।
- ईएफई ऐसे देश में निवासी है जिसकी प्रतिभूतियां या वस्तु यौगिक बाजार नियामक सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता है।

- ऐसे ईएफई के लिए न्यूनतम शुद्ध संपत्ति की आवश्यकता 500,000 अमेरिकी डालर होगी।

11. मानव संसाधन विकास के लिए एसबीआई ने नेपाल के नेशनल बैंकिंग संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

- भारतीय स्टेट बैंक ने मानव संसाधनों के विकास के लिए काठमांडू स्थित नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट (एनबीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एसबीआई ने एनबीआई के साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करके एनबीआई के मानव संसाधनों के विकास के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद महत्वपूर्ण समझौता गठबंधन स्थापित करने के लिए तीन वर्षीय ज्ञापन समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- • एमओयू के तहत, एसबीआई की महत्वपूर्ण प्रशिक्षण इकाई एनबीआई के मानव संसाधन विभाग में परिवर्तन की सुविधा के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और विकास प्रदान करेगी।

12. सरकार ने छह महीने तक आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में राकेश शर्मा की नियुक्ति की

- राकेश शर्मा ने आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभारी पदभार संभाला है।
- 5 अक्टूबर को, सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में शर्मा की नियुक्ति की घोषणा की थी

13. 2027 तक भारत की शीतलन ऊर्जा खपत 2.2 गुना बढ़ने के आसार: रिपोर्ट

- एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 तक देश की शीतलन ऊर्जा मांग मौजूदा स्तर से 2 गुना बढ़ जाएगी और अगले दशक तक इसमें हस्तक्षेप 17 प्रतिशत तक कटौती करने में मदद कर सकता है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की तरफ से इंडो-जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा शुरू की गई रिपोर्ट को ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था (एईईई) के लिए गठबंधन द्वारा तैयार किया गया था।

14. स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस-भारत साइबर हमले की हानि ₹ 19 करोड़ हुई

- मॉरीशस-इंडिया स्टेट बैंक की मुंबई शाखा ने इस महीने की शुरुआत में साइबर हमले का सामना किया था। यह लगभग 1 9 करोड़ को छोड़कर लगभग सभी को ठीक करने में सक्षम रहा है।
- साइबर हमला 2 अक्टूबर को मुंबई के नरीमन प्वाइंट बैंक की शाखा में धोखाधड़ी वाले 'स्विफ्ट' भुगतान के माध्यम से हुआ था।

15. ऊर्जा कुशल उपकरणों के वितरण के लिए ईईएसएल डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन

- ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने सभी (उजाला) कार्यक्रम के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्4नत ज्योति के तहत ऊर्जा कुशल उपकरणों के वितरण के लिए डाक विभाग (डीओपी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एक बयान में कहा गया है कि ईईएसएल भारत भर में डाकघरों के डीओपी नेटवर्क के माध्यम से एलईडी रोशनी (बल्ब और ट्यूब रोशनी) और बीईई 5-स्टार रेटेड पंखों को वितरित करेगा।

16. लिबर्टी, आर्सेलर मित्तल की यूरोपीय संपत्तियों को खरीदेगा

- लिबर्टी आर्सेलर मित्तल की यूरोपीय संपत्तियों को हासिल करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह यूके में तेजी से निर्माण के बाद यूरोपीय मुख्य भूमि पर विस्तार के लिए प्रेरित है।
- संपत्तियों में रोमानिया और चेक गणराज्य के साथ-साथ मैसेडोनिया और इटली में रोलिंग मिलों में एकीकृत स्टीलवर्क शामिल हैं और यूरोप में लिबर्टी की स्टील रोलिंग क्षमता सालाना 10.5 मिलियन टन तक ले जाएंगी।

17. बैंक ऑफ बड़ौदा के एम.डी. और सी.ई.ओ. जयकुमार को एक वर्ष का अतिरिक्त समय मिला

- केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक (प्रबंध निदेशक) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) पी.एस. जयकुमार (12 अक्टूबर से) को एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया।

18. सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जी.पी.एफ. ब्याज दर 8% तक बढ़ा दी

- केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) और अन्य संबंधित योजनाओं के लिए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 0.4 प्रतिशत अंक से 8 प्रतिशत तक ब्याज दर में वृद्धि की है।
- वर्ष 2018-19 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जी.पी.एफ. पर ब्याज दर 7.6 प्रतिशत थी।
- ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे और रक्षा बलों के भविष्य निधि पर लागू होगी।

19. किश्तों में ऋणशोधन मुआवजे की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए आई.आर.डी.ए.आई. ने पैनल बनाया

- बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.आई.) ने किश्तों में सामान्य और स्वास्थ्य बीमा दावों के भुगतान की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक पैनल बनाया है।
- आई.आर.डी.ए.आई.एस. ने सुरेश माथुर, ई.डी. (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया।

20. विप्रो ने पूर्व एस.बी.आई. अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया

- विप्रो ने 1 जनवरी, 2019 से पहले एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य को नियुक्त किया था।

21. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में आर्थिक विकास के योगदान के लिए सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग में योगदान और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 के लिए सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

22. ए.डी.बी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2017 में सबसे बाहरी प्रवासी हैं

- एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में अधिकांश अंतरराष्ट्रीय प्रवासी भारत से थे, इसके बाद चीन और बांग्लादेश में हैं।
- रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वर्ष 2017 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में से एक तिहाई एशिया से थे। "वर्ष 2017 (17 मिलियन) में सबसे बाहरी प्रवासियों में भारत के प्रथम स्थान के बाद चीन (10 मिलियन) और बांग्लादेश (7.5 मिलियन) का स्थान था।

23. सितंबर में डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति बढ़कर 5.13% हो गई

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति (डब्ल्यू.पी.आई.) बढ़कर 5.13% हो गई है।
- 5.13 प्रतिशत मुद्रास्फीति दो महीने में सबसे अधिक है, और जुलाई में इस स्तर की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति जुलाई में 5.27 प्रतिशत पर देखी गई थी।

24. गीता गोपीनाथ को आई.एम.एफ. के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया

- गीता गोपीनाथ को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, जो इस पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी भारतीय बनी।

25. बी.एस.ई. सोने, चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना

- बी.एस.ई. सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने वाला देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया।
- आज तक, कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट केवल एम.सी.एक्स. और एन.सी.डी.ई.एक्स. पर उपलब्ध हैं, देश में दो विशेष कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज हैं।
- सेबी के पूर्णकालिक सदस्य, एस के मोहंती के अनुसार- दुनिया भर में कुल एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के अलावा, कमोडिटी डेरिवेटिव्स का आकार केवल 22 प्रतिशत है, जिनमें से भारत में 5-6 फीसदी का बहुत कम हिस्सा है।

26. अगस्त 2018 में कोर इन्फ्रा सेक्टर की वृद्धि दर 4.2% तक धीमी हो गई

- कच्चे तेल और उर्वरक उत्पादन में गिरावट के कारण अगस्त में भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र की वृद्धि दर 4.2 फीसदी तक पहुंच गई और कोयला, स्टील, रिफाइनरी उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के सुस्त प्रदर्शन रहा।

- एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार - आठ प्रमुख क्षेत्रों में से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) में 40 प्रतिशत योगदान दिया है, सीमेंट (5.37 प्रतिशत के वजन) ने पिछले साल इसी महीने के मुकाबले अगस्त में 14.3 फीसदी की उच्चतम वृद्धि दर्ज की थी, इसके बाद बिजली उत्पादन (1 9 .85 प्रतिशत का वजन) ने 5.4 प्रतिशत की बढ़त की है।

27. आई.एम.एफ., विश्व बैंक और डब्ल्यू.टी.ओ. ने पुनर्वितरण व्यापार एवं समावेशी विकास रिपोर्ट शुरू की

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन ने सामूहिक रूप से "पुनर्वितरण व्यापार एवं समावेशी विकास" रिपोर्ट शुरू की है।
- इस रिपोर्ट में सभी तीन अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने वैश्विक सेवा क्षेत्र के उदारीकरण की मांग की है, इस बात पर जोर देकर कहा है कि वर्तमान में इन सेवाओं के व्यापार में बाधाएं आधी शताब्दी पहले वस्तु में व्यापार करने वालों के बराबर थीं।

28. सिडबी ने राष्ट्रीय स्तर का उद्यमिता जागरूकता अभियान, उद्यम अखिलाषा शुरू किया

- महात्मा गांधी की जन्मदिवस की वर्षगांठ पर 02 अक्टूबर, 2018 लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने राष्ट्रीय स्तर का उद्यमिता जागरूकता अभियान, उद्योग अखिलाषा (उद्यम अभिलाषा) शुरू किया ।
- इसे 28 राज्यों में नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 115 आकांक्षा जिलों में पेश किया गया था और लगभग 15,000 युवाओं तक पहुंच गया है।

उद्यम अभिलाषा

- यह अभियान इन जिलों में महत्वाकांक्षी युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 800 से अधिक प्रशिक्षकों के कैडर को बनाएगा और मजबूत करेगा जिससे उन्हें उद्यमियों के चुनिंदा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- सिडबी ने सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एक विशेष प्रयोजन वाहन, (सी.एस.सी. एस.पी.वी.) के साथ भागीदारी की है जो सी.एस.सी. के माध्यम से अभियान को लागू करने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय द्वारा स्थापित है।

प्रचारक अभियान के उद्देश्यों में शामिल हैं: -

- महत्वाकांक्षी जिलों में ग्रामीण युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करना ताकि वे अपने उद्यम को स्थापित करने में सहायता कर सकें,
- पूरे देश में डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना,
- सी.एस.सी. वी.एल.ई. के लिए व्यावसायिक अवसर बनाना,
- महिलाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए इन महत्वाकांक्षी जिलों में महिला उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित करन
- प्रतिभागियों को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से बैंक योग्य बनने और क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करना ।

29. एस.बी.आई. ने ए.टी.एम. नकद निकासी सीमा 40,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति दिन कम कर दी है

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) ने घोषणा की है कि स्वचालित टेलर मशीनों (ए.टी.एम.) से नकद निकासी सीमा 31 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी रूप से 20,000 रुपये प्रति दिन कर दी गई है।
- वर्तमान में, ए.टी.एम. से एस.बी.आई. की नकद निकासी सीमा प्रति दिन 40,000 रुपये है।
- बैंक के अनुसार, यह ए.टी.एम. पर लेनदेन में धोखाधड़ी के साथ-साथ डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देते हुए शिकायतों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

30. मंत्रिमंडल में रबी फसलों की बढ़ोतरी एम.एस.पी. 21% तक बढ़ाई

- सरकार ने गेहूं, दालें और तिलहन सहित प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में वृद्धि की है, जो 2 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक है।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) ने छह शीतकाल में बोए जाने वाली या रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को मंजूरी दी।

- कुछ महीने पहले, सरकार ने खरीफ (गर्मी) फसलों के लिए उच्च एम.एस.पी. की घोषणा की थी, ताकि किसानों को उत्पादन लागत की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक मूल्य देने का वादा पूरा हो सके।
- कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सभी रबी फसलों के लिए एम.एस.पी. 50-112 प्रतिशत से उत्पादन की लागत से अधिक है।
- सी.सी.ई.ए. ने गेहूं एम.एस.पी. में 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि 2018-19 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के रबी मौसम के लिए 1,840 रुपये की मंजूरी दे दी है।

सितम्बर

1. सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 0.4 प्रतिशत तक राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दीं।

• वित्तीय वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होने और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें 0.4 प्रतिशत तक बढ़ा दीं।

विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें निम्नानुसार हैं:

योजनाएं	ब्याज दर (% में)
5 साल वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (भुगतान तिमाही)	8.7%
डाकघर बचत जमा	4%
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)	8%
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी)	8%
किसान विकास पत्र (परिपक्वता अवधि 112 महीने)	7.7%
सुकन्या समृद्धि अकाउं	8.5%
पांच साल की सावधि जमा	7.8%
पांच साल के डाकघर आवर्ती जमा	7.3%
डाकघर मासिक आय योजना (एमआईएस)	7.7%

2. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को मंजूरी दी

- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के नाम से पहचाने जाने वाली नई दूरसंचार नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करना और इस क्षेत्र में 4 मिलियन नौकरियां बनाना है।
- नीति के प्रारूप के मुताबिक, एनडीसीपी देश भर में 5 जी और ऑप्टिकल फाइबर जैसे किफायती दरों पर आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड में निवेश को बढ़ाने पर केंद्रित है।

विशेषताएं: नीति का लक्ष्य है

- प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना;
- 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 जीबीपीएस प्रदान करना;
- सभी अनावृत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना;

- डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करना;
- नई आयु कौशल के निर्माण के लिए दस लाख जनशक्ति प्रशिक्षित करना;
- आईटी पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार 5 बिलियन जुड़े उपकरणों तक करना;

3. सरकार ने वित्तीय समावेशन सूचकांक शुरु किया

- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआईआई) शुभारंभ किया।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सी.ई.ओ. के साथ वित्त मंत्री की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा बैठक के बाद सूचकांक शुरू किया गया था।
- सूचकांक में तीन मापदण्ड पैमाने होंगे; (i) वित्तीय सेवाओं तक पहुंच (ii) वित्तीय सेवाओं का उपयोग और (3) गुणवत्ता।
- एकल समग्र सूचकांक वित्तीय समावेशन के स्तर का एक स्नैप शॉट देता है जो मैक्रो नीति परिप्रेक्ष्य को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

4. अरुण जेटली ने एक घंटे के भीतर एम.एस.एम.ई. ऋण की मंजूरी देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शाखा में जाने की अनिवार्यता के बिना एक घंटे के भीतर ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को सक्षम करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया।
- वेब पोर्टल, www.psbloansin59minutes.com, एम.एस.एम.ई., वित्तीय सेवाओं के लिए 59 मिनट के भीतर 10 मिलियन रुपये तक के ऋण के लिए साधारण तौर पर मंजूरी प्रदान करेगा।
- पोर्टल केवल लघु उद्योग विकास बैंक, और पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.), बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक और इंडियन बैंक से ऋण अनुमोदन सुरक्षित करने के लिए है।

5. जी.एस.टी. जुर्माने के रूप में येस बैंक पर 38 करोड़ रुपये लगाए गए

- घरेलू प्रेषण में कथित उल्लंघन के लिए जी.एस.टी. विभाग को येस बैंक ने जुर्माने के रूप में 38 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

6. वित्त मंत्रालय ने मोबाइल ऐप "जन धन दर्शक" लॉन्च किया

- वित्त मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन के एक हिस्से के रूप में मोबाइल एप्लिकेशन जन धन दर्शक लॉन्च किया है।
- यह ऐप देश में किसी दिए गए स्थान पर वित्तीय सेवा टच पॉइंट का पता लगाने में आम लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग (डी.एफ.एस.), वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) ने वित्तीय समावेशन पहल के हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से जन धन दर्शक ऐप विकसित किया है।

7. ब्रिक्स बैंक मध्य प्रदेश में इन्फ्रा परियोजनाओं के लिए 525 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है

- ब्रिक्स देशों के नए विकास बैंक (एन.डी.बी.) ने मध्य प्रदेश को बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए 525 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है।
- एन.डी.बी. के निदेशक मंडल ने मध्य प्रदेश की प्रमुख जिला सड़क परियोजना द्वितीय और 350 पुलों के निर्माण और उन्नयन के लिए 175 मिलियन डॉलर के लिए 350 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।

8. फिच ने वित्त वर्ष 19 के लिए 7.4% से 7.8% तक भारत का जी.डी.पी. पूर्वानुमान बढ़ाया

- फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7.8 प्रतिशत कर दिया, जो पहले अनुमानित 7.4 प्रतिशत था।

9. सरकार ने 10 पीएसयू बैंकों में एमडी और सीईओ की नियुक्ति की

- इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ – पद्मजा चुंडरू
- सिंडिकेट बैंक के नए एमडी और सीईओ - मृतुन्जय महापात्रा
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - पल्लव महापात्रा
- आंध्र बैंक के नए एमडी और सीईओ - पच्चिकरिसमी
- देना बैंक के नए एमडी और सीईओ - कर्णम सेकर
- इलाहाबाद बैंक के नए एमडी और सीईओ - एसएस मल्लिकार्जुन राव
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ - एएस राजीव
- यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ - अतुल कुमार गोयल
- पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ - एस हरिसंकर
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ - अशोक कुमार प्रधान

10. आईपीपीबी ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए बजाज एलियाज के साथ साझेदारी की

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने अपने ग्राहकों के लिए उत्पादों के विस्तार करने के लिए बजाज एलियाज लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की।
- बीमा उत्पाद पहले 3250 एक्सेस पॉइंट्स के आईपीपीबी में उपलब्ध होंगे, धीरे-धीरे भारत के हर गांव, शहर और जिले में 155,000 डाकघरों तक विस्तृत हो जाएगे।
- बजाज एलियाज लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी पहली जीवन बीमा कंपनी है जिसने किसी नवीन बैंक के साथ गठन किया हो।

11. सरकार ने देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज करने का प्रस्ताव रखा है

- केंद्र सरकार ने बैंकों के कार्यकाल में सुधार लेन के लिए राज्य के बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के विलय का प्रस्ताव दिया ।
- बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएस जयकुमार ने कहा कि इन बैंकों के समामेलन में 4-6 महीने लग सकते हैं।

12. नाबार्ड ने 93 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 65,635 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया

- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक (नाबार्ड) ने सरकार की प्रमुख योजना प्रधान मंत्री कृषि सिंचई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत अब तक 93 प्राथमिकता सिंचाई परियोजनाओं के लिए 65,634.93 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दे दी है।

13. IPPB ने असंगठित खुदरा बिक्री के लिए भुगतान नेटवर्क बनाने हेतु FSS के साथ समझौता किया

- छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर समेत असंगठित खुदरा बिक्री के लिए उपभोक्ताओं के भुगतान के एक भुगतान स्वीकृति नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने फाइनेंसियल सॉफ्टवेयर और सिस्टम (FSS) के साथ भागीदारी की है।
- इस समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि माइक्रो-व्यापारी किसी भी चैनल - ऑनलाइन, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, आधार और आईपीपीबी खातों पर भुगतान स्वीकार कर सकें।

14. एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया

- एक्सिस बैंक ने 1 जनवरी से अमिताभ चौधरी को प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है, इस वर्ष के अंत में शिखा शर्मा यह पद से हट जाएगी।

15. विश्व बैंक उच्च मध्यम आय वाले देश में अपने संक्रमण का समर्थन करने के लिए भारत के लिए देश भागीदारी ढांचे को मंजूरी दी

- विश्व बैंक ने भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी पांच साल के ढांचे का समर्थन किया है, जिसके तहत कम मध्यम आय से लेकर उच्च-मध्यम आय वाले देश में अपने संक्रमण के लिए 25-30 अरब अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है।
- भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (सीपीएफ) का उद्देश्य संसाधन कुशल और समावेशी विकास, नौकरी निर्माण और अपनी मानव पूंजी के निर्माण जैसी कुछ प्रमुख विकास प्राथमिकताओं को संबोधित करते हुए उच्च मध्यम आय वाले देश में भारत के संक्रमण का समर्थन करना है।
- यह भारत के साथ लिखित पहली किसी देश के साथ साझेदारी है।

16. प्रधान मंत्री ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु -

- एयरटेल और पेटीएम के बाद भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाली आईपीपीबी तीसरी इकाई थी।
- आईपीपीबी को 17 अगस्त, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ, डाक मंत्रालय, संचार मंत्रालय के तहत की गई है।
- इसने 30 जनवरी, 2017 को दो पायलट शाखाएं खोलकर, एक रायपुर में और दूसरा रांची में ऑपरेशन शुरू किया।
- सुरेश सेठी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के एमडी और सीईओ हैं।
- आईपीपीबी 650 शाखाओं और 3,250 एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से उपलब्ध होगी

प्रमुख विशेषताऐं

- आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, भुगतान बैंक जमा में 1 लाख रुपये से अधिक नहीं स्वीकार कर सकते हैं और ऋण और बीमा प्रदान नहीं कर सकते हैं।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बचत खातों में 4 प्रतिशत ब्याज देगा ।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बैंकों से कम शुल्क पर विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान कर सकता है।
- आईपीपीबी क्यूआर कार्ड की एक और सेवा प्रदान करेगा । एक क्यूआर कार्ड की मदद से, आप अपने बैंक खाते तक पहुंच सकते हैं और खाता संख्या याद किए बिना लेनदेन कर सकते हैं।
- आईपीपीबी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ करार किया है और खाता धारकों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंक के एजेंट के रूप में काम करेगा।
- आईपीपीबी ने अपने ग्राहकों को बीमा प्रदान करने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ करार किया है।
- एटीएम सुविधा के लिए आईपीपीबी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ करार किया है।

खाते : **आईपीपीबी ग्राहकों के लिए तीन प्रकार के खातों की अनुमति देगा -**

- एक नियमित बचत खाता - नकद निकालने, पैसे जमा करने और आसान प्रेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- एक मूल बचत खाता - जो प्रति माह केवल चार नकद निकासी की अनुमति देगा।
- डिजिटल बचत बैंक खाता- जो उपयोगकर्ताओं को आईपीपीबी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना खाता खोलने की अनुमति देगा।

17. PayU को आरबीआई ने एनबीएफसी के रूप में काम करने की मंजूरी दी

• अग्रणी ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता **PayU** को एनबीएफसी के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है (कुछ आरबीआई अनुपालन के अधीन)।

18. एसबीआई ने अंशुला कांत को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अंशुला कांत को बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
- इस नियुक्ति से पहले, कांत बैंक के उप प्रबंध निदेशक थी । इस नियुक्ति के साथ अब एसबीआई में चार एमडी हैं - पीके गुप्ता, डीके खारा और अरजीत बसु।

19. Temasek, एनआईआईएफ (NIIF) मास्टर फंड में $ 400 मिलियन निवेश करने के लिए समझौता किया

- नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) ने सिंगापुर के संप्रभु निधि टेमासेक के साथ 400 मिलियन डॉलर तक के मास्टर फंड तक निवेश करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एनआईआईएफ ने कहा कि टेमासेक भी निवेश प्रबंधन कंपनी, नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का शेयरधारक बन जाएगा, लेकिन शेयर होल्डिंग के आकार का खुलासा नहीं किया गया ।

ध्यान दें:

- एनआईआईएफ, ₹ 40,000 करोड़ के प्रस्तावित कॉर्पस के साथ - जिसमें से केंद्र 49 प्रतिशत योगदान देगा - 2015 में सेबी नियमों के तहत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में बनाया गया था।
- भारत सरकार के अलावा, वर्तमान शेयरधारक अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए), एचडीएफसी समूह, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और एक्सिसबैंक हैं।

20. डीआरटी में मामलों को दर्ज करने के लिए मौद्रिक सीमा दोगुनी होकर 20 लाख हो गई

- सरकार ने गुरुवार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में ऋण वसूली आवेदन दाखिल करने के लिए आर्थिक सीमा को 20 लाख रुपये तक दोगुनाकर दिया।
- इस कदम का उद्देश्य डीआरटी में मामलों की लापरवाही को कम करने में मदद करना है।
- इस समय देश में 39 डीआरटी हैं।
- वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस तरह के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण रिकवरी ट्रिब्यूनल में ऋण की वसूली के लिए आवेदन दाखिल करनेके लिए 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सीमा बढ़ा दी है।
- नतीजतन, यदि कोई देय राशि 20 लाख रुपये से कम है तो बैंक या वित्तीय संस्थान या बैंक या वित्तीय संस्थानों का संघ डीआरटी से संपर्क नहीं कर सकता है।

21. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए है कि बैंक स्तर पर शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक लोकपालों को नियुक्त करें

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिये है जिनके 10 से अधिक बैंकिंग आउटलेट है कि एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त करें जिससेग्राहको की शिकायतों को बैंक स्तर पर ही हल किया जा सके।
- 'आंतरिक लोकपाल योजना, 2018' के अनुसार, आईओ ग्राहक शिकायतों की जांच करेगा जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से बैंक द्वारा खारिज किए गए हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियामक निरीक्षण के अलावा, आईओ योजना 2018 के कार्यान्वयन की निगरानी बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र द्वारा की जाएगी।
- "इससे पहले, आईओ योजना अर्द्ध औपचारिक व्यवस्था थी। अब, यह अनिवार्य कर दिया गया है। एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा, उनके निर्णय बैंक पर बाध्यकारी होंगे
- मई 2015 में, आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी थी, निजी ग्राहक सेवा अधिकारी, या आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के लिए निजी और विदेशी बैंकों का चयनकरें।
- इस योजना के अनुसार, आईओ के पास तीन से पांच वर्ष का कार्यकाल तय होगा, जो विस्तार योग्य नहीं है। उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- आईओ नियुक्त होने के बाद, उसे आरबीआई की अनुमति के बिना हटाया नहीं जा सकता है। उनका पारिश्रमिक बैंक के बोर्ड की ग्राहक सेवा उप-समिति द्वारा तय किया जाएगा।

22. राष्ट्रीय आवास बैंक ने केरल को 200 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की है

- केरल के बाढ़ प्रभावित राज्य के ग्रामीण इलाकों में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एवम शहरी इलाको में 6 लाख रुपये तक की आय वालो को राष्ट्रीयआवास बैंक (एनएचबी) ने 200 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता की घोषणा की है।
- यह पुनर्वित्त सुविधा प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से निर्माण / मरम्मत और घरों के नवीनीकरण के लिए ब्याज की रियायती दर की सुविधा प्रदान करेगी।

अगस्त

1. **88.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास बचत खाता है:**

नाबार्ड सर्वेक्षण - नाबार्ड अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) के अनुसार - 88.1 प्रतिशत परिवार ग्रामीण इलाकों में बचत खाते हैं।

- इस तरह के पहले सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रामीण परिवारों में, कृषि परिवारों ने गैर-कृषि से अधिक अर्जित किए हैं।
- सर्वेक्षण में 29 राज्यों में 245 जिलों को शामिल किया गया था जो टियर III में टियर VI शहरों में किया गया था।
- इसमें 40,327 परिवार और 187,000 लोग शामिल थे।

सर्वेक्षण की मुख्य हाइलाइट्स:

- ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय ₹ 96,708 थी।
- 48% कृषि परिवार हैं।
- 55 प्रतिशत कृषि घरों में बैंक खाता होने की सूचना दी गई है।
- 33% परिवारों ने एक से अधिक बचत खाते की सूचना दी।
- प्रति परिवार औसत बचत प्रति वर्ष 17,488 रुपये थी।
- इन घरों में से केवल 7.4% डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। 7.5% कम से कम तीन महीने में भुगतान करने के लिए चेक का उपयोग करते हैं ।
- उनमें से लगभग 24% कम से कम तीन महीने में एटीएम सेवाओं का उपयोग करते हैं।
- 50% से अधिक कृषि घरों में ऋणात्मकता का सामना करना पड़ रहा है।
- बीमा के तहत 26 प्रतिशत कृषि घरों और 25 प्रतिशत गैर-कृषि परिवारों को कवर किया गया पाया

ध्यान दें:

- ग्रामीण परिवारों के लिए पंजाब, हरियाणा और केरल शीर्ष 3 राज्य हैं जिनमें औसत मासिक आय 23,133 रुपये, 18,496 रुपये और 16, 9 27 रुपये है।
- उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मासिक आय 6,668 रुपये प्रति माह है।
- आंध्र प्रदेश में, आय के संबंध में उच्च व्यय मनाया गया था। इसलिए एक ग्रामीण परिवार को केवल 9 5 रुपये प्रति माह का औसत अधिशेष मिलता है।
- बिहार में एक परिवार 262 / माह रुपये रखता है। उत्तर प्रदेश में यह 315 रुपये / माह है।

2. **पीएनबी प्रमुख आईबीए अध्यक्ष चुने गए**
    - पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुनील मेहता को वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था।
    - दीनबंधू महापात्रा, प्रबंध निदेशक और सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया, को आईबीए के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।
3. **रिलायंस बाजार पूंजी में 8 ट्रिलियन रुपये पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है**

- मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) इस साल लगभग 38% बढ़ने के बाद 8 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई।
- बीएसई पर आरआईएल शेयर की कीमत 1.86% बढ़कर 1,269.70 रुपये हो गई, जो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़ों के बाद 8.05 ट्रिलियन पर अपनी मार्केट कैप पर चढ़ाई कर रही है। रिलायंस जियो ने स्वस्थ गति से ग्राहकों को जोड़ना जारी रखा ।

4. इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश में एफडीआई 23% बढ़कर 13 अरब डॉलर हो गया है

- आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई इस वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही के दौरान 23 प्रतिशत बढ़कर 12.8 अरब डॉलर हो गया।
- औद्योगिक नीति और संवर्धन डेटा विभाग के अनुसार, अप्रैल-जून 2017-18 में विदेशी निधि प्रवाह 10.4 बिलियन डॉलर था।
- चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अधिकतम विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में 2.4 बिलियन डॉलर की सेवाएं, 1.62 अरब डॉलर का व्यापार और दूरसंचार 1.5 9 अरब डॉलर शामिल हैं।
- सिंगापुर अप्रैल से जून तिमाही के दौरान 6.52 अरब डॉलर के साथ एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत था।

5. Google Tez अब Google पे है

- भारत के भुगतान बाजार में अपने बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, Google ने Google पेज़ में Google पेज़ को अपने भुगतान ऐप को दोबारा प्रस्तुत किया, नई सुविधाओं को पेश किया और नए टाई-अप के साथ अपना दायरा बढ़ाया।
- भारत के लिए Google की वार्षिक घटना में, तकनीकी जायंट ने निजी बैंकों के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की ताकि Google पे ग्राहकों को तत्काल अनुमोदित ऋण की सुविधा मिल सके।
- Google पे ऐप का उपयोग करके, ग्राहक जल्द ही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से ऋण प्राप्त कर पाएंगे।

6. आइडिया सेल्युलर, वोडाफोन इंडिया के साथ विलय हुआ

- आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया का विलय पूरा हो गया है, जिसमें 408 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार सेवा प्रदाता बनाया गया है।
- 12 निदेशकों (छह स्वतंत्र निदेशकों सहित) और कुमार मंगलम बिड़ला के अध्यक्ष के रूप में मर्ज किए गए इकाई "वोडाफोन आइडिया लिमिटेड" के लिए एक नया बोर्ड गठित किया गया है।
- कंपनियों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि बोर्ड ने बलेश शर्मा को सीईओ नियुक्त किया है।

7. एसबीआई ने एक एकीकृत भुगतान टर्मिनल एमओपीएडी (MOPAD) लॉन्च किया

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाजार हिस्सेदारी के पांचवें हिस्से के साथ सबसे बड़ा ऋणदाता, एक भुगतान मशीन लॉन्च करता है जो व्यापारियों को कार्ड से लेनदेन को क्यूआर कोड आधारित भुगतानों में सुविधाजनक बनाने के लिए कई विकल्पों को खत्म करने में मदद करेगा।
- एमओपीएडी (MOPAD) या मल्टी ऑप्शन पेमेंट स्वीसेप्टेंस डिवाइस नामक नया डिवाइस, एक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल है जो कार्ड के साथ यूपीआई, भारत क्यूआर और एसबीआई बडी वॉलेट के माध्यम से भुगतान स्वीकार करेगा,

जो अब तक भुगतान प्राप्त करने के लिए विभिन्न टूल्स की आवश्यकता है।

8. **परेश सुकुंकर ने एचडीएफसी बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इस्तीफा दे दिया**
    - एचडीएफसी बैंक के परेश सुक्तांकर ने देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है।
9. **एस गोपाकुमार यूनाइटेड इंडिया इन्सुरेंस के निदेशक और जीएम के रूप में शामिल हुए**
    - पब्लिक सेक्टर गैर-जीवन बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने एस गोपाकुमार को तत्काल प्रभाव से निदेशक और महाप्रबंधक के रूप में नियुक्ति की घोषणा की।
10. **मॉरीशस के SBM को सहायक के लिए मिली आरबीआई की स्वीकृति**
    - स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस (एसबीएम), द्वीप राष्ट्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक ऋणदाता, ने कहा है कि यह जल्द ही भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करेगा - पहले किसी भी विदेशी संस्थान द्वारा।
    - एसबीएम होल्डिंग्स सीईओ (भारत और पूर्वी अफ्रीका) मूसा हार्डिंग ने कहा कि बैंक 500 करोड़ रुपये से अधिक की स्टार्ट-अप पूंजी के साथ संचालन शुरू करेगा और दिल्ली, बेंगलुरू, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद और जयपुर में छह शाखाएं लॉन्च करेगा।
    - मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम में बैंक की मौजूदा शाखाएं हैं।
11. **एनएचएआई ने 25 करोड़ रुपये के ऋण के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया**
    - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 25,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ एक समझौता किया।
    - यह किसी भी इकाई को एसबीआई का उच्चतम दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण है और एनएचएआई को स्वीकृत सबसे बड़ा ऋण भी है।
12. **एस.बी.आई ने उच्च प्रावधानों पर 48.76 बिलियन रुपये की लगातार तीसरी तिमाही हानि दर्ज की**
    - **भारतीय स्टेट बैंक** (एस.बी.आई) ने अप्रैल-जून 2018 अवधि (पहली तिमाही) के लिए **75 बिलियन रुपये** की निवल हानि दर्ज दी, जो कि बॉन्ड में निवेश मूल्य की कमी के लिए बड़े प्रावधान और वेतन संशोधन एवं ग्रेच्युटी की बढ़ी सीमा के चलते परिचालन खर्च में वृद्धि के कारण लगातार तीसरी तिमाही हानि है।
    - देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने मार्च, 2018 तिमाही में 18 बिलियन रुपये का सबसे बड़ा तिमाही नुकसान और अप्रैल-जून 2017 (वित्त वर्ष 18 पहली तिमाही) में 20.05 बिलियन रुपये का निवल लाभ दर्ज किया था।
13. **इफको लुधियाना, पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगा**
    - पंजाब के लुधियाना जिले में 325 करोड़ रुपये की ग्रीनफील्ड खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए भारतीय उर्वरक सहकारी IFFCO स्पेनिश फर्म कांगेलैडोस डी नवरारा के साथ हाथ मिलाया है।
    - स्पेनिश फर्म कांगेलैडोस डी नवरारा त्वरित जमे हुए (आईक्यूएफ) प्रौद्योगिकी में अग्रणी है।
14. **एक्सिस बैंक ने आधार, आधारित लेनदेन के लिए आईरिस प्रमाणीकरण पेश किया**
    - एक्सिस बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेनदेन के लिए आईरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा पेश करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है।
    - इस सेवा के लिए एक ग्राहक को अपने आईरिस को टैबलेट पर स्कैन करने की आवश्यकता होती है।
    - यह आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया परेशानी मुक्त करके बैंक के वित्तीय समावेशन प्रयासों को बढ़ावा देगा और विशेष रूप से देश के ग्रामीण हिस्सों में उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल बैंकिंग तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।

15. जून में, औद्योगिक उत्पादन 7% तक बढ़ा

- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक - खनन, विनिर्माण, बिजली उत्पादन खंडों और कम आधार वृद्धि में उच्च उत्पादन के कारण औद्योगिक उत्पादन में जून में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापा गया औद्योगिक उत्पादन, जून 2017 में 0.3 प्रतिशत से अनुबंधित।
- आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल-जून 2018 के लिए संचयी वृद्धि पिछले साल की समान अवधि में 5.2 प्रतिशत थी, जब यह 1.9 प्रतिशत थी।

16. कॉसमॉस बैंक का सर्वर हैक हुआ; 2 दिनों में 94 करोड़ रुपये निकाले गये

- पुणे स्थित कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक ने डेबिट कार्ड भुगतान प्रणाली और स्विफ्ट लेनदेन पर मैलवेयर हमले सहित साइबर हमलों के कारण 94 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की सूचना दी है।
- 112 वर्षीय बैंक ने कहा कि कनाडा, हांगकांग सहित 28 देशों में स्थित विभिन्न एटीएम के माध्यम से 78 करोड़ रुपये वापस ले लिए गए थे।
- इसी तरह, बैंक ने कहा कि भारत में 2,800 डेबिट कार्ड लेनदेन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर 2.50 करोड़ रुपये निकाले गए थे।
- रिपोर्टों के अनुसार, 13.9 करोड़ रुपये को स्विफ्ट (वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सोसाइटी) लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।

17. एनपीसीआई ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ यूपीआई 2.0 लॉन्च किया

- भारत में सभी खुदरा भुगतानों के लिए संगठन, भारतीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), ने 16 अगस्त को अद्यतन एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) 2.0 लॉन्च किया।
- यूपीआई का नया संस्करण, मौजूदा और बचत खातों के अतिरिक्त, ग्राहकों को यूपीआई को ओवरड्राफ्ट खातों को लिंक करने देगा।
- ग्राहक तत्काल लेनदेन करने में सक्षम होंगे, और ओवरड्राफ्ट खाते से जुड़े सभी लाभ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- एक अन्य सुविधा ग्राहकों को भुगतान करने से पहले व्यापारियों द्वारा भेजे गए उनके चालान की जांच करने की अनुमति देगी।
- यह ग्राहकों को प्रमाण-पत्र देखने और सत्यापित करने में सहायता करेगा और जांच करेगा कि यह सही व्यापारी से आया है या नहीं।
- ग्राहक इनवॉइस में उल्लिखित राशि और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की पुष्टि करने के लिए पोस्ट का भुगतान कर सकते हैं।
- हस्ताक्षर किए गए इरादे और क्यूआर कोड के लिए, ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करते समय व्यापारियों की प्रामाणिकता की जांच कर पाएंगे।
- यह जानकारी के साथ उपयोगकर्ता को यह सूचित करने के लिए सूचित करेगा कि क्या व्यापारी यूपीआई व्यापारी सत्यापित है या नहीं।
- अप्रैल 2016 में यूपीआई संस्करण 1 लॉन्च किया गया था।

18. भारती एक्सा और एयरटेल पेमेंट बैंक जीवन ज्योति बीमा की पेशकश करेंगे

- भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सरकार द्वारा समर्थित जीवन बीमा योजना 'प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (पीएमजेजेबीवाई) की पेशकश करने के लिए गठबंधन किया है।
- यह गठबंधन ग्रामीण इलाके तक पहुंचने और बीमाधारक की सेवा करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाएगा।
- कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत में भारत के समर्थित जीवन बीमा योजना की पेशकश करने वाला पहला भुगतान बैंक भी बन गया है।

- भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस द्वारा प्रदान की गई योजना (PMJJBY) 330 रुपये प्रति वर्ष के मामूली प्रीमियम के साथ 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करता है और यह सभी मौजूदा या नए एयरटेल भुगतान बैंक बचत बैंक के खाता धारकों द्वारा जिनकी आयु 18- 50 के बीच है खरीदी जा सकती है।
- इस समझोते के तहत, 'प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' शुरू में देश भर में एक लाख एयरटेल भुगतान बैंकों पर ही उपलब्ध होगा।

19. TReDS पर लेनदेन करने के लिए HAL पहला पीएसयू बन गया: RXIL

- भारतीय रिसीवबल एक्सचेंज (आरएक्सआईएल) ने कहा कि; हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल) "ट्रेड्स प्लेटफार्म" पर लेनदेन करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है।
- एनएसई-सिडबी संयुक्त उद्यम के मुताबिक, टीआरईडीएस कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है।
- "हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म पर अपना पहला डिजिटलीकृत चालान छूट लेनदेन निष्पादित किया, जब उसने इस सप्ताह के शुरू में नासिक आधारित एमएसएमई (माइक्रो श्रेणी) विक्रेता नरेंद्र उद्योग द्वारा अपलोड किए गए डिजिटल चालान को स्वीकार किया," आरएक्सआईएल के एक बयान में कहा गया ।
- "यह प्लेटफार्मों में टीआरईडीएस पर लेनदेन करने वाला पहला पीएसयू एचएएल बनाता है।
- लेनदेन को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

20. आशीष कुमार भूटानी को प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना के सीईओ बने

- कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वरिष्ठ नौकरशाह आशीष कुमार भूटानी को प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है।
- असम-मेघालय कैडर के 1992 के बैच आईएएस अधिकारी भूटानी को 9 मई, 2020 तक पद पर नियुक्त किया गया है।
- 2016 में लॉन्च किया गया, पीएमएफबीवाई एक राष्ट्र एक योजना विषय के अनुरूप है।

जुलाई

1. **भारतीय स्टेट बैंक और नाबार्ड ने तेलंगाना में क्रेडिट के लिए समझौता किया**
   - **भारतीय स्टेट बैंक** और **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** ने तेलंगाना में संयुक्त देयता समूह के द्वारा जमानत मुफ्त क्रेडिट प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है।
   - दोनों बैंकों ने निजामाबाद, माड़क और वारंगल जिले से सात गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर वर्तमान वर्ष के दौरान 2,000 जे.एल.जी. को प्रोत्साहन देने और क्रेडिट जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. **जन लघु वित्त बैंक ने अपना संचालन शुरू किया**
   - जन स्माल फाइनेंस बैंक, पूर्व में एम.एफ.आई. - जनलक्ष्मी फाइनेन्शियल सर्विसेस ने 18 जुलाई 2018 से अपने वाणिज्यिक बैंकिंग संचालनों की अधिकारिक शुरूआत कर दी है।

- इस बैंक को इस वर्ष मार्च में लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ था, जिसके बाद इसे एक औपचारिक वाणिज्यिक शुरूआत के लिए अपने तंत्र को उन्नत बनाने में थोड़ा समय लगा।
- इस कायाकल्प के बाद, बैंक 19 राज्यों में फैली अपनी 157 शाखाओं के अतिरिक्त 402 अतिरिक्त सूक्ष्म-वित्त शाखाओं का प्रयोग करेगी।
- **अजय कनवाल जन स्माल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।**
- जन स्माल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय **बंगलुरू** में है।

3. **भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय साक्षरता पर किसानों को शिक्षित करने के लिए किसान मेला का आयोजन किया**
   - किसानों में वित्तीय साक्षरता लाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने देशभर की अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं पर किसान मेला का आयोजन किया।
   - यह किसान ग्राहकों के साथ संबंध विकसित करने, उनकी शिकायतों को दूर करने और उन्हें विभिन्न अधिकारों और बैंक की योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए एक प्रकार की पहली पहल है।
4. **नाबार्ड स्थापना दिवस – 12 जुलाई**
   - **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** ने राष्ट्र की सेवा में अपने **36 सालों को** पूरा किया है और **12 जुलाई को अपना 37 वां स्थापना दिवस** मनाया है।
   - नाबार्ड की स्थापना **बी. शिवरमन समिति की सिफारिशों पर** (संसद के अधिनियम 61, 1981 द्वारा) 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करके हुई थी।
   - **नाबार्ड का मुख्यालय : मुंबई** और **अध्यक्ष : हर्ष कुमार भनवाला**
5. **भारत यूरोपीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक का नया शेयरधारक बन गया है**
   - भारत अब यूरोपीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक का 69वां शेयरधारक बन गया है, जिससे बैंक के कार्यक्षेत्र में भारतीय कंपनियों के साथ अधिक संयुक्त निवेश का रास्ता खुल गया है।
   - भारत सरकार ने लंदन स्थित ई.बी.आर.डी. में सदस्यता के लिए दिसम्बर 2017 में आवेदन किया था।
   - बैंक ने अपने बयान में कहा कि ई.बी.आर.डी. के वर्तमान सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड ऑफ गर्वनर ने मार्च 2018 में सर्वसम्मति से भारत के आवेदन के पक्ष में मतदान दिया, और इस सप्ताह संपूर्ण सदस्यता प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
6. **भारत का पहला मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन नोएडा में होगा**
   - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2018 को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में नोएडा में देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज (एमओएक्स) क्षेत्र की आधारशिला रखी।
   - यूपी सरकार ने टेक ट्रेड विकसित करने के लिए यूपी निवेशकों के शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नोएडा के साथ एक समझौतेपर हस्ताक्षर किएथे जो राज्य में मोबाइल और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
7. जून में कोर क्षेत्र 6.7% बढ़ोतरी दर्ज की
   - जून में भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र की वृद्धि ने रिफाइनरी उत्पादों, कोयले और सीमेंट के बढ़ते उत्पादन पर 6.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की।
   - उच्च उत्पादन वाले अन्य कोर बुनियादी ढांचे क्षेत्रों में इस्पात, बिजली और उर्वरक शामिल हैं। दोनों क्षेत्रों, जहां उत्पादन गिर गया कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस हैं।

8. भारत एसटीए -1 स्थिति प्रदान करने के लिए अमेरिकी कदम का स्वागत करता है
    - भारत ने सामरिक व्यापार प्राधिकरण -1 (एसटीए - 1) देश की स्थिति प्रदान करने के अमेरिकी सरकार के फैसले का स्वागत किया है - यह एक कदम है जो व्यक्तिगत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना भारत में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों की संख्या के निर्यात के लिए योग्य होगा। ।
    - यह कदम रक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-यूएस व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग को और सुविधाजनक बनाएगा।
9. **सेबी ने यस बैंक को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए मंजूरी दी**
    - निजी ऋणदाता यस बैंक ने घोषणा की कि उसे म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अंतिम नियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
    - यह अनुमोदन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी के बाद है।
    - यस एसेट मैनेजमेंट (इंडिया), जो यस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अगले 6-12 महीनों में ऋण और इक्विटी बाजारों में स्पेक्ट्रम में फंड ऑफरिंग लॉन्च करेगी।
10. **बंधन बैंक ने चंद्रशेखर घोष को सीईओ, एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया:**
    - बंधन बैंक को मौजूदा एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष की तीन साल तक फिर से नियुक्ति के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली।
    - घोष बैंक के संस्थापक हैं और माइक्रो फाइनेंस उद्योग में 37 साल का अनुभव है।
    - बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है।
11. **चीन के बाहर उभरते बाजार में एचडीएफसी बैंक सबसे मूल्यवान बैंक:**
    - चीन के बाहर उभरते बाजार में एचडीएफसी बैंक रूस के सबरबैंक से सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है।
    - एचडीएफसी बैंक का मौजूदा बाजार पूंजीकरण 74 अरब डॉलर के मुकाबले 78.4 अरब डॉलर है।
    - चीनी बैंक उभरते बाजार में चोटी के आदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना 273.4 अरब डॉलर की मार्केट कैप के साथ सूची में शीर्ष पर है, इसके बाद चीन कंस्ट्रक्शन बैंक (225.1 अरब डॉलर) है।
    - वैश्विक स्तर पर, अमेरिका का जेपी मॉर्गन चेस $ 353 बिलियन की मार्केट कैप के साथ सबसे मूल्यवान बैंक है, इसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका 282 अरब डॉलर के सथ दुसरे स्थान पर है।
    - भारत के चार उधारदाता हैं जो अब दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक हैं।
    - एचडीएफसी बैंक के बाद, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (एचडीएफसी), कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थान है।
12. **परियोजना 'सशक्त' जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है:**
    - तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के तीव्र समाधान के लिए **सुनील मेहता समिति** ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के तनाव वाले ऋण के प्रस्ताव के लिए **एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी** के निर्माण की सिफारिश की है.
    - खराब ऋण प्रस्ताव पर सुनील मेहता समिति ने **देश की बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित संपत्तियों से निपटने के लिए पांच-प्रवृत रणनीति परियोजना 'सशक्त'** की सिफारिश की है. पांच-प्रवृत रणनीति में शामिल हैं:

      एसएमई प्रस्ताव प्रवेश, बैंक नेतृत्व वाले प्रस्ताव प्रवेश, AMC/AIF नेतृत्व वाले प्रस्ताव प्रवेश, NCLT/IBC प्रवेश और एसेट ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म

- मेहता समिति ने 50 से 500 करोड़ रुपये के बीच ऋण के लिए **बैंक लेड रेज़ोल्यूशन दृष्टिकोण** (**BLRA**) का प्रस्ताव दिया है. **BLRA** दृष्टिकोण के तहत, वित्तीय संस्थान 180 दिनों में एक प्रस्ताव योजना लागू करने के लिए लीड बैंक को अधिकृत करने के लिए एक अंतर-लेनदेन समझौते में प्रवेश करेंगे.

13. मंत्रिमंडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना का विस्तार मंजूरी दे दी है:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले तीन वर्षों (2019-20 तक) के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण की योजना को विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है।
- यह आरआरबी को न्यूनतम निर्धारित पूंजी को 9% की जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। यह एक मजबूत पूंजी संरचना और न्यूनतम आवश्यक स्तर सीआरएआर सुनिश्चित करेगा।
- आरआरबी संयुक्त रूप से केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों द्वारा क्रमशः 50%, 15% और 35% के अनुपात में साझा पूंजी के साथ स्वामित्व में हैं।

जून

1. अरजीत बसु को एस.बी.आई. के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

- सरकार ने अर्जित बसु को देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया।
- रजनीश कुमार के अध्यक्षता पद छोड़ने के बाद उनके स्थान पर पद ग्रहण करेंगे।
- अब, इसके बाद एस.बी.आई. के चार प्रबंध निदेशक होंगे।
- एस.बी.आई. अधिनियम के अनुसार, बैंक के चार प्रबंध निदेशक हो सकते है

2. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने संदीप बख्शी को सी.ओ.ओ. के रूप में नियुक्त किया

- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के सी.ई.ओ. संदीप बख्शी को पूर्ण निदेशक और मुख्य संचालन अधिकारी (सी.ओ.ओ.) के रूप में नियुक्त किया।

3. बी. श्रीराम को आई.डी.बी.आई. बैंक के सी.एम.डी. के रूप में नियुक्त किया गया

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक बी. श्रीराम को आई.डी.बी.आई. बैंक के एम.डी. और सी.ई.ओ. के रूप में तीन महीने की अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।
- उन्हें मौजूदा एम.डी. और सी.ई.ओ. महेश कुमार जैन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के उप गवर्नर के लिए चुना गया था।

4. वैश्विक स्तर पर एचडीएफसी पांचवीं सबसे बड़ी उपभोक्ता वित्तीय सेवा कंपनी: फोर्ब्स

- फोर्ब्स पत्रिका द्वारा संकलित सूची में 'उपभोक्ता वित्तीय सेवा श्रेणी' में आवास वित्त प्रमुख एचडीएफसी को वैश्विक स्तर पर 5 वीं सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है।
- अमेरिकन एक्सप्रेस इस श्रेणी में सबसे ऊपर है, जबकि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस सूची में एकमात्र अन्य भारतीय कंपनी (13 वें स्थान पर) है।
- उपभोक्ता वित्तीय सेवा श्रेणी में, एचडीएफसी का रैंक पिछले साल 7 वां स्थान से बढ़ गया है।

5. फिच ने एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा की व्यवहार्यता रेटिंग घटाई

- फिच रेटिंग्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर) को क्रमशः BB+' और 'BB' कर दिया है, जो

कमजोर संपत्ति की गुणवत्ता के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनकी कमजोर आंतरिक जोखिम प्रोफाइल और घटी कमाई के असर के चलते जोखिम में जाती प्रोफाइल को दर्शाता है।'

- वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बैंकों के मूल पूंजी बफर भी मध्यम झटके के लिए कमजोर दिखते हैं।

नोट:

- व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर) एक वित्तीय संस्थान की अंतर्निहित क्रेडिट योग्यता को मापती है और इकाई की असफल होने की संभावना पर फिच की राय को दर्शाती है।
- एसबीआई का एक-डाउन डाउनग्रेड बैंक की कमजोर कोर पूंजीकरण को लंबे समय तक संपत्ति की गुणवत्ता की समस्याओं और कमजोर कमाई से दर्शाता है।
- फिच ने कहा कि बीओबी का एक-डाउनग्रेड डाउनग्रेड एनपीएल और कमाई के मामले में विस्तारित वित्तीय कमजोरी से अपनी पूंजी स्थिति पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।

6. फिच ने घटाई एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की रेटिंग

- वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने जोखिम नियंत्राण व्यवस्था में खामियों के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक की रेटिंग घटाई है।
- एजेंसी ने जहां एक्सिस बैंक के मामले में परिदृश्य को स्थिर से नकारात्मक किया है जबकि आईसीआईसीआई बैंक की 'सपोर्ट रेटिंग ' को कम कर '2' से '3' कर दिया है।
- साथ ही ' सपोर्ट रेटिंग फ्लोर ' को ' बीबीबी माइनस ' से घटाकर ' बीबी प्लस ' कर दिया है। फिच ने कहा , 'दोनों बैंकों में जोखिम नियंत्रण को लेकर जोखिम दिखता है।

7. आरबीएल बैंक ने स्वधार फिनसर्व में अपनी हिस्सेदारी 100% बढ़ा दी

- निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक ने मुंबई स्थित वित्तीय उत्पाद वितरण फर्म स्वाधार फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड को पूरी तरह से अधिग्रहित किया है, जहां पहले 60.49 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
- स्वधार अब बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।
- स्वधार एक व्यापार पत्राचार है जो विशेष रूप से आरबीएल बैंक के लिए काम करता है।

8. IRDAI ने दी LIC-IDBI बैंक सौदे को मंजूरी दी

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
- सूत्रों ने बताया कि एलआईसी आईडीबीआई बैंक में 10 से 13 हजार करोड़ रुपए का निवेश किस्तों में करेगी।
- सूत्रों ने बताया कि बीमा कंपनी अगले 5 से 7 सालों में बैंक में अपनी हिस्सेदारी 15 प्रतिशत कर लेगा।
- वर्तमान में सरकार की आईडीबीआई बैंक में 80.96 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

9. डीबीएस बैंक अक्टूबर में भारत में सहायक कंपनी खोलेगा:

- सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इस साल अक्टूबर तक भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) के रूप में काम करने वाला पहला विदेशी ऋणदाता बनने की उम्मीद करता है।
- डीबीएस दो साल पहले नए ऑपरेटिंग डब्ल्यूओएस मॉडल के लिए आवेदन करने के लिए 2015 में पहला विदेशी ऋणदाता था, और पिछले साल सितंबर में इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी।
- सिंगापुर के सबसे बड़े ऋणदाता ने मार्च 2018 में 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है ताकि भारत में अपनी कुल पूंजी 5,000 करोड़ रुपये हो सके।

10. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया:

- देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
- अरुण जेटली ने सुब्रमण्यन के इस्तीफा की जानकारी देते हुए बताया कि वह पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अमेरिका जाना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा की इच्छा जताई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है.
- अरविंद सुब्रमण्यन को 16 अक्टूबर 2014 को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था. तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को एक साल और बढ़ाने का फैसला लिया था.

11. कर्नाटक बैंक ने 'केवल जमा कार्ड' लॉन्च किया

- कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने 'केबीएल-जमा केवल कार्ड' लॉन्च किया है जो बैंक की 24X7 ई-लॉबी सेवाओं पर परेशानी रहित नकदी जमा लेनदेन को सक्षम बनाता है।
- यह कार्ड विशेष रूप से बैंक के वर्तमान/ओवरड्राफ्ट ग्राहकों के लिए है। ये ग्राहक इस कार्ड का उपयोग कर बैंक के गुच्छा नोट स्वीकार्य (बीएनए) या नकद पुनर्चक्रण कियोस्क पर उच्च जमा सीमा के साथ भी नकदी जमा लेनदेन कर सकते हैं।
- एक दिन नकदी जमा की सीमा 10 लाख रुपये है।

12. विजया बैंक ने पीएफआरडीए पुरस्कार जीता

- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से वित्तीय क्षेत्र 2017-2018 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र विजया बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पुरस्कार मिला है।
- बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत अच्छा प्रदर्शन किया है।
- यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अटल पेंशन योजना सम्मेलन में दिया गया था।

13. यस बैंक ने राणा कपूर को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया

- निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने राणा कपूर को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में तीन साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया है।

14. भारत में एफडीआई 2017-18 में 61.96 अरब डॉलर तक बढ़ गया: सरकार

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2017-18 में 61.96 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
- पिछले वित्त वर्ष में एफडीआई प्रवाह 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस आंकड़े में इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेशित कमाई और अन्य पूंजी शामिल है।

15. सरिता नायर को WEF प्रबंधन बोर्ड में नियुक्त किया गया

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने कहा कि उसने सरिता नायर को अपने प्रबंध बोर्ड में नियुक्त किया है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एलएलसी के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) के रूप में उनकी भूमिका के अलावा, नायर चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क के लिए फोरम के केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का नेतृत्व करने में मदद करेंगे।

मई

1. **वित्त वर्ष 18 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 8.6% बढ़कर 1.13 लाख रुपये हो गई है**
    - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय 8.6 प्रतिशत की धीमी गति से 1,12,835 रुपये हो गई।
    - 2016-17 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,03,870 रुपये थी, जो मार्च 2016 को समाप्त हुए पिछले वित्त वर्ष (94,130 रुपये) से 10.3 प्रतिशत अधिक थी।
2. **भारत ने गुयांग, चीन में दूसरा आईटी कॉरिडोर लॉन्च किया**
    - **भारत** ने चीनी सॉफ्टवेयर बाजार में बढ़ोतरी के लिए **गुयांग, चीन में अपना दूसरा आईटी कॉरिडोर लॉन्च** किया है.
    - **नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियां** (**NASSCOM**) ने चीन में एक और **चीनी-भारतीय डिजिटल** कोल्लेबोरेटिव ऑप्पोरच्युनिटीज़ प्लाजा (**SIDCOP**) मंच स्थापित किया है.
    - पिछले दिसंबर में, NASSCOM ने चीन के बंदरगाह शहर डालियान में अपना पहला सिडकोप मंच स्थापित किया, जो चीन में भारत का पहला आईटी हब है।
3. टीसीएस 7 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है
    - टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) 7 लाख करोड़ रुपये बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) मील का पत्थर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई।
    - बाजार पूंजीकरण कंपनी का मूल्य है जो स्टॉक मार्केट पर कारोबार किया जाता है, जो वर्तमान शेयर मूल्य द्वारा शेयरों की कुल संख्या गुणा करके गणना की जाती है।
    - अब यह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है, इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और आईटीसी है।
4. **देना बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए**
    - केंद्र सरकार ने पंजाब एंड सिंध बैंक (चरण सिंह), देना बैंक (अंजलि बंसल) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (तपन रे) में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं।
5. **SBI ने को मार्च तिमाही में 7,718 करोड़ रुपए का हुआ घाटा: रिपोर्ट**
    - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने वित्त वर्ष की चौथी तिमाही18 में 7,718 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया।
    - दिसंबर तिमाही में, बैंक ने 17 वर्षों में अपनी पहली त्रैमासिक हानि की सूचना दी थी, शुद्ध घाटा 2,416 करोड़ रुपये था।
    - बैंक ने वित्त वर्ष की चौथी तिमाही17 में 2,814 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
6. **एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अनुब्रत बिश्वास को एम.डी और सी.ई.ओ के रूप में नियुक्त किया**
    - एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने 'अनुब्रत बिश्वास' को अपने प्रबंध निदेशक (एम.डी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ) के रूप में नियुक्त किया है
7. **चीन के बैंक ने देश का पहला भारत-समर्पित निवेश निधि लॉन्च किया**
    - चीन के एक शीर्ष राज्य संचालित चीनी बैंक, औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना ने

चीन का पहला भारत-समर्पित सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित निवेश निधि लॉन्च किया।

- बैंक ने कहाँ की यह चीनी निवेशकों के लिए सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है, क्योंकि 'भारतीय अर्थव्यवस्था "आर्थिक अधिग्रहण की स्वर्ण युग" में प्रवेश कर रही है।
- औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) क्रेडिट सुइस इंडिया मार्केट नामक फंड, "यूरोप और अमेरिका में 20 से अधिक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में निवेश करेगा जो भारतीय बाजार पर आधारित हैं"।
- यह फंड भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य में निवेश करेगा और भारतीय बाजार में औद्योगिक संरचना के वितरण को ट्रैक करेगा।

नोट:

- औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड (एबीबी आईसीबीसी) एक चीनी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी है।
- यह फरवरी 2017 के बाद से बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक है और कुल संपत्ति के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है।

8. बीएसई यूएस एसईसी मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय विनिमय है

- 16 मई 2018 को, बीएसई, संयुक्त राज्य अमेरिका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा 'नामित ऑफशोर सिक्योरिटीज मार्केट' (डीओएसएम) के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय विनिमय बन गया।
- डीओएसएम स्थिति यूएस एसईसी के साथ ऐसी प्रतिभूतियों के पंजीकरण के बिना बीएसई के व्यापार स्थल के माध्यम से अमेरिकी निवेशकों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अनुमति देती है, जो भारत में अमेरिकी निवेशकों के व्यापार को आसान बनाता है।
- यह मान्यता अमेरिकी निवेशकों के बीच भारतीय डिपोजिटरी रसीदों (आईडीआर) की आकर्षकता को भी बढ़ाएगी।
- बीएसई की नई स्थिति उन कंपनियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी जिनकी प्रतिभूतियां अमेरिका और बीएसई दोनों में कारोबार की जाती हैं।

9. PNB को मार्च क्वॉर्टर में सबसे बड़ा घाटा

- 15 मई 2018 को, पंजाब नेशनल बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-2018 की जनवरी-मार्च अवधि के लिए 13,417 करोड़ रुपये की हानि की सूचना दी, जो भारत के किसी भी बैंक द्वारा पोस्ट की गई सबसे बड़ी तिमाही हानि है।
- यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा तिमाही नुकसान है।
- पिछले साल की समान तिमाही में बैंक का लाभ 261.9 करोड़ रुपये था।

बेकार ऋण में वृद्धि

- बैंक को नेट परफॉर्मिंग असेट्स (NPAs) या फंसे कर्ज से बड़ी क्षति हुई है, जो इस साल मार्च अंत में बढ़कर 18.38 फीसदी हो गया। पिछले साल यह 12.53 फीसदी था।
- एनपीए पिछले साल की तुलना में 7.81 फीसदी से बढ़कर 11.24 फीसदी हो गया।
- इसके अलावा, एनपीए के लिए बैंक का प्रावधान क्यू 4 में 16,203 करोड़ रुपये था, जबकि क्यू 3 में 2,996 करोड़ रुपये था।

10. पेटीएम ने स्वचालित पुनरावर्ती भुगतान लागू किया

- 14 मई 2018 को, पेटीएम ने एक नई सुविधा यानी स्वचालित आवर्ती भुगतान पेश किया।
- यह नई सुविधा उपयोगकर्ताओं को आवधिक आवर्ती व्यय के लिए स्वचालित रूप से भुगतान

करने के लिए भुगतान ऐप को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देगी।

- बैंक खातों के लिए समान निर्देशों के लिए, 'माई पेमेंट्स' सुविधा का इस्तेमाल कई मामलों के लिए उच्च मूल्य भुगतान के लिए किया जा सकता है।

11. डीओटी भारती एयरटेल और टेलीनॉर इंडिया के विलय को मंजूरी दे दी है

- दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारती एयरटेल के साथ टेलीनॉर इंडिया के विलय को मंजूरी दी।
- गारंटी में नीलामी के बिना एयरटेल को आवंटित रेडियोवॉव के लिए एक बार स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए 1,49 9 करोड़ रुपये और टेलीनॉर को स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है।
- विलय 1800 मेगाहट्ज़ बैंड में 43.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त, सात दूरसंचार सर्किलों में एयरटेल के स्पेक्ट्रम पदचिह्न को बढ़ावा देगा।
- टेलीनॉर इंडिया आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी (पूर्व), यूपी (पश्चिम) और असम में सात सर्किलों में परिचालन चलाता है।

12. भारत ने अमेरिका को एल्यूमीनियम, इस्पात शुल्क मुद्दे पर WTO में घसीटा

- भारत ने अमेरिका को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान प्रणाली में एल्यूमीनियम और इस्पात पर आयात शुल्क लगाने के मुद्दे पर घसीटा है।
- भारत ने कहा है कि इन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले से उसका निर्यात प्रभावित होगा।
- भारत में स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों का भारत का निर्यात हर साल करीब 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- 2016-17 में अमेरिका के लिए भारत का निर्यात 42.21 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात 22.3 अरब अमेरिकी डॉलर था।

13. वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी खरीदेगा

- 9 मई 2018 को, वॉलमार्ट इंक ने घोषणा की कि वह भारत ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में लगभग 77% की प्रारंभिक हिस्सेदारी के लिए $ 16 बिलियन का भुगतान करेगी।
- यह दुनिया के सबसे बड़े उभरते बाजारों में से एक में प्रतिद्वंद्वी अमेज़ॅन से लड़ने के बाद अभी तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है।
- इस सौदे के साथ, फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक और अध्यक्ष सचिन बंसल कंपनी छोड़ देंगे और कंपनी में 5.5-6% हिस्सेदारी बेचेंगे।

14. आने वाले दशक में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी: हार्वर्ड

- हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले दशक में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी।
- चीन और अमेरिका से पहले, भारत सालाना 7.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
- रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक चीन की औसत विकास दर 4.9 फीसदी, अमेरिका की तीन फीसदी और फ्रांस की साढ़े तीन फीसदी रहेगी।

15. अप्रैल में जीएसटी 1 लाख करोड़ रुपये के संग्रह पार हो गया है

- अप्रैल में जीएसटी 1 लाख करोड़ रुपये संग्रह के पार हो गया है। आंकड़े अर्थव्यवस्था में वृद्धि और बेहतर अनुपालन को दर्शाते हैं।
- 2017-18 में सामान और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 7.41 लाख करोड़ रुपये था, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 89,264 करोड़ रुपये था।

16. सिंगापुर एशिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टॉक मार्केट है

- सिंगापुर स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स एशिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टॉक मार्केट है।

- इस साल के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में स्थानीय मुद्रा में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वियतनाम के वीएन इंडेक्स जो 2 प्रतिशत गिर गया था, उसको पीछे करके स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया ।

बैंकिंग और वित्तीय शब्द

1. **AEPS –** Aadhar Enabled Payment System
2. **APBS –** Aadhar Payment Bridge System
3. **ATM** – Automated Teller Machine
4. **ALM** - Asset Liability Management
5. **BBPS** – Bharat Bill Payment System
6. **BCA** -Baseline Credit Assessment
7. **BHIM** - Bharat Interface for Money
8. **BLRA:** Bank Led Resolution Approach
9. **CBS** – Core Banking System
10. **CIDR** - Central Identities Data Repository
11. **CTS –** Cheque Truncation System
12. **CDR** - Corporate Debt Restructuring
13. **CASA** – Current Account Saving Account
14. **CAD** – Capital Account Deficit
15. **CRA** - Counterparty Risk Assessment
16. **CRR** – Cash Reserve Ratio
17. **ECS** – Electronic Clearing Service
18. **DNS -** Domain Name System
19. **DEAF** - Depositor Education and Awareness Fund
20. **EFTPOS -** Electronic funds transfer at point of sale
21. **EFT** – Electronic Fund Transfer.
22. FRBM - Fiscal Responsibility and Budget Management
23. **LGD** - Loss Given Default
24. **LTV**- Loan To Value
25. **LRS** - Liberalized Remittance Scheme
26. **LCR** - Liquidity Coverage Ratio
27. **GNFV -** Gross Negative Fair Value
28. **SFTs**: Securities financing transactions
29. **HCE -** Host Card Emulation
30. **PFE** - Potential Future Exposure
31. ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process
32. **IFSC -** Indian Financial System Code
33. **IMPS** - Immediate Payment Service
34. **IMPS** - Interbank Mobile Payment Service
35. **MMID** - Mobile Money Identifier
36. **MPIN** - Mobile Personal Identification Number
37. **NPA** – Non- Performing Assets
38. **NSFR** - Net Stable Funding Ratio
39. **NPCI** - National Payment Corporation of India
40. **NFS** – National Financial Switch
41. **NSFR** - Net Stable Funding Ratio
42. **NACH** – National Automated Clearing House
43. **NEFT** – National Electronic Fund Transfer
44. **NFC** - Near field communication
45. **NDTL** – Net Demand and Time Liabilities.
46. **OTC** – Over the Counter
47. **PIN** – Personal Identification Number
48. **PAC** - Personal Access Code
49. **PCA** - Prompt Corrective Action
50. **PCR** – Public Credit Registry
51. **PCR** - Provisioning Coverage Ratio
52. **PSPs** - Payment Support Providers
53. **RTGS** – Real Time Gross Settlement
54. **USSD** - Unstructured Supplementary Services Data
55. **UIDAI** - Unique Identification Authority of India
56. **VPA** - Virtual Payment Address.
57. **GDR** – Global Depository Receipt
58. **GAAR** - General anti avoidance rule
59. **PAN** – Permanent Account Number
60. **PLR** – Prime Lending Rate
61. **SLR** – Statutory Liquidity Ratio
62. **SDR** – Special Drawing Rights
63. **DTAA** – Double Taxation Avoidance Agreement
64. **TIEA** – Tax Information Exchange Agreement
65. **EFSF** – European Financial Stability Facility
66. **PPP** – Purchasing Power Parity
67. **PPP** – Public Private Partnership
68. **NPS** – New Pension Scheme
69. **EEFC** - Exchange Earner's Foreign Currency
70. **FII** – Foreign Institutional Investor
71. **DII** – Domestic Institutional Investor
72. **GST** – Goods and Services Tax
73. **DTC** – Direct Tax Code
74. **FCNRA** – Foreign Currency Non- Resident account
75. **MFI** - Micro Finance Institutions
76. **MFDC** – Micro Finance Development Council
77. **TRAI** - Telecom Regulatory Authority of India
78. **MSF** – Marginal Standing Facility
79. **IDF** – Infrastructure Debt Fund
80. **CRIS** – Comparative Rating Index for Sovereign
81. **LIBOR** – London Inter Bank Operation Rate
82. **MIBOR** – Mumbai Inter Bank Operation Rate
83. **MICR** – Magnetic Ink Character Recognition
84. **SARFAESI** - Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest
85. **BCBS** - Basel Committee on Banking Supervision
86. **NPCI** - National Payments Corporation of India

समझौते और सौदे

अन्य देशों/ संस्था के साथ भारत के समझौते

दिसम्बर

1. **भारत, संयुक्त अरब अमीरात ने मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए**
    - भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए और डॉलर या अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग किए बिना प्रत्यक्ष व्यापार सक्षम किया।
    - भारतीय दूतावास के एक बयान में कहा गया है कि स्वैप 2 बिलियन दिरहम या 35 बिलियन भारतीय रुपये (4 9 6 मिलियन डॉलर) के लिए है, जो कि केंद्रीय बैंक राशि का अनुरोध करता है।
    - भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौते से यू.एस. डॉलर जैसी कठिन मुद्राओं पर निर्भरता को कम करने की उम्मीद है।
2. बहरीन और महाराष्ट्र सरकार ने फिनटेक पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
3. भारत ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग के लिए पेरू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए
4. रेल मंत्रालय ने मैडम तुसाद के वैक्स संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
5. मंत्रिमंडल ने पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी.
6. मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत तथा अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी.
7. मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग-समझौते को मंजूरी दी
8. मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा ताजीकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
9. मंत्रिमंडल ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त गतिविधियों पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
10. मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष की खोज तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच समझौता को स्वीकृति दी
11. मंत्रिमंडल ने भूगर्भ, खनन एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौते को मंजूरी दी
12. मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा मोरक्को के बीच समझौता को स्वीकृति दी
13. मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी तथा ऐप्लीकेशन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत तथा अल्जीरिया के बीच समझौता को स्वीकृति दी
14. मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य व आरोग्य के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग- ज्ञापन को मंजूरी दी.

नवम्बर

1. भारत, दक्षिण कोरिया ने खेल में सहयोग पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए
2. भारत और कोरिया गणराज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

3. आईआईएमसी इनोवेशन पार्क, आईसीसी ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए
    - आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क और इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ने पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
4. निर्यात के लिए स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं पर भारत और चीन ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए
5. भारत, मलावी ने प्रत्यर्पण संधि, परमाणु ऊर्जा और वीज़ा छूट में एमओयू पर हस्ताक्षर किए

ध्यान दें:
- मलावी राजधानी: लिलोन्ग्वे, मुद्रा: मलावीयन क्वचा

अक्टूबर

1. **पंजाब कृषि अनुसंधान, जल प्रबंधन के लिए इजरायल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए -** पंजाब सरकार ने किसानों के मुद्दों को हल करने और राज्य में भूजल स्तर को कम करने के लिए इजरायली संस्थानों के साथ चार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. **भारत, बांग्लादेश ने जलमार्ग कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए -** भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में चटोग्राम और मोंगा बंदरगाहों का इस्तेमाल माल आवाजाही के लिए, दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए ।
3. **भारत इजरायली मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए 777 मिलियन डॉलर का समझौते पर हस्ताक्षर किए -** इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आई.ए.आई.) ने भारतीय नौसेना में सात जहाजों को एल.आर.एस.ए.एम. वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त 777 मिलियन डॉलर का अनुबंध जीता है।
    - अनुबंध भारत के सरकारी स्वामित्व वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) के साथ है, जो परियोजना में मुख्य संविदाकार है।
4. **भारत, चीन ने सुरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए।**
5. भारत और क्रोएशिया ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और राजनयिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
6. भारत और श्रीलंका ने 1200 घरों के निर्माण के लिए दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए - भारत और श्रीलंका ने 50 करोड़ गांवों के माध्यम से 1200 घरों के निर्माण के लिए दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 60 करोड़ श्रीलंकाई रुपये की भारतीय अनुदान सहायता का उपयोग किया गया है।
7. **दिल्ली, मॉस्को ने दोहरा-शहरी समझौते पर हस्ताक्षर किए -** दिल्ली सरकार ने अगले 3 वर्षों तक पर्यावरण, संस्कृति और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए मॉस्को सरकार के साथ दोहरे शहर समझौते पर हस्ताक्षर किए।
8. **जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए -** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जम्मू में केंद्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय जम्मू (सी.यू.जे.) के साथ जम्मू में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सतीश धवन केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
9. **यूनिसेफ और नैसकॉम ने बाल अधिकारों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए-** यूनिसेफ और नैसकॉम फाउंडेशन ने "सार्थक व्यापार हस्तक्षेप" के माध्यम से बाल अधिकारों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
10. **अटल इनोवेशन मिशन और सिरीस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए -** भारत और रूस के छात्रों के बीच अभिनव

सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारत के अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और रूसी संघ के सिरीस एजुकेशनल फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

11. **भारत, रूस ने 5 बिलियन डॉलर की एस -400 मिसाइल एयर डिफेंस डील पर मुहर लगाई-** भारत और रूस ने हैदराबाद हाउस में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान 5 बिलियन डॉलर एस -400 वायु रक्षा प्रणाली सौदे पर हस्ताक्षर किए।
12. **भारत और कजाकिस्तान रक्षा एवं सैन्य-तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हैं -** भारत और कज़ाकिस्तान रक्षा सहयोग में सैन्य-तकनीकी सहयोग, सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, दौरे के द्विपक्षीय विनिमय और कैडेट युवा विनिमय कार्यक्रम शामिल हैं।
13. **जल और सीवेज प्रबंधन के लिए गोवा और पुर्तगाल के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर -** पुर्तगाली पर्यावरण मंत्रालय और गोवा लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह गोवा को अपने जल संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा।

सितंबर

1. **भारत और संयुक्त राष्ट्र ने पांच साल के सतत विकास ढांचे पर हस्ताक्षर किए –** नीति आयोग के सी.ई.ओ., अमिताभ कांत और भारत में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक, यूरी अफनासेव ने 2018-2022 के लिए भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढांचे (यू.एन.एस.डी.एफ.) पर हस्ताक्षर किए।
2. **भारत और मोरक्को ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।**
3. **बी.एस.एन.एल. ने सॉफ़्टबैंक के साथ सौदा किया, एन.टी.टी. को भारत में 5 जी रोल आउट करने के लिए -** दूरसंचार कंपनी बी.एस.एन.एल. ने भारत में 5जी और इंटरनेट सामग्री (आई.ओ.टी.) प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिए जापान के सॉफ्टबैंक और एन.टी.टी. संचार के साथ एक समझौता किया है।
4. **भारत और मोरक्को ने एयर सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए -** भारत और मोरक्को ने दोनों देशों के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो आधुनिक समझौते के माध्यम से अधिक कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है।
5. **भारत और फ्रांस, गगनयान मिशन के लिए सहयोग करेंगे**
    - भारत और फ्रांस ने इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 2022 में लॉन्च होने के लिए सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ध्यान दें:

- इस समझौते के तहत, इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस अंतरिक्ष यात्री जीवन समर्थन, विकिरण संरक्षण, अंतरिक्ष मलबे संरक्षण और व्यक्तिगत स्वच्छता प्रणालियों के क्षेत्रों में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिए कार्यकारी समूह का गठन करेगी।
- यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा।
- इसके तहत, भारत 2022 तक पांच से सात दिनों की अवधि के लिए अंतरिक्ष में तीन मनुष्यों (गैग्नैरेटिस) भेजने की योजना बना रहा है।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 72 वें स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान इस मिशन की घोषणा की थी।
- दुनिया में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष प्रकाश मिशन शुरू करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा।
- जी.एस.एल.वी एमके -3 लॉन्च वाहन, जिसमें आवश्यक पेलोड क्षमता है, का उपयोग गगनयान को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा।

6. **भारत और फ्रांस आपके शहर को मोबिलिज़ करेंगे:**

- भारत और फ्रांस ने शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी के लिए तीन पायलट शहरों - नागपुर, कोच्चि और अहमदाबाद का समर्थन करने के लिए अपने शहर (एमएसी) को मोबिलिज़ाई पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

7. भारत, चेक गणराज्य ने पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए

- भारत और चेक गणराज्य ने रक्षा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, लेजर प्रौद्योगिकी, कृषि और राजनयिक वीज़ा छूट पर पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

ध्यान दें:

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन यूरोपीय देशों - साइप्रस, बुल्गारिया और चेक गणराज्य के अपने राजकीय दौरे के अंतिम चरण में चेक गणराज्य का दौरा किया।
- चेक गणराज्य की राजधानी - प्राग
- चेक गणराज्य की मुद्रा - कोरुना
- बुल्गारिया की राजधानी - सोफिया
- बुल्गारिया की मुद्रा- लेव
- साइप्रस की राजधानी - निकोसिया
- साइप्रस की मुद्रा - यूरो

8. भारत, बुल्गारिया असैनिक परमाणु सहयोग, एसएंडटी, निवेश और पर्यटन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- भारत और बुल्गारिया ने सोफिया विश्वविद्यालय में नागरिक परमाणु सहयोग, निवेश, पर्यटन और हिंदी कुर्सी की स्थापना के क्षेत्र में चार एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
- दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग के कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए।

9. भारत और साइप्रस 2 एमओयू पर हस्ताक्षर किए

- भारत और साइप्रस ने पर्यावरण के क्षेत्र में मनी लॉन्डरिंग और सहयोग का मुकाबला करने पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

10. इंटरनेट सोसायटी, आईएसपीएआई भारत में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

- यूएस-आधारित गैर-लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी और इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ (आईएसपीएआई) ने स्वस्थ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण राउटर को सुरक्षित करके भारत में इंटरनेट सुरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

11. भारत और नेपाल (रक्सुअल-काठमांडू रेलवे लाइन के लिए)

- भारत और नेपाल ने बिहार, भारत में नेपाल की राजधानी काठमांडू से रक्सौल शहर को जोड़ने वाली रणनीतिक रेल लाइन बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अगस्त

1. भारत और यूरोपीय संघ – (क्षितिज 2020 के लिए)

- केंद्र सरकार और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दुनिया भर के नागरिकों की रक्षा के लिए नेक्स्ट जेनरेशन इन्फ्लुएंजा टीका विकसित करने के लिए होरिजन 2020 नामक शोध कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है।

2. तेलंगाना, टेक महिंद्रा स्याही एमओयू भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले के लिए -

- तेलंगाना राज्य सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग (आईटीई और सी) ने भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले को लॉन्च करने के लिए टेक महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकचैन कांग्रेस 2018 में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।

3. **जर्मनी यूरो 120 मिलियन सॉफ्ट लोन, स्वच्छ गंगा मिशन के लिए प्रदान करेगा-**
   - स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदी गंगा को साफ करने के प्रयास में उत्तराखंड में सीवेज जल उपचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जर्मनी ने 120 मिलियन यूरो (लगभग 909 करोड़ रुपये) के नरम ऋण प्रदान करने की घोषणा की है।
4. **डाक राजमार्ग परियोजना: भारत ने नेपाल को 470 मिलियन रुपये दिए -**
   - भारत ने अतिरिक्त 470 मिलियन रु (नेपाली) नेपाल के दक्षिणी मैदानों में निर्माण किया जा रहा डाक राजमार्ग परियोजना के चरण 1 के प्रदान किये हैं। जारी की गई राशि डाक राजमार्ग परियोजना के तहत 14 सड़क पैकेजों के चालू निर्माण के लिए फंड तरलता बनाए रखने में मदद करेगी।

जुलाई

1. भारत, रवांडा अंतर-संसदीय वार्ता को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं:
   - उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस तरह के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राज्यसभा अध्यक्ष बने, जब उन्होंने सीनेट के दौरे के रवांडा गणराज्य के राष्ट्रपति बर्नार्ड मकुजा के साथ समझौता ज्ञापन किया।
   - रवांडा की राजधानी किगाली है।
   - रवांडा की मुद्रा फ्रैंक है।
2. भारत और दक्षिण कोरिया ने नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पांच एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. माइक्रोसॉफ्ट ने राजस्थान सरकार के साथ एक वर्ष में 9,500 कॉलेज छात्रों को मुफ्त डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
4. भारत और नेपाल संयुक्त रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए: भारत और नेपाल बौद्ध और रामायण सर्किट और साहसिक पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने पर सहमत हुए।

जून

1. भारत और चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के आंकड़ों को साझा करने और गैर-बासमती चावल की आपूर्ति से संबंधित दो ज्ञापन समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. भारत ने सिंगापुर के साथ नर्सिंग में म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहला एमआरए भारत द्वारा हमारे किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भागीदारों के साथ हस्ताक्षरित किया जा रहा है।
3. भारत ने बायोटेक्नोलॉजी और पारंपरिक दवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए क्यूबा के साथ समझौते के दो ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
4. भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेशल्स को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट घोषित किया है।
5. भारत और ताजिकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और विशेष रूप से टिकाऊ जल विकास में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है।
6. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष तकनीकी संगठन ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए Google के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय संस्थानों के साथ भारत के समझौते

दिसम्बर

1. **भारत और एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के लिए $ 31 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए**
    - राज्य पर्यटन उद्योग के निर्माण और तमिलनाडु में आगंतुकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
2. **एडीबी, केंद्र ने ओडिशा में कौशल विकास परियोजना का समर्थन करने के लिए $ 85 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर करें**
    - ओडिशा में कौशल विकास पर्यावरण प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 85 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।
    - एक उन्नत कौशल प्रशिक्षण केंद्र, विश्व कौशल केंद्र (डब्ल्यूएससी) भी भुवनेश्वर में ऋण की मदद से स्थापित किया जाएगा।

नवम्बर

1. विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के साथ $ 172 मिलियन परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए
2. सीसीईए भारत के ड्रेजिंग निगम में 100% सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है
    - आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकार की इक्विटी के 100% सामरिक विनिवेश को मंजूरी दी।
    - वर्तमान में, भारत सरकार के ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 73.44% शेयर हैं।
3. **भारत और एडीबी ने हिमाचल प्रदेश के लिए $105 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए**
    - भारत और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने जलविद्युत की आपूर्ति में वृद्धि के लिए हिमाचल प्रदेश में ट्रांसमिशन सिस्टम उन्नयन को वित्त पोषित करने के लिए 105 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
4. भारत और विश्व बैंक ने झारखंड के लिए $ 310 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
    - भारत सरकार, झारखंड सरकार और विश्व बैंक ने झारखंड के नागरिकों को विश्वसनीय, गुणवत्ता और सस्ती 24 × 7 बिजली प्रदान करने के लिए झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए 310 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
5. **बिहार में राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए केंद्र, एडीबी ने 200 मिलियन डॉलर का ऋण** समझौते पर हस्ताक्षर किये
    - केंद्र और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बिहार में 230 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को सड़क सुरक्षा सुविधाओं के साथ सभी मौसम मानकों के विस्तार और उन्नयन के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अक्टूबर

1. **भारत ने लौह एवं इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए-** 20 प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, पूंजीगत वस्तुओं के निर्माताओं और इस्पात उत्पादकों के बीच 5 बिलियन डॉलर के आठ अथाय पर हस्ताक्षर किए गए, जो लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देंगे ।
2. **भारत और ए.डी.बी. ने मध्यप्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 110 मिलियन डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किए** - भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने मध्य प्रदेश राज्य में 2,800 किलोमीटर की सभी मौसम ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को वित्तपोषित करने के लिए प्रधान मंत्री के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत 110 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए ।
3. **भारत और ए.डी.बी. ने भारत के पहले वैश्विक कौशल पार्क का समर्थन करने के लिए 150 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए -** एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में वैश्विक कौशल पार्क (जी.एस.पी.), भारत का पहला बहु-कौशल पार्क, स्थापित करने के लिए नई दिल्ली में 150 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
4. **भारत और ए.डी.बी. ने पश्चिम बंगाल के लिए सुरक्षित पेयजल सेवा के लिए 240 मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किए -** भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने आर्सेनिक, फ्लोराइड और लवणता से प्रभावित पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में लगभग 1.65 मिलियन लोगों को सुरक्षित और टिकाऊ पेयजल प्रदान करने के लिए 240 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

सितंबर

1. **भारत ने यू.के.डब्ल्यू.डी.पी. के लिए विश्व बैंक के साथ वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए -** उत्तराखंड कार्यबल विकास परियोजना (यू.के.डब्ल्यू.डी.पी.) के लिए 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर आई.बी.आर.डी. क्रेडिट के लिए ऋण समझौते पर भारत और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
2. **भारत, श्रीलंका ने 5000-मीट्रिक टन तापमान नियंत्रित वेयरहाउस के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए -** भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के डंबुला में 5000 मीट्रिक टन तापमान नियंत्रित गोदाम के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
3. **दिल्ली, सियोल वायु प्रदूषण को संभालने के लिए समझौता ज्ञापन -** दिल्ली सरकार ने सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार के साथ पर्यावरण, पर्यटन, अपशिष्ट जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बारीकी से काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
4. **एक्ज़िम बैंक और ब्रिक्स बैंक (ब्लॉकचैन अनुसंधान के लिए) -**
    - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में वितरित लेजर और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर सहयोगी अनुसंधान पर ब्रिक्स इंटरबैंक सहयोग तंत्र के तहत निर्यात-आयात बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) और सदस्य बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन समझौते को मंजूरी दे दी है।

अगस्त

1. **एडीबी और मध्य प्रदेश - सिंचाई के लिए ($ 375 मिलियन)**
    - केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ $ 375 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. **एडीबी और पश्चिम बंगाल - सुरक्षित पेयजल के लिए ($ 245 मिलियन)**
    - एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आर्सेनिक, फ्लोराइड और लवणता से प्रभावित पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में लाखों लोगों को सुरक्षित, टिकाऊ पेयजल सेवा प्रदान करने के लिए परियोजना को लागू करने के लिए 245 मिलियन डॉलर के वित्तपोषण पैकेज को मंजूरी दे दी है।
3. **भारत और विश्व बैंक - ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए ($ 300 मिलियन)**
    - केंद्र सरकार (वित्त मंत्रालय) ने इनाडा के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ 220 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते को शामिल किया है। इसने विश्व बैंक के साथ $ 80 मिलियन गारंटी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।
4. **भारत और विश्व बैंक - राजस्थान राज्य बिजली के लिए ($ 250 मिलियन)**
    - राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार ने राजस्थान में बिजली वितरण क्षेत्र सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $ 250 मिलियन विकास नीति ऋण (डीपीएल) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
5. **भारत और एडीबी - कर्नाटक राज्य राजमार्गों के लिए ($ 346 मिलियन)**
    - कर्नाटक में 400 किलोमीटर से अधिक राज्य राजमार्गों के सुधार के लिए भारत ने कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार III परियोजना (केएसएचआईपी -3) को वित्त पोषित करने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 346 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते की कमाई की है।

जुलाई

1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बिहार के शाहबाद-भोजपुर क्षेत्र में सोन नहर की 503 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अस्तर परियोजना को मंजूरी दे दी है जो इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को अत्यधिक लाभ पहुंचाएगी।

जून

1. **ए.आई.आई.बी. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एन.आई.आई.एफ. में 200 मिलियन डॉलर निवेश करेगी**
    - एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (ए.आई.आई.बी.) ने मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एन.आई.आई.एफ.) में 200 मिलियन डॉलर के निवेश को मंजूरी दे दी है।

एन.आई.आई.एफ.

- देश के बुनियादी ढांचे क्षेत्र में वित्त पोषण अर्जित करने के लिए दिसंबर 2015 में राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष स्थापित किया गया था।
- इसे श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत किया गया है।
- इसे बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपने निवेशकों के लिए जोखिम समायोजित लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से निधि संरचना के एक कोष के रूप में स्थापित किया गया है।

मई

1. **भारत ने राजस्थान परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए**
    - भारत और विश्व बैंक ने राजस्थान परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए 21.7 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2. **भारत, विश्व बैंक ग्रामीण सड़कों के लिए $ 500 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर** किए
    - प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान करने के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ 500 मिलियन अमरीकी डालर (3,371 करोड़ रुपये) ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
3. **नाबार्ड ने अरुणाचल में सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम को अधिकृत किया**
    - नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने अरुणाचल प्रदेश के लिए अपने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 87.83 लाख रुपये के कुल अनुदान के साथ एलईडी सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम को अधिकृत किया।
4. **भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए**
    - भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोशन अभियान) के लिए विश्व बैंक के साथ $ 200 मिलियन के ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किए।
    - यह ऋण 0-6 साल के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत को कम करके 25 प्रतिशत करने में सहायता प्रदान करेगी.
    - यह अभियान पहले चरण में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में चलाया जाएगा.

    नोट:
    - प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को झुंझुनू, राजस्थान में पोषण अभियान को लांच किया था.
    - पोशन अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है।
5. **विश्व बैंक ने ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए $ 300 मिलियन का क्रेडिट दिया**
    - विश्व बैंक बोर्ड ऑफ एक्जीक्यूटिव डायरेक्टरों ने भारत ऊर्जा दक्षता स्केल-अप कार्यक्रम के लिए 300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट गारंटी को मंजूरी दी।
    - कार्यक्रम का उद्देश्य निजी क्षेत्र ऊर्जा सेवा कंपनियों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि करना है।
    - कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा लागू किया जाएगा।

महत्वपूर्ण समितियां

दिसम्बर/ नवम्बर

1. **राजीव कुमार (नीति आयोग उपाध्यक्ष) समिति** - निजी और विदेशी कंपनियों को राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के 14 9 छोटे और सीमांत तेल और गैस क्षेत्रों की बिक्री को देखने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए।
2. **नाम्रिता महिंद्रो समिति** - देश में आर्थिक विकास, नौकरी निर्माण और कौशल विकास को चलाने के लिए बढ़ी हुई

और आभासी वास्तविकता (एआर / वीआर) प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए।

नोट:

- समिति का गठन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) द्वारा किया जाता है।
- आईएएमएआई मुख्यालय मुंबई में है।

3. **न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी रोहिणी समिति** - अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की जांच करने के लिए।

ध्यान दें:

- राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया था।
- इस समिति का नेतृत्व दिल्ली उच्च न्यायालय के के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी रोहिणी को दिया गया।
- इसकी रिपोर्ट से ओबीसी के भीतर अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित उप-कोटा की सिफारिश करने की उम्मीद है।

4. **राजनाथ सिंह (केंद्रीय गृह मंत्री) समिति -** देश और विदेश में गुरु नानक की 550 वीं जयंती मनाने के लिए।
5. **सतत विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति**
   - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संबंधित लक्ष्यों के साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) की समय-समय पर समीक्षा और परिष्करण के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति के गठन को मंजूरी दे दी है।
   - उच्चस्तरीय संचालन समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की होगी।

अक्टूबर

1. **इंजेती श्रीनिवास समिति** - संघ सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की समीक्षा के लिए एक प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति गठित की।

सितम्बर / अगस्त

1. **सुशील मोदी पैनल** - सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के मामले में राजस्व आंदोलन के लिए तरीकों की जांच करने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय मंत्रिस्तरीय पैनल का गठन किया।
2. **न्यायमूर्ति अमितव राय समिति** - सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जेलों की समस्याओं को देखने और सुधार उपायों का सुझाव देने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की।
3. **न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति** - केंद्र सरकार ने लोकपाल के नामों की सिफारिश करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में लोकपाल खोज समिति गठित की।
4. **के विजय राघवन (केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार)** - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों से संबंधित मामलों पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने के लिए।

5. **भास्कर राममुर्ती (आईआईटी-मद्रास निदेशक) समिति** - इस साल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की अपर्याप्त संख्या के चलते जेईई (उन्नत) में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए।
6. **बिमल जालान (पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर) पैनल** - भारत के अगले मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) का चयन करने के लिए।
7. **अमिताभ कांत (सीईओ - एनआईटीआई अयोध) समिति** - देश में तेजी से बढ़ रहे ई-कॉमर्स उद्योग से संबंधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानदंडों सहित सभी मुद्दों को देखने के लिए।
8. **पी जे जोसेफ समिति** - मोटर थर्ड पार्टी बीमा मूल्य निर्धारण पहलुओं की जांच करने के लिए।
9. **प्रदीप कुमार सिन्हा (कैबिनेट सचिव) समिति** - तनावग्रस्त थर्मल पावर प्रोजेक्ट के मुद्दों को हल करने के लिए।
10. **राजीव गौबा (गृह सचिव) समिति** - देश में भीड़ हिंसा और झुकाव की घटनाओं के प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों और कानूनी ढांचे का सुझाव देने के लिए।
11. **अनिल स्वरुप (शिक्षा सचिव) समिति** - राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देने के लिए।
12. **इंजेती श्रीनिवास (कॉर्पोरेट मामलों के सचिव) समिति** - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा करने के लिए।

जुलाई/जून

1. **सुशील कुमार मोदी पैनल** - माल और सेवा कर परिषद द्वारा गठित एक मंत्री पैनल ने सिफारिश की है कि राजस्व विचारों का हवाला देते हुए एक वर्ष के लिए डिजिटल लेनदेन के लिए कोई अतिरिक्त कर प्रोत्साहन नहीं होगा।
2. **रविंद्र ढोलकिया समिति:** राष्ट्रीय खातों या सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्यों और जिलों के स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करना।
3. **न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण:** आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए
    - सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण कॉर्पोरेट प्रबंध निदेशक और सीईओ, चंदा कोचर के खिलाफ कॉर्पोरेट दुर्व्यवहार और प्रश्नोत्तरी के आरोपों पर आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड द्वारा शुरू की गई जांच का नेतृत्व करेंगे।
4. **सुरेश माथुर समिति** - बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा विपणन फर्मों से संबंधित नियमों की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है।
5. **जयंत सिन्हा समिति** - मानव रहित विमान (यू.ए.वी) प्रौद्योगिकी के शीघ्र कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए इस समिति का गठन किया है.
6. **सुभाष चंद्र गर्ग समिति** - वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया है.
7. **वाई एच मालेगाम समिति** - भारतीय रिजर्व बैंक ने खराब ऋणों के वर्गीकरण, धोखाधड़ियों की बढ़ती घटनाओं और लेखापरीक्षाओं की प्रभावशीलता से संबंधित मुद्दों के पूरे पहलुओं की जांच के लिए इस समिति का गठन किया है.
8. **विनय शैल ओबेरॉय समिति** - सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं की निगरानी और शीघ्रता के लिए।

9. **एन चंद्रशेखरन (टाटा सन्स के अध्यक्ष) समिति** - सेना में कृत्रिम बुद्धि (एआई) के उपयोग और आवेदन का अध्ययन करने के लिए।
10. **दिनेश शर्मा समिति** - क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए
11. **अमिताभ कांत समिति** - भारत के बिजली क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की समस्या को हल करने के लिए।
12. **वाई एम देवस्थले समिति** -- लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) पर टास्क फोर्स समिति जो भारत में क्रेडिट की मौजूदा उपलब्धता की समीक्षा करेगी।
13. **बी सी खंडूरी समिति** - रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति यह समिति सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की जांच करेगी और रणनीतिक रक्षा संपत्ति से जुड़े दुर्घटनाओं की समीक्षा करेगी और रक्षा उपकरणों से संबंधित खरीद नीति का आकलन करेगी।
14. **अरुण जेटली समिति -** संघ सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली बैंकों के विलय प्रस्तावों की देखरेख के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली एक मंत्रीय समिति का गठन किया है।
15. **डॉ हसमुख अधिया समिति** - केंद्र सरकार ने डॉ। हसमुख अधिया की अध्यक्षता में जीएसटी कमेटी का गठन किया है।
16. **डॉ वी. कमकोती समिति** - केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर टास्क फोर्स का गठन किया। आईआईटी मद्रास के डॉ वी। कामकोती की अध्यक्षता वाली 18 सदस्यीय पैनल।
17. **के. कस्तुरीरंगन समिति** - राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए।

gradeup

x x x x x x

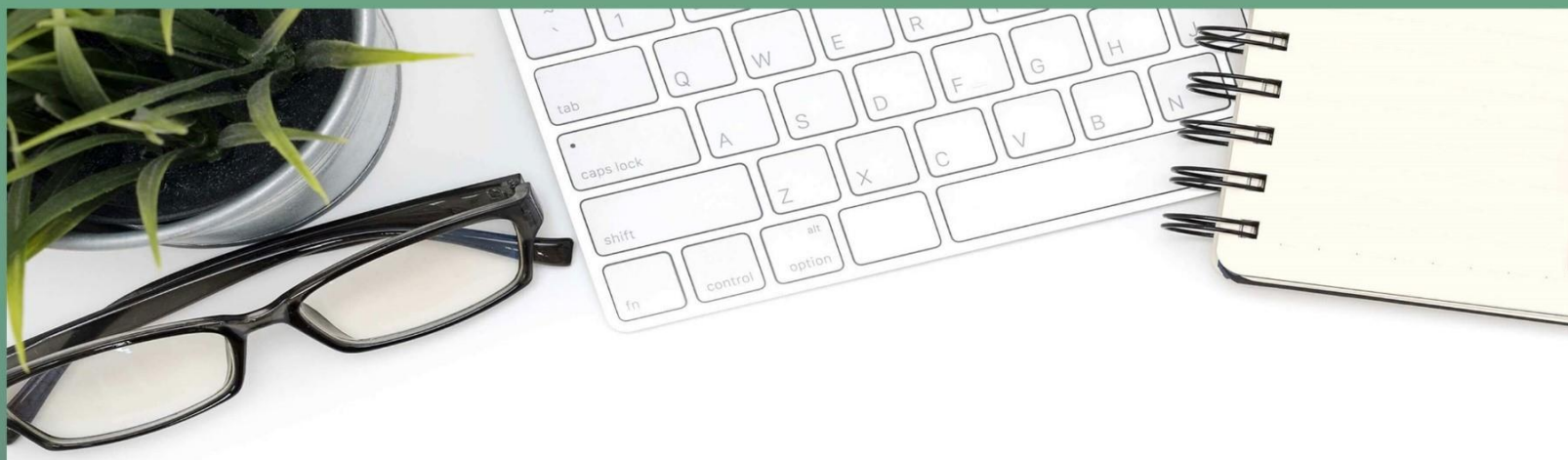

बैंकिंग, एसएससी, गेट, सीटीईटी, जेईई एवं अन्य प्रवेश परीक्षाएं

- नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित
- हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है
- अखिल भारतीय रैंक और परिणाम विश्लेषण प्राप्त करें
- विस्तृत समाधान

ANDROID APP ON Google play